चतुर्थ माला, खंड 14, अंक 21 मंगलवार, 12 मार्च, 1968/22 फाल्गुन, 1889 (शाक)

Fourth Series, Vol. XIV, No. 21 Tuesday, March 12, 1968/Phalguna 22, 1889 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th

LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 16.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 14 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XIV contains Nos. 21—30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee.

यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 21—मंगलवार, 12 मार्च, 1968/22 फाल्गुन, 1889 (शक)

No. 21--Tuesday, March 12, 1968/22 Phalguna ...

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या
*S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
570.	रेलवे में घाटे के कारण छंटनी	Retrenchment due to deficit on Railways	1—5
573.	सीमेन्ट आवंटन तथा समन्वय संगठन	Cement Allocation and Co-ordinating Organisation	6—14
574.	रेलवे के वेज तथा वर्क्स निरीक्षक तथा सहायक निरीक्षक	Assistant Inspectors and Inspectors of Ways and Works .	14-15
575.	रेलवे पर दिये जाने वाले भोजन के स्तर का घटिया होता जाना	Deterioration in quality of Food served on Railways	15-16

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या

Short Notice Q. No.

7.	पेंसिलीन के टीके के कारण एक लड़की की मृत्यु	Death of a girl due to Pencillin Injection	17—20

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तारांकित प्रश्न संख्या

S. Q. Nos.

569.	उड़ीसा की औद्योगिक नीति	Industrial Policy of Orissa	20-21
571.	कालीकट में भारतीय जनसंघ के वार्षिक अधिवेशन के लिये विशेष गाड़ी का चलाया जाना	Running of Special Train for Annual Session of Bhartiya Jana Sangh at Calicut	21
572.	पटसन के सामान पर निर्यात शुल्क	Export duty on Jute Goods . . .	21

*किसी नाम पर अंकित यह+चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
576.	मुगलसराय स्टेशन से माल की चोरी	Pilferage of Goods from Mughal Sarai Station	21-22
577.	री-रोलिंग मिलें	Re-Rolling Mills . . .	22-23
578.	रेलवे में स्वचालित मशीनों का प्रयोग	Automation on Railways . .	23
579.	ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors . .	23-24
580.	उड़ीसा में एक पटसन मिल का स्थापित किया जाना	Setting up a Jute Mill in Orissa	24
581.	हरिद्वार में हैवी इलैक्ट्रिकल प्लांट	Heavy Electrical Plant at Hardwar .	25
582.	मोटर गाड़ियों के पुर्जों का निर्माण	Manufacture of Motor Parts . .	25
583.	मैसर्स भारत बैरल कम्पनी	M/s. Bharat Barrel Company . .	25-26
584.	फ्रांस द्वारा मूंगफली तथा मूंगफली के तेल का आयात	Import of Groundnut and Groundnut Oil by France	26
585.	व्यापारिक मोटर गाड़ियों का निर्माण	Production of Commercial Vehicles . .	26-27
586.	ऊन के आयात के लिये नियतन	Allocation for Import of wool .	27
587.	सरकारी क्षेत्र के तीन इस्पात कारखानों में लगी पूंजी	Investiment in Three Public Sector Steel Plants	27-28
588.	मध्य प्रदेश में छोटी कार परियोजना तथा अन्य औद्योगिक योजनाएं	Small Car Project and other industrial Schemes in Madhya Pradesh . .	28-29
589.	दक्षिण पूर्व रेलवे में रेलवे सेवा आयोग	Railway Service Commission on S. E. Railway	29
590.	घाटे पर चलने वाली कपड़ा मिलें	Sick Textile Mills . .	29-30
591.	कच्चे लोहे का उत्पादन	Pig Iron Production. . .	30
592.	दूसरे संयुक्त राष्ट्र संघ व्यापार तथा विकास सम्मेलन में अनुवादक	Translators at UNCTAD II	30
593.	लघु उद्योग क्षेत्र	Small Scale Industrial Sector . . .	31

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
594.	थाईलैण्ड से पटसन का आयात	Import of Jute from Thailand . .	31
595.	मद्रास प्रदर्शनी	Madras Exhibition	31-32
596.	बीकानेर और दिल्ली के बीच रेलवे लाइन में दरार	Cracks in Railway line between Bikaner and Delhi	32-33
597.	स्कूटरों, मोटर साइकिलों तथा मौपेडों के निर्माण के लिये नये लाइसेंस	New Licences for Manufacture of Scooters, Motor-Cycles and Mopeds . .	33
598.	कीनिया में औद्योगिक कारखाने	Industrial Units in Kenya	33-34

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. Q. Nos.

3637.	टीनबन्द खाद्य पदार्थों तथा आचार का निर्यात	Export of Canned Food and Pickle	34
3638.	कपास का आयात	Import of Cotton . . .	34
3640.	खादी उद्योग	Khadi Industry . . .	35
3641.	त्रिवेन्द्रम में बुनकर सेवा केन्द्र	Weavers Service Centre at Trivandrum	35
3642.	केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन	Central Small Scale Industries Organisation	35-36
3643.	कमर्शियल क्लर्क	Commercial Clerks	36
3644.	मोटर कारों के निर्माण के लिये लोहे का अयात	Import of Iron for Manufacture of Motor Cars	36-37
3645.	रुमानिया से व्यापार करार	Trade Agreement with Rumania .	37
3646.	बिड़लाओं के बैंक	Banks owned by Birlas . . .	37
3647.	दिल्ली में दस्तकारी केन्द्र	Handicraft House in Delhi . .	38
3648.	दस्तकारी के उद्योगों के लिये भूमि	Land for Handicraft Industries	38
3649.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	Hindustan Steel Ltd.	38
3650.	छोटी कार परियोजना	Small Car Project	39

अता० प्र० संख्या	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
U. Q. Nos.			
3651.	मद्रास से रामेश्वरम तक रेलवे लाइन	Madras-Rameshwaram Railway Line	39
3652.	हिमाचल प्रदेश में स्थापित किये गये उद्योग	Industries set up in Himachal Pradesh	40
3653.	खादी ग्रामोद्योग आयोग में अंशदायी भविष्य निधि	Contributory Provident Fund in Khadi and Village Industries Commission . .	40
3654.	खादी ग्रामोद्योग भवन के कर्मचारियों में मंहगाई भत्ते की अदायगी	Payment of D. A. to Khadi Gramodyog Bhawan Employees . . .	40
3655.	खादी तथा ग्रामोद्योग भवन में वेतनक्रम	Pay Scales in Khadi and Gramodyog Bhawans	40-41
3656.	खादी ग्रामोद्योग भवन के कर्मचारियों को बोनस	Bonus to employees of Khadi Gramodyog Bhawan]	41
3657.	राजस्थान के करौली क्षेत्र में सीमेंट के पत्थर के भंडार	Deposits of Cement Stone in Karauli area in Rajasthan	41
3658.	कोटा डिवीजन के रेलवे कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Railway Employees of Kotah Division	41
3659.	गोशिन नामक जहाज का हटाया जाना	Clearance of Ship Goshen	41-42
3660.	चावल का आयात	Import of Rice . .	42
3661.	बड़गांव (मध्य रेलवे) के निकट बम मिलना	Recovery of Bomb near Baragon (Central Railway)	42
3662.	आय व्ययक पेश किये जाने से पूर्व की जाने वाली चोर बाजारी को रोकना	Prevention of Pre-Budget black-marketing	42-43
3663.	कोयले का निर्यात	Export of Coal .	43
3664.	सिमको लिमिटेड भरतपुर का रूसी प्रतिनिधि मंडल द्वारा दौरा	Visit by a Soviet Delegation to CIMMCO LTD., Bharatpur	43
3665.	उत्तर रेलवे, दिल्ली का डिविजनल लेखा कार्यालय	Divisional Accounts Office N. Rly. .	43-44
3666.	ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors .	44

अता० प्र० संख्या	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
U. Q. Nos.			
3667.	नेपा नगर में वृक्ष लगाया जाना	Plantation of trees in NEPA Nagar .	44-45
3668.	महाराष्ट्र में औद्योगिक उत्पादन में हानि	Loss in Industrial Production in Maharashtra	45
3669.	कम्पनी सेक्रेटरीशिप	Company Secretaryship	45-46
3670.	महाराष्ट्र में उद्योग	Industries in Maharashtra .	46
3671.	दक्षिण पूर्व रेलवे में निराकारपुर पर एक्सप्रेस गाड़ियों का रुकना	Stoppage of Express trains at Nirakarpur on South Eastern Railway . .	46
3672.	खुरदा डिवीजन में रेलवे के कर्मचारियों और उनके बच्चों के लिए शिक्षा सुविधायें	Educational facilities for Railway staff and their children in Khurda Division . .	47
3673.	महालक्ष्मी कपड़ा मिल्स लिमिटेड भावनगर	Mahalaxmi Textile Mills Ltd., Bhavnagar	47-48
3674.	महालक्ष्मी कपड़ा मिल, भावनगर	Mahalaxmi Textile Mills, Bhavnagar . .	48
3675.	रेलवे में स्थायी मार्ग निरीक्षक	Permanent Way Inspectors on the Railways	48-49
3676.	जोधपुर डिवीजन के कर्मचारियों को उच्चतर ग्रेड दिया जाना	Higher Grade to Staff of Jodhpur Division	49
3677.	लोहा और इस्पात नियंत्रक का कार्यालय	Iron and Steel Controller's Office .	49-50
3678.	फ्रन्टियर मेल में प्रथम श्रेणी में आरक्षण कोटा	Quota of Reservation in Ist Class in Frontier Mail	50
3679.	रूस के सहयोग से ट्रैक्टर का कारखाना	Tractor Factory with Russian Collaboration	50
3680.	अन्देरी नदी (पश्चिम रेलवे) पर पुल पर दुर्घटना	Incident on Railway Bridge over Anderi River (W. Rly.)	50
3681.	सीमेंट का वितरण	Distribution of Cement . . . ,	50-51

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3682.	बून्दी जिले में सीमेंट का कारखाना	Cement Factory in Bundi District . .	51
3683.	रेलवे गार्ड	Railway Guards	51
3684.	चमड़े पर निर्यात शुल्क	Export Duty on Leather . .	51–52
3685.	हरिजनों द्वारा चलाये जाने वाले उद्योग	Industries Run by Harijans . . .	52
3686.	सीमेंट संयंत्रों का निर्यात	Export of Cement Plants. . . .	52
3687.	केरल में नारियल जटा उद्योग का विकास	Development of Coir Industry in Kerala	52–53
3688.	कटनी से मिर्जापुर तक रेलवे लाइन पर व्यय	Expenditure on Railway Line from Katni to Mirzapur	53
3689.	विदेशी समवाय	Foreign Companies	53
3690.	डनलप कम्पनी	Dunlop Company	53–54
3691.	सोयाबीन खाद्य तेल, नाइलोन तथा स्टेनलैस स्टील का आयात	Import of Soyabean Edible Oil, Nylon and Stainless Steel	54
3692.	चतुर्थ श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of Class IV Railway Employees	54–55
3693.	वाणिज्यिक संस्थापनाओं को लाइसेंस जारी करना	Issue of licences to Commercial Establishments	55
3694.	पूर्वोत्तर रेलवे पर वातानुकूलित डिब्बों के इंचार्ज अटेण्डैण्टस	A. C. Coach Incharge/Attendents on N. E. Railway	55
3695.	माल डिब्बों का निर्यात	Export of Wagons	56
3696.	दुर्गापुर इस्पात कारखाना	Durgapur Steel Plant	57
3697.	पटसन की बनी वस्तुओं के निर्यात मूल्य	Export prices of Jute Goods . . .	56
3698.	रेलवे के यातायात प्रशिक्षार्थी	Traffic Apprentices of Northern Railway	57
3699.	गुजरात में छोटी लाइनों का बन्द किया जाना	Closing of Narrow Gauge Lines in Gujarat	57
3700.	भावनगर में कच्चे लोहे तथा मशीनी औजार कारखाने की स्थापना	Location of Pig Iron and Machine Tool Factories at Bhavnagar.	58

अता० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3701.	भारत का विदेशी व्यापार	India's Foreign Trade	58
3702.	दिल्ली हावड़ा सैक्शन पर तीव्र गति से चलने वाली गाड़ी	Introduction of High Speed Train on Delhi Howrah Line	58–59
3703.	विभिन्न उद्योगों में मन्दी	Stamp in various Industries	59
3704.	बेरोजगार छोटे व्यापारियों के लिये रोजगार	Jobs for Unemployed Small Traders	59–60
3705.	राजस्थान में औद्योगिक विकास	Industrial Development in Rajasthan	60
3706.	राजस्थान में बड़ी लाइन	Broad Gauge line in Rajasthan.	60
3707.	ठक्कर समिति	Thacker Committee.	61
3708.	लघु उद्योग कारपोरेशन	Small Scale Industries corporation	61
3709.	तकनीकी विकास महानिदेशालय	Directorate General, Technical Development	61
3710.	बबी कारों का निर्माण	Manufacture of Baby Car	62
3711.	महेश्वरी देवी पटसन मिल, कानपुर	Maheshwari Devi Jute Mills, Kanpur	62
3712.	टसर रेशम का निर्यात	Export of Tasor Silk	62–63
3713.	रेयन और सिन्थेटिक टैक्सटाइल का निर्यात	Export of Rayon and Synthetic Textiles	63–64
3714.	लोहे और इस्पात का निर्यात	Export of Iron and Steel	64
3715.	पंजाब में ढलाई का कारखाना	Foundry in Punjab.	65
3717.	पिसी हुई हड्डियों का निर्यात	Export of Crushed Bones	65
3718.	राक फास्फेट	Rock Phosphate.	65–66
3719.	दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) के कमर्शियल इन्सपेक्टर	Commercial Inspectors of Delhi Division (N. Railway)	66
3720.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	National Coal Development Corporation	66
3721.	अन्तर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भारत द्वारा भाग लना	India's Participation in International Fairs and Exhibitions	66–67

अता० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3722.	तेनालि रेपल्लि और बर्दवान कठवा रेलवे लाइनें	Tenali Repalli and Burdwan Katwa Railway Lines	67
3723.	रेलवे कमर्शियल क्लर्क	Railway Commercial Clerks . . .	68
3724.	भारतीय रेलों में कमर्शियल क्लर्कों के पास यातायात देनदारी	Traffice Debits against Commercial Clerks on Indian Railways	68
3725.	रेलों में कमर्शियल क्लर्क वर्ग के लिये छुट्टी रिजर्व कर्मचारी	Leave Reserve Staff for Commercial Clerks in Railways	68-69
3726.	रेलवे में कमर्शियल क्लर्क	Commercial Clerks on Railways .	69
3727.	खादी के माल का निर्यात	Export on Khadi Goods . .	69
3728.	धातु मिश्रित इस्पात का उत्पादन	Production of Alloy Steel . .	69-70
3729.	धातु मिश्रित इस्पात का उत्पादन	Production of Alloy Steel .	70
3730.	सिगरेटों तथा अफीम का उत्पादन	Production of Cigarettes and Opium	70-71
3731.	बिहार में खनिजों का निक्षेप	Mineral Deposits in Bihar	71-72
3732.	पश्चिमी तथा दक्षिण पूर्व रेलवे के स्टेशनों पर बिजली लगाना	Electrification of Stations on Western and S.E. Railway	72
3733.	फ्रन्टियर मेल गाड़ी से कैश बक्सों की चोरी	Theft of Cash Boxes from Frontier Mail	72-73
3734.	दरमियाने तथा मोटे कपड़े का निर्यात	Exports of Medium and Coarse Cloth	73
3735.	रेलवे विद्युतीकरण योजना के फालतू कर्मचारी	Surplus Employees of Railway Electrification Scheme	73-74
3736.	पटसन के दाम	Prices of Jute	74
3737.	राज्य व्यापार निगम के पास सोयाबीन तेल	Soyabean Oil With STC .	74
3738.	निर्यात प्रोत्साहन योजना	Export Incentive Scheme	74-75
3739.	खल कद सामान का उद्योग	Sports Goods Industry	75

अता० प्र० संख्या U.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3740.	अलौह धातु	Non-Ferrous Metals.	75-76
3741.	रेलगाड़ियों में चोरी	Pilferage on Railways	76
3742.	दिल्ली में उद्योग	Industries in Delhi.	76
3743.	छोटे पैमाने पर रबड़ की खेती	Small Scale Rubber Cultivation	
3744.	औद्योगिक उत्पादन	Industrial Production	77
3745.	टाटा आयरन ऐंड स्टील कम्पनी तथा इंडिया आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का विस्तार	Expansion of TISCO AND IISCO.	77-78
3746.	रेलवे कर्मचारियों के अंगहीन बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें	Educational Facilities to Disabled Children of Railway Employees	78
3747.	हेयर बैल्टिंग टाप्स का नियतन	Allocation of Hair Belting Tops	78
3748.	राजस्थान में जिन्क स्मैल्टर	Zinc Smelter in Rajasthan.	78-79
3749.	दुर्गापुर इस्पात कारखाना	Durgapur Steel Plant	79-
3750.	बैटरी के सैलों की कमी	Shortage of Battery Cells	79
3751.	उत्तर प्रदेश में रेलवे गैंगमैनों के लिये क्वाटर	Quarters for Railway Gangmen in U. P.	80
3752.	रेलगाड़ियों में जगह	Accommodation in Trains	80
3753.	लडलो जूट कम्पनी कलकत्ता	Ludlow Jute Company, Calcutta	80
3754.	रेलों पर रेल डिब्बा अटैंडेंट	Coach Attendents on the Railway.	81
3755.	बिड़ला तथा टाटाओं के उद्योग	Industries Owned by Birlas and Tatas	81-
3756.	रूस के व्यापार मंत्री की यात्रा	Visit by the Soviet Minister of Trade	82
3757.	सिले सिलाये कपड़ों के निर्माताओं को प्रोत्साहन-स्वरूप धन	Incentive Payment to Makers of ready made cloths	82
3758.	पश्चिमी बंगाल में पटसन मिलें	Jute Mills in West Bengal	82-83
3759.	सहायक स्टेशन मास्टरों के लिये उच्च श्रेणी के पद	Higher Grade Posts of Assistant Station Masters	83

अता० प्र० संख्या U.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3760.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में स्टेशन मास्टरों के लिये क्वार्टर	Quarters for Station Masters on N. E. Rly.	83-84
3761.	स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों का नौकरी से निकाला जाना	Removal from Service of Station Masters and Assistant Station Masters . . .	84-
3762.	चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप	Chittaranjan Locomotive Workshop	84-85
3763.	निर्यात के लिये प्रोत्साहन	Incentive for Exports . . .	85-86
3764.	निर्यात के कारण मुद्रा स्फीति	Inflation due to Exports . .	86
3765.	मध्य प्रदेश में लाइसेंसों का जारी किया जाना	Issue of Licences in Madhya Pradesh	86
3766.	बरहानपुर स्टेशन पर पंजाब मेल का रुकना	Halt of Punjab Mail at Burhanpur Station	86-87
3767.	नेपा पेपर मिल्स	Nepa Paper Mills	87
3768.	सहायक स्टेशन मास्टरों की पदोन्नति	Promotion of Assistant Station Masters	87
3769.	दक्षिण पूर्व रेलवे में नियुक्ति	Appointments on S.E. Railway . .	87-88
3770.	रायपुर में माल डिब्बों की मरम्मत का कारखाना	Wagon Repair Factory at Raipur .	88
3771.	जगदलपुर तथा बालोद के बीच रेलवे लाइन	Railway Line between Jagdalpur and Balod	88
3772.	भिलाई इस्पात कारखाना	Bhilai Steel Plant	88-89
3773.	समस्तीपुर डिवीजन के मैकनिकल विभाग के कैरिज कर्मचारियों को रात्रि कार्य भत्ता	Night Duty Allowances to Carriage Staff of Mechanical Deptt. of Samastipur Division	89
3774.	धामनगांव स्टेशन (मध्य रेलवे) पर प्लेटफार्म पर शेड की व्यवस्था	Shed over Platform at Dhamangaon Station (C. Rly)	89-90
3775.	कपड़े और रुई पर प्रतिबन्ध	Restrictions on cloth and cotton . .	90
3776.	साम्राज्य सम्बन्धी रियायती दर की नीति के स्थान पर नई नीति	Replacement of Imperial Preferences	90

अता० प्र० संख्या U. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
3777.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के कारखाने	H.M.T. Factories	90–91
3778.	अलोह धातु	Non-ferrous Metals	91–92
3779.	गैर सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां	Private Sector Companies . .	92–93
3780.	रानीगुन्ता और तिरुपती के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन बदलना	Conversion of M. G. Line into B. G. from Ranigunta to Trupati . .	93
3781.	गाड़ियों में चोरियों तथा बिना टिकट यात्रायें	Ticketless Travel and Thefts in Trains	93–94
3782.	जूतों का निर्यात	Export of Shoes	94
3783.	कोयला तथा अन्य खनिज पदार्थों की ढुलाई	Transportation of Coal and other Minerals	95–96
3784.	रेलवे सिगनलों का आयात	Import of Railway Signals . . .	96
3785.	रक्त सुरक्षित रखने के रैफ्रीजरेटरों और फ्रीजर्स का निर्माण	Manufacture of Blood Storage Refrigarators and Freezers	96–97
3786.	डीमापुर मनीपुर रोड नीचूगारोट रेलवे लाइन	Dimapur Manipur Road-Nichugarot Railway Line	97
3787.	बैटरी के सैलों का निर्माण	Manufacture of Dry Cell Batteries . .	97
3788.	नर्सों के लिये रेलवे यात्रा सम्बन्धी रियायतें	Railway Concessions to Nurses . .	98
3789.	जापान को निर्यात पर स्टर्लिंग के अवमूल्यन का प्रभाव	Impact of Devaluation of Sterling on exports to Japan	98–99
3790.	सुराकाचार कोयला खान से रूसी तारों के गुम होने के बारे में जांच	Enquiry into missing Russian Cables from Sura Kachar Colliery . .	99
3791.	बीकानेर में रेलवे फाटक	Railway Crossings in Bikaner . . .	99
3792.	यात्री सुविधायें	Passenger Amenities	100
3793.	खेत्री और कोलीहर ताम्बा खानें	Khetri and Kolihar Copper Mines . . .	100–101
3794.	भारतीय खान ब्यूरो	Indian Bureau of Mines	101

अता० प्र० संख्या U. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
3795.	रेलवे गार्डों के लिये संचल भत्ता	Running Allowance for Railway Guards	101
3796.	खनन मशीनरी का आयात	Import of Mining Machinery .	101
3797.	रेलवे में अविलम्बनीयता प्रमाणपत्रों के दिये जाने पर किये गये काम	Jobs executed on Urgency certificates on Railways	102
3798.	भतपूर्व बीकानेर रियासत की रेलवे के कर्मचारियों से मकान किराये की वसूली	Recovery of House Rent ftom Staff of Ex. Bikaner State Railway	102
3799.	ब्लैक चाय पर उत्पादन शल्क	Excise Duty on Black Tea . .	102–103
3800.	सहकारी औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण	L. I. C. Loans for establishing cooperative Industrial Estates	103
3801.	अतरा स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के लिये कार्यालय कक्ष	Office Room for Station Master at Atarra Station	103–104
3802.	कैमरून के साथ व्यापार समझौता	Trade Agreement with Cameroon	104
3803.	ईराकी औद्योगिक प्रतिनिधिमंडल	Iraqi Industrial Delegation . .	104–105
3804.	वाणिज्य मंत्री की विदेश यात्रायें	Foreign visits by Commerce Minister	105
3805.	आन्ध्र प्रदेश में सीमेंट का कारखाना	Cement Factory in Andhra Pradesh .	105–106
3806.	अन्तर्राष्ट्रीय काफी करार	International Coffee Agreement . .	106
3807.	हस्तिनापुर में कागज तैयार करना	Manufacture of Paper in Hastinapur	106–107
3808.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा इस्पात के माल का निर्यात	Export of Steel Products by Hindustan Steel Ltd.	107
3809.	सीप के बटन बनाने वाले कारखानों के लिये योजना	Scheme for shell Button Factories . .	108

U.Q.Nos	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3810.	कान्ती तथा मोतीपुर स्टेशनों के बीच नया स्टेशन	New Station between Kanti and Motipur Stations	108
3811.	मेहती (बिहार) में सीप के बटनों का उत्पादन	Manufacture of Shell Buttons in Mehti (Bihar)	108–109
3812.	जापान से रोल्ड इस्पात का आयात	Import of Rolled Steel from Japan	109
3813.	रेलवे में मिस्त्रियों के पदों की वर्गोन्नति	Upgradation of Posts of Mistries on Railways	109
3814.	पैकटों में चाय का निर्यात	Export of Tea in Packets	110
3815.	रेलवे में लोगों को यात्रा सम्बन्धी रियायतें	Travelling Concessions to the Public on the Railways	110
3816.	नैनी और इलाहाबाद स्टेशनों के बीच रेल-गाड़ियों में जंजीर का खींचा जाना	Chain-Pulling between Naini and Allahabad Stations	111
3817.	सराय रोहिल्ला स्टेशन पर रेल कर्मचारी के साथ मारपीट	Manhandling of Railway Employee at Sarai Rohilla Station	111
3818.	बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जम्बर्ग के साथ व्यापार करार	Trade agreement with Benelux countries	111
3819.	अखबारी कागज निर्माण कारखाने	Newsprint Plants	112
3820.	कच्चे रेशम पर आयात शुल्क	Import Duty on Raw Silk	112
3821.	आरंडी के तेल का निर्यात	Export of Caster Oil	112–113
3822.	पटना जंकशन और पटना सिटी स्टेशन के नामों में परिवर्तन	Change in the names of Patna Junction and Patna Station	113
3823.	कोयले की खनन लागत	Cost of Mining coal	113–114
3824.	मैसूर में नये उद्योग	New Industries in Mysore	114
3825.	वेस्टीबुलर गाड़ियां	Vestibular Trains	114
3826.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	Hindustan Steel Ltd.	114–115

अता० प्र० संख्या

U.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3827.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची	H.E.C., Ranchi .	115
3828.	कोट्टयम में क्षेत्रीय चाय बोर्ड	Regional Tea Board at Kottayam	115
3829.	रेलवे के कर्मचारी निरीक्षक और कल्याण निरीक्षक	Personnel and welfare Inspectors on Railways	115–116
3830.	गैर-सरकारी क्षेत्र में कच्चे लोहे के कारखाने	Pig Iron Units in Private Sector	116
3832.	रेलवे विशेष सुरक्षा दल	Railway Security Special Force	116
3833.	रेलवे मंत्रालय में हिन्दी में काम	Hindi Work in Railway Ministry .	116–117
3834.	रेलवे यात्रियों की श्रेणियां	Classes of Railway Passengers .	117
3835.	हिन्दी में कार्य	Work in Hindi	117
3836.	हैवी इलेक्ट्रिकल संयंत्र	Heavy Electrical Plants	117
3837.	दिल्ली में रेलवे कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of quarters to Railway employees in Delhi	118
3838.	रासायनिक संयंत्र तथा मशीनरी संस्था	Chemicals Plant and Machinery Association	118
3839.	खनन तथा सम्बद्ध मशीनरी निगम, दुर्गापुर	Mining and Allied Machinery Corporation, Durgapur	118–119
3840.	खनन तथा सम्बद्ध मशीनरी निगम	Mining and Allied Machinery Corporation	119–120
3841.	चामाग्राम स्टेशन का रेलवे यार्ड	Railway Yard Chamagram Station	120
3842.	आटा तथा मैदा मिल	Flour and Maida Mills . .	120–121
3843.	स्वयं चालित यंत्रों से रेलगाड़ियों को रोकना	Stopping of Trains with Automatic Devices	121
3844.	हरयाना में इस्पात कारखाना	Steel Plant in Haryana . . .	121
3845.	पांचवां इस्पात कारखाना	Fifth Steel Pant	121–122
3846.	भारतीय मानक संस्था के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Employees of Indian Standards Institution . . .	122
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	123–126

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
एम० वी० विश्वशान्ति जहाज का कांस्टेन्टज़ा के निकट धंस जाना	Grounding of M. V. Vishwa Shanti at Constanza .	123—126
श्री सीताराम केसरी	Shri Sita Ram Kesari .	123
डा० वी० के० आर० वी० राव	Dr. V. K. R. V. Rao .	123—126
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	126
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Committee on Public Undertakings .	127
कार्यवाही सारांश	Minutes . .	127
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	127
तेईसवां प्रतिवेदन	Twenty-third Report	127
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee . . .	127
सैंतीसवां तथा चवालीसवां प्रतिवेदन	Thirty-seventh and Forty-Fourth Report .	127
मारीशस द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त किये जाने के बारे में वक्तव्य	Statement re. Attainment of Independence by Mauritius .	127–128
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	127–128
सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा	General Budget—General Discussion	128
डा० मेलकोटे	Dr. Melkote .	128
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua .	128—131
श्री को० सूर्य नारायण	Shri K. Suryanarayana . .	131–132
श्री रवि राय	Shri Rabi Ray	132–133
श्री पी० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti . .	133–134
डा० वी० के० आर० वी० राव	Dr. V. K. R. V. Rao . . .	135—137
श्री प्र० के० देव	Shri P. K. Deo . . .	137—140
श्री मुद्रिका सिंह	Shri Mudrika Sinha .	140
श्री मनोहरन	Shri Manoharan .	140—142
श्री रा० कृ० सिंह	Shri R. K. Sinha . . .	142–143
श्री सेक्वीरा	Shri Sequeira	143—145
श्री तुलशीदास जाधव	Shri Tulshidas Jadhav	145–146
श्री आर० एस० अरुमुगम	Shri R. S. Arumugam . . .	146—149
श्री तन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham . .	149—151
श्री एम० वी० राणा	Shri M. B Rana	151–152

लोक-सभा वाद-विवाद का

संक्षिप्त अनुदित संस्करण

दिनांक 12 मार्च, 1968। 22 फाल्गुन, 1889 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
शीर्षक पृष्ठ	'तीसरा सत्र' के स्थान पर 'चौथा सत्र' पढ़िये। Third Session / Fourth Session
1	'March 13' के स्थान पर 'March 12' पढ़िये
6.	ऊपर से चौदहवीं पंक्ति में 'औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)' के स्थान पर 'औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह)' पढ़िये।
24	पंक्ति 17 में 'श्री क.रा. सिंह देव' के स्थान पर 'श्री रा.रा. सिंह देव' पढ़िये।
35	पंक्ति 18, 'अतारांकित प्रश्न संख्या 19' के स्थान पर 'अतारांकित प्रश्न संख्या 1636' पढ़िये।
105	ऊपर से पंक्ति संख्या 13 में '3805' के स्थान पर '3804' पढ़िये
142	ऊपर से पंक्ति संख्या 18 में 'श्री रा.कु. सिंह' के स्थान पर 'श्री रा.कृ. सिंह' पढ़िये।
146	पंक्ति 34 में 'श्री अरुसुरम' के स्थान पर 'श्री अरुमुगम' पढ़िये।

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	
श्री कृ० मा० कौशिक	Shri K. M. Kaushik	
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata	
श्री उमानाथ	Shri Umanath	
श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	
श्री कृष्णमूर्ति	Shri V. Krishnamoorthi	
श्री शशि भूषण वाजपेयी	Shri Shashibhushan Bajpai	
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Srinibas Misra	
श्री रबि राय	Shri Rabi Ray	
श्री बूटा सिंह	Shri Buta Singh	

लोक सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 12 मार्च, 1968 / 22 फाल्गुन, 1889 (शक)

Tuesday, march 13, 1968/Phalguna 22, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

Lok Sabha met at Eleven of the Clock

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

रेलवे में घाटे के कारण छंटनी

***570. श्री लखन लाल कपूर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में घाटे के कारण सरकार ने चौथी योजना में रेलवे के विकास-कार्य के लिये बजट में की गई धन व्यवस्था में कमी कर दी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि चौथी योजना में बजट में की गई धन व्यवस्था को कम करने के कारण रेलवे ने रेलवे के विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी तथा पदावनति के लिये आदेश जारी कर दिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कर्मचारियों की छंटनी अथवा पदावनति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में अपेक्षित परिव्यय की तुलना में रेलों के विकास के लिए बजट परिव्यय में 1966–67 से लेकर 1968–69 के वर्षों में कमी करनी पड़ी क्योंकि माल यातायात में प्रत्याशित वृद्धि नहीं हुई और यह रेलवे के घाटे के बजट का एक महत्वपूर्ण कारण है ।

(ख) और (ग). नियमित रेल कर्मचारियों की छंटनी की आशा नहीं है, यद्यपि कुछ कर्मचारियों का प्रत्यावर्तन अपरिहार्य हो सकता है । जब कर्मचारी आवश्यकता से अधिक हो जाते हैं, उन्हें वैकल्पिक काम दिया जाता है । केवल नैमित्तिक मजदूरों को, जिन्हें

नियमों के अन्तर्गत नियमित रेल कर्मचारी नहीं माना जाता उस काम के पूरा हो जाने पर सेवामुक्त किया जा सकता है, जिस काम के लिए उनकी भर्ती की गयी थी। लेकिन उन के मामले में भी इस बात की पूरी कोशिश की जाती है कि क्या उनके लिए किसी वैकल्पिक काम की व्यवस्था की जा सकती है ।

Shri Lakhan Lal Kapoor: Mr. Speaker, I want to know from the Minister of Railways regarding the retrenchement being talked about in Railways ; and whereas persons earlier were recruited with a view to improving the efficiency of Administration, will it not be decreased if there is retrenchment and if it decreases then why his retrenchment ?

श्री परिमल घोष: जहाँ तक रेलवे के नियमित कर्मचारी-वृन्द का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने पहले बताया, कोई छंटनी करने का विचार नहीं है । छंटनी तो निर्माण तथा परियोजना कार्य में हो सकती है तथा इसका प्रभाव तो उन्हीं लोगों पर पड़ेगा जो कि रेलवे के नियमित कर्मचारी नहीं गिने जाते । निर्माण-कार्य में किसी विशेष निर्माण-परियोजना हेतु हम काफ़ी आदमी भरती करते हैं और जब काम समाप्त हो जाता है तो स्वाभाविक है कि उनकी छंटनी करनी पड़ती है ।

Shri Lakhan Lal Kapoor: To avoid deficit in Railway Budget and keep it balanced, will the hon. Minister think in terms of abolishing this useless and very expensive Railway Board and thus doing away with the costly officers' saloons ? Whether there is any plan with the Government, if not whether the Government is formulating a plan to abolish Railway Board ?

श्री परिमल घोष : मुख्य प्रश्न में से रेलवे बोर्ड के बारे में प्रश्न नहीं उठता । मैं पहले ही बता चुका हूं कि छंटनी तो केवल निर्माण परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में ही हो सकती है ।

श्री उमा नाथ : रेलवे मंत्रालय के नवीनतम प्रतिवेदन के अनुसार मुझे पता लगा है कि यहाँ 4,000 कर्मचारियों की वृद्धि हुई तथा इसकी तुलना में 800 अधिकारियों की वृद्धि हुई जिसका अर्थ है प्रत्येक 5 कर्मचारियों पर एक अधिकारी। क्या मैं जान सकता हूं कि अधिकारियों और कर्मचारियों का परस्पर इतना ऊंचा अनुपात क्यों है, और क्या सरकार सीधी भरती के स्थान पर नीचे पद से ऊंचे पद की ओर पदोन्नति का ढंग अपनायेगी ताकि मंत्री के वचनानुसार, यथासम्भव, एक तदर्थ मजदूर की भी पदोन्नति न हो ?

श्री परिमल घोष : यह सत्य है कि अधिकारियों की कुछ वृद्धि हुई है परन्तु यह वृद्धि चिकित्सा -विभाग में हुई है तथा यह भी श्रेणी iii के लायसेंस-धारियों को श्रेणी ii में पदोन्नत करने के लिये है ।

श्री उमानाथ : 800 की संख्या है ।

श्री परिमल घोष : 1966–67 में प्रायः 1100 व्यक्तियों को श्रेणी iii से श्रेणी ii में पदोन्नत किया है।

श्री उमानाथ : सीधी-भरती के बारे में क्या नीति है ?

श्री परिमल घोष : सीधी भरती के बारे में, कुछ मामलों पर हम इसी पद्धति पर सोच रहे हैं परन्तु हम किसी विशिष्ट निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। अभी तक यह जाँचाधीन है।

Shri Chandika Prasad : Hon. Minister has said that there has not been any retrenchment whereas I say that the persons kept on casual labour are never allowed to complete six months of service and generally they are removed a month before they complete six months, procedurally, they should be made regularised. In this way, lakhs of casual labourers become jobless.

what is the reply of the Hon. Minitser to this ?

श्री परिमल घोष : जो नैमित्तिक मजदूर प्रायोजनाओं तथा निर्माण-कार्यों के लिये नहीं होते उन को छः मास पूरा करने पर अस्थायी रेलवे कर्मचारी माना जाता है। परन्तु रोजगार न देने का प्रश्न तो उन कर्मचारियों के लिये उठता है जो कि किसी प्रायोजना के अन्तर्गत निर्माण-कार्य में लगे हैं।

Shri Rabi Ray : Whether the temporary people working for a project have been removed after the work is over ? Will the Hon. Minister state as to how much money is spent on the officers' saloon and will consider the abolishing of these saloons and thereby providing the jobs to those jobless people with the help of money thus saved ?

श्री परिमल घोष : उसका इस से सम्बन्ध नहीं है, परन्तु फिर भी यदि हम इन सैलूनों से सम्बन्धित कोई प्रबन्ध कर भी लें तो भी ये मजदूर तो किसी विशेष कार्य के लिये विशेष रूप से भरती किये जाते हैं तथा वह कार्य पूरा होने पर उन्हें निकाल देने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं।

Shri Sheo Narain : An unnecessary expenditure of Rs. 18 crores, with regards to issuing free passes......

An Hon. Member : Hon. M.Ps. also get free passes ?

Shri Sheo Narain : I include those also. I mean, if you abolish all of these first class passes, you will be able to save Rs. 18 crores and adjust this towards your Railway Budget deficit I want to know whether the Government would appoint a special Committee to consider this matter? Government may not agree with us but get it investigated by appointing a special Committee.

श्री परिमल घोष : रेलवे का खर्च घटाने के लिये लगातार प्रयत्न किये गये हैं तथा किये जा रहे हैं। मुफ्त पासों तथा विशेषाधिकार यात्रा आदेश-पत्रों के सम्बन्ध में, हाल ही में, हमें समिति प्राक्कलन का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जो कि विचाराधीन है।

Shri Deven Sen : Whether there has been an order of retrenching 2000 members of class IV staff and side-by-side recruitment of class I and class II officers is being made in Asansol Division ?

श्री परिमल घोष : मेरे पास यह विशिष्ट जानकारी नहीं है।

Shri Nathu Ram Ahirwar : Whether the Hon. Minister of Railways be pleased to state whereas casual labourers, have been retrenched, the regular employees also, have been reversed, whether there is any bargaining in regard to such a reversion and the recruitment of officers ? Whether the Government received any information in this connection, if so, what action is being taken thereon ?

श्री परिमल घोष : मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं मिली।

डा० रानेन सेन : अभी अभी मंत्री महोदय ने प्रायोजनाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में कहा । क्या सरकार ने रेलवे विद्युतीकरण प्रायोजना कर्मचारियों के बारे में भी कोई योजना बनाई है ? जहाँ तक मुझे मालूम है रेलवे मंत्री जी ने कुछ समय पूर्व एक विश्वास दिलाया था कि फालतू कर्मचारियों को उचित रोजगार दे दिया जायेगा । वर्तमान नीति क्या है ? उन को रोजगार देने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री परिमल घोष : रेलवे विद्युतीकरण परियोजना भी अपने आप में एक प्रायोजना है । पहले हमारे पास इसमें काफ़ी संख्या में कर्मचारी थे क्योंकि हमें काफ़ी सारी विद्युतीकरण परियोजनायें उठा रखी थीं । अब काम के सिकुड़ने अथवा घटने से कोई छंटनी हुई है । उन को दूसरे रोजगार देने के सब प्रयत्न किये गये हैं । वास्तव में तो, उस प्रायोजना से बेकार हुए काफ़ी लोगों को दूसरी नौकरियों में रख लिया गया है ।

श्री बी० चं० शर्मा : रेलवे के केटरिंग विभाग को निश्चित रूप से लाभ वाला विभाग बनाया जा सकता था, किन्तु जहां तक मुझे पता है यह एक घाटे वाला विभाग है। इस विभाग को जनता के लिये अधिक उपयोगी और रेलवे के लिये अधिक लाभ वाला बनाने के लिये सरकार क्या पग उठाने जा रही है ?

श्री परिमल घोष : केटरिंग पर आज एक पृथक् प्रश्न है । मैं उस प्रश्न के आने पर इसका उत्तर दूंगा ।

Shri Balraj Madhok : what steps have been taken [as are benig taken to effect improvement in the management of Railway stores and present miguse of material ?

श्री परिमल घोष : स्टोर्स के मामले की जांच करने और यथासम्भव बचत करने के लिये हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री द० रा० परमार : क्या रेलवे कर्मचारियों की छंटनी करते समय सरकार अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों को और सुविधाएं दे रही है क्योंकि श्रेणीवार उनके लिये विहित कोट में उनका पूरा प्रतिनिधित्व नहीं है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : भर्ती के नियमों के अनुसार हम अधिकतम संख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी रखने का प्रयत्न करते हैं। वास्तव में श्रेणी तीन और चार के सम्बन्ध में उनका अनुपात पर्याप्त रूप से पूरा हो जाता है, किन्तु प्रशिक्षित कर्मचारियों के सम्बन्ध में वे पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। इस छंटनी का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों पर बुरा असर न पड़े इसके लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि इस योजना के परिणामस्वरूप उत्तर सीमान्त रेलवे के 10000 से भी अधिक कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है ; यदि हां, तो सरकार उनको और क्या रोजगार देने जा रही है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं नहीं समझता कि संख्या 10000 है । उत्तर सीमान्त रेलवे में कुछ परियोजनाओं के पूरा होने के कारण कुछ नैमित्तिक कर्मचारी और श्रमिक बेकार हो गये हैं। किन्तु उनमें से अधिकांश को रेलवे में वैकल्पिक रोजगार भी दिया गया है ।

Shri Ram Charan : The vacancies of Class III posts are not advertised and persons from Class IV posts are promoted on receipt of Rs. 500—700 from each person. I want that the vacancies should be advertised and filled by through employment exchange to put an end to corruption.

श्री परिमल घोष : श्रेणी तीन और श्रेणी चार की रिक्तियों को अधिसूचित किया जाता है। भर्ती के लिये एक समिति नियुक्त की गई है वह सभी आवेदन पत्रों की जांच करके नियुक्तियां करती है।

श्री देव व्रत बरुआ : सारी योजना तथा इस्पात विकास रेलवे की मांग पर निर्भर करता है किन्तु पिछले साल रेलवे द्वारा अपनी इस्पात माल डिब्बों आदि की मांग में 30 प्रतिशत की कमी किये जाने के कारण मन्दी का रुख अपनाया था तो क्या रेलवे अपनी मांग इस प्रकार की कमी न करने पर विचार करेगी ताकि सारे देश की अर्थव्यवस्था पर उसका बुरा असर न पड़े?

श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या सरकार ने पारगामी स्थानों पर काम करने वाले नैमित्तिक श्रमिकों को स्थायी बनाने का निर्णय किया है?

श्री परिमल घोष : जिन स्थानों पर ठेकेदारों द्वारा कम संख्या में श्रमिक दिये जाते हैं, वहां हम रेलवे सहकारी श्रमिकों से काम लेने का प्रयत्न करते हैं।

Shri Sarjoo Pandey: May I know the reasons for not abolishing the Railway Board and other higher posts with a view to redressing the grievances of the Railways employees and preventing retrenchment in regard to which representations have been made a number of times particularly from Railway Guards Association ?

श्री परिमल घोष : रेलवे के गार्डों तथा अन्य कर्मचारियों से कुछ अभ्यावेदन और ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। इस समय हम उनपर विचार कर रहे हैं और यदि सम्भव हुआ तो हम उन्हें कुछ देने का प्रयत्न करेंगे।

Shri Shiv Charan Lal : Do Government propose to revive the 20 year train service run between Agra and Waha via Etava ?

श्री परिमल घोष : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

श्री नायनार : क्या यह सच है कि ओलावावकोट स्टेशन 'करेओसोट प्लांट' में अनेक स्थायी कर्मचारियों की छटनी की गई है और 29 फरवरी को उत्तर रेलवे के मुख्यालय ने 8 या 10 वर्ष की सेवा वाले पांच स्थायी कर्मचारियों को छंटनी के नोटिस दिये थे? क्या सरकार उन नोटिसों को रद्द कर के उन्हें बहाल करेगी?

रेलवे मंत्री (चे० मु० पुनाचा) : जहां तक ओलावावकोट संयंत्र का सम्बन्ध है वहां पर कार्यभार कम हो गया है क्योंकि सरकारी वन विभागों से स्लीपर उपलब्ध होने लगे हैं। विभिन्न राज्य सरकारें मांग कर रही हैं कि हम उनसे स्लीपर खरीदें। उनसे स्लीपर खरीद कर उन्हें ओलावावकोट में तैयार करके कुछ कठिनाइयां पैदा होती हैं। इसलिये वहां पर कार्यभार कम हो गया है और कुछ कर्मचारी बेकार हो गये हैं। जहां तक उत्तर रेलवे के पांच स्थायी कर्मचारियों का सम्बन्ध है यदि मुझे विशिष्ट जानकारी दी जाये तो मैं उसकी जांच करूंगा।

सीमेन्ट आवंटन तथा समन्वय संगठन

+

*573. श्री पी० राम मूर्ति
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री रमानी :
श्री उमानाथ :
श्री अनिरुद्धन :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट आवन्टन तथा समन्वय संगठन द्वारा स्थापना के समय से लेकर अब तक क्या-क्या चूक की गई हैं ;

(ख) भारतीय सीमेंट निगम के कृत्य क्या हैं ; और

(ग) सीमेंट वितरण की प्रणाली क्या है और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सीमेंट आवन्टन तथा समन्वय संगठन के कार्य में निम्नलिखित खराबियां और कमियां सरकार के ध्यान में आई हैं :—

1. 1-4-67 से तेल अनुदान की गैर अदायगी से हुई बचत का भाड़े को सामान करने के लिए पूरी तरह से उपयोग न किया जाना ।

2. सीमेंट आवन्टन तथा समन्वय संगठन ने धन की कमी के तर्क पर सरकार के इस सुझाव को नहीं माना था कि वह वर्षा ऋतु में सीमेंट की पूर्ति सम्बन्धी स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए उपभोक्ता केन्द्रों के समीप सीमेंट के स्टोर की सुविधाओं का निर्माण करे ।

3. संगठन ने सरकार के निदेशों के विपरीत संधारण मूल्यों की दोहरी प्रणाली लागू की ।

4. संगठन के सदस्यों में आन्तरिक मतभेद हो गए । दो सदस्यों ने अपनी सदस्यता समाप्त कर दी और कुछ अन्य सदस्य ऐसा करने की धमकी दे रहे थे ।

5. संगठन ने राज्य व्यापार निगम के पास पिछली नियंत्रण अवधि में हुई सीमेंट अभिकरण खाते में 39.91 लाख रुपये की घाटे की राशि जमा नहीं करवाई थी ।

6. संगठन सीमेंट का कुछ भी निर्यात नहीं कर सका ।

7. सरकारी विभागों द्वारा कम सीमेंट उठाने से होने वाली बचत का प्रयोग विस्तार के लिए आरक्षित निधि के रूप में किया जाना था किन्तु उसने इसके विपरीत इसे अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए संगठन के हवाले कर दिया और यह भी पता चला है कि संगठन के अध्यक्ष को दी गई राशि वस्तुतः राजनैतिक दलों को चन्दा देने में खर्च की गई ।

(ख) सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

1. देश में सीमेंट ग्रेड के चूने के पत्थर के सर्वेक्षण और खुदाई की व्यवस्था करना ;
2. चौथी पंचवर्षीय योजना में सीमेंट उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकारी क्षेत्र में सीमेंट की पर्याप्त क्षमता का निर्माण करना ;
3. सीमेंट उद्योग के विकास से सम्बद्ध तथा सहायक सभी कार्य करना और विशिष्टता का विकास करना ; तथा
4. देश में सीमेंट के वितरण, क्रय तथा विक्रय का नियमन करना तथा निर्यात की व्यवस्था करना ।

(ग) 1968 की पहली तिमाही में सीमेंट वितरण प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । किन्तु इस वर्ष की दूसरी तिमाही में सीमेंट के वितरण के बारे में अभी निर्णय किया जाना है ।

सीमेंट कारपोरेशन ने सीमेंट के बिक्री एजेंटों से कहा है कि यदि देश के किसी भी भाग में सीमेंट की कमी की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वे निगम को लिखे बिना ही उसकी सप्लाई बढ़ा सकते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमेंट निगम द्वारा राज्य सरकार के द्वारा नामजद व्यक्तियों के पक्ष में विशेष रिलीज आर्डर भी जारी किये जायेंगे ।

श्री पी० राम मूर्ति : सीमेंट आवंटन तथा समन्वय संगठन में मुख्य रूप से सीमेंट के बड़े निर्माता शामिल हैं । जबकि यह संगठन किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिये बनाया गया था, तो यह सुनिश्चित करने के लिये कि यह अपने कृत्यों का दुरुपयोग न करे सरकार ने क्या व्यवस्था की ? दूसरे क्या यह सच है कि इस संगठन ने राजनीतिक दलों को धन दिया है ? भूमि शासक दल को भी इससे काफी धन प्राप्त हुआ है, क्या इसीलिये इसके कार्य के सम्बन्ध में सरकार ने कोई जांच नहीं करवाई ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : जैसा कि माननीय सदस्य को पता है, सीमेंट पर से नियंत्रण 1 जनवरी, 1966 को हटाया गया था परन्तु उद्योग अनौपचारिक नियंत्रण के लिये राजी हो गया था उस प्रयोजन के लिये उसने सीमेंट आवंटन तथा समन्वय संगठन स्थापित किया । इस संगठन का उद्देश्य यह था कि सीमेंट का वितरण सभी उपभोग केन्द्रों, मनीपुर और नेफा जैसे दूरस्थ स्थानों पर भी किया जायेगा । सरकार की आवश्यकता के लिये भी वे अपना (एक तिहाई उत्पादन देने को सहमत हो गये थे) यह एक स्वयंसेवी संगठन था । उद्योग के सदस्यों ने आपस में लड़ना आरम्भ कर दिया, उनमें कुछ बाहर निकल गये और कुछ अन्य ने निकलने की धमकी दी । जब हमने देखा जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये इस संगठन को स्थापित किया गया था वह पूरा नहीं किया जा रहा है तो सरकार ने इस संगठन के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की ।

श्री पी० राम मूर्ति : किन किन राजनीतिक दलों को इस संगठन से कितना कितना चन्दा प्राप्त हुआ है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां तक राजनीतिक दलों को दी गई राशि का सम्बन्ध है वह इस प्रकार है : 34,15,355 रुपये० में से स्वतन्त्र पार्टी 14,64,000 रु०, कांग्रेस 10,06,000 रु०, जनसंघ 5,12,000 रु०, नेशनल कांफ्रेंस 2,08,000 रु०, और जन कांग्रेस 2,25,000 रु० ।

श्री रमानी : यह संगठन सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। किन्तु उत्पादन सूचकांक 225.8 था जो 1967 में घट कर 198 रह गया । अतः उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं है । इसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार पुनः नियन्त्रण लागू करेगी और सीमेंट में मुनाफ़ाखोरी को रोकने के लिये इसके वितरण को अपने हाथ में लेगी ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : शायद माननीय सदस्य को पता नहीं है कि औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 18(जी) और 25 के अन्तर्गत यह कार्य अब सीमेंट निगम के माध्यम से सरकार द्वारा किया जाता है । जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है वह देश में मांग से अधिक है ।

श्री उमानाथ : उनका प्रश्न है कि क्या यह अपेक्षाकृत कम हुआ है ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह कम नहीं हुआ है ।

श्री उमानाथ : क्या यह सच है कि विनियन्त्रण के पश्चात् विभिन्न सीमेंट कम्पनियों के मुनाफे में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो विनियन्त्रण के पश्चात कितने प्रतिशत मुनाफा सीमेंट उद्योग के विस्तार में लगाया गया है और क्या सरकार का विचार सीमेंट के मूल्य में कमी करने का है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यदि माननीय सदस्य इस प्रश्न के लिये अलग से सूचना दें, तो मैं इसका ब्यौरा दे दूंगा । विभिन्न क्षेत्रों के लिये दो या तीन मूल्य क्यों निश्चित किये गये हैं, वास्तव में यह एक शिकायत थी और यह कारण था कि उद्योगों के कुछ सदस्यों ने सदस्यता से इस्तीफा देने की धमकी दी । हम इस प्रश्न की जांच कर रहे हैं कि क्या सभी कारखानों के सीमेंट के लिये समान दर निश्चित की जा सकती है । सीमेंट के मूल्य में कमी करने का इस समय कोई विचार नहीं है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : चूंकि यह संगठन सीमेंट उद्योग के संवर्द्धन के अपने उद्देश्य में विफल रहा है और इसने राजनीतिक दलों को चन्दा दिया है, इसलिये सरकार इसके विरुद्ध क्या दाण्डिक कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : कुछ अनियमितताओं का पता लगते ही हमने इस संगठन को अपनी कार्यवाही जारी रखने से रोक दिया । जहां तक अन्य कार्यवाही का सम्बन्ध है उसके बारे में कुछ कहना लोकहित में नहीं होगा । मामलों की जांच की जा रही है।

श्री कंडप्पन : सीमेंट पर से नियन्त्रण हटाने के साथ साथ सरकार ने इसके मूल्य में भी वृद्धि की और वह इस सूत्र पर कि वितरण व्यवस्था को समुचित बनाया जायेगा

और अतिरिक्त मुनाफे को उद्योग में लगाया जायेगा । अब चूंकि विनियन्त्रण के पश्चात् वे अपना वचन पूरा नहीं कर पाते हैं और बहुत सी अनियमितताओं का पता लगा है, क्या सीमेंट के मूल्य में कमी करना उचित न होगा ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह कहना सही नहीं है कि सभी कारखानों के अपने मुनाफे को कारखानों के विस्तार में नहीं लगाया है । अधिकांश कारखानों ने अपने मुनाफे को कारखानों के विस्तार में लगाया है। कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में हम सोच रहे हैं कि उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री प्र० कु० घोष : ऐसा समझा जाता है कि कुछ निर्माता मण्डी में सीमेंट की कमी बनाये रखने के लिये उत्पादन घटाने का प्रयत्न कर रहे हैं । इसको ध्यान में रखते हुए उन कारखानों को उनकी वास्तविक क्षमता पर चलाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां तक मेरी जानकारी है, वर्तमान स्थिति कठिन नहीं है और यही कारण है कि सीमेंट निगम स्थापित किया गया है । यदि सप्लाई को मांग से कम पाया गया तो सीमेंट निगम कुछ कारखानों को सरकारी क्षेत्र में ले लेगा ।

Shri Shinkre : May I know from the hon. Minister whether the tranport facilities have been taken into account or not in the zones set up for the distribution of cement? Goa falls in the western zone and cement produced in Gujarat is allotted to it. That cement is transported through Sazaur sea route which remains closed, as is evident, at least for four and a half months during monsoons. That is why there is always shortage of cement in Goa. Keeping it inview may I know whether the hon. Minister propose to include Goa in Southern zone ?

Shri F. A. Ahmed : We have not formed any zones and we are prepared to supply cement from where it can be supplied. In case we receive any complaint of shortage of cement we will see to it as to how we can supply the same.

Shri K. N. Tiwari : May I know the total requirement of cement in the country, the production at present and whether it is being imported from abroad?

Shri F. A. Ahmed : I don't have the total figures of production with me at present. In case the hon. Member wants I will supply the same later on. The question of import of cement does not arise. On the other hand it should be exported.

श्री बलराज मधोक : उन्होंने माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने यह पूछा था कि क्या सीमेंट का आयात किया जाता है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : दूसरी ओर हमें सीमेंट का निर्यात करना चाहिये ।

श्री लोबो प्रभु : इस समय स्थिति यह है कि सीमेंट का उत्पादन कम हो रहा है। योजना में कमी होने के कारण सीमेंट की बिक्री और खपत कम हो रही हैं। अतः क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार सीमेंट के सारे उत्पादन और वितरण को कारखानों पर छोड़ने का विचार कर रही है ?

श्री उमानाथ : ताकि उन्हें और बीस लाख रुपये मिल सकें।

श्री लो॰ प्रभु : नियंत्रण हटाने की नीति से मूल्य भी कम हो जायेंगे और इसकी मांग अन्य दल भी कर रहे है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां तक सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का सम्बन्ध है हमने ऐसा इसलिये किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि कमी वाले क्षेत्रों में भी वह समान मूल्य पर मिल सके। यदि हम उन धाराओं के अन्तर्गत, जिनका अभी उल्लेख कर चुका हूं। कार्यवाही न करते तब कुछ क्षेत्रों में सीमेंट बिल्कुल ही न मिलता।

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही कह चुके हैं कि दूरस्थ क्षेत्रों में भी सीमेंट समान दरों पर मिलना चाहिये। प्रश्न यह है कि क्या सीमेंट पर से नियंत्रण हटाने का उनका विचार है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है, अब हम नियंत्रण नहीं हटा रहे है।

Shrimati Jayaben Shah : The time such efforts are being made to improve the cement industry its position is becoming from bad to worse. At the time of decontrol it was hoped in the country that some improvement will be here. But may I know whether taking into consideration all these factors Government propose to treat cement indutry as a basic industny and its production and disttribution nationalised.

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : सीमेंट उद्योग एक उपभोक्ता उद्योग है तथा उपभोक्ता उद्योगों के बारे में सरकार की यह नीति है कि गैर-सरकारी क्षेत्र को वहां चलने की अनुमति दी गई है। परन्तु जब कभी हमने सार्वजनिक हित से किसी उपभोक्ता मूल्य को सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लाना आवश्यक समझा तो हमने उसके लिये कार्यवाही की। अब कुछ क्षेत्रों में सीमेंट के कुछ कारखाने स्थापित करने के लिये सीमेंट निगम भी बनाया गया है। दो कारखानों के सम्बन्ध में पहले कार्यवाही की जा चुकी है तथा दो अन्य कारखाने स्थापित करने से सम्बन्धित प्रस्ताव विचाराधीन है ?

श्री स॰ मो॰ बनर्जी : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या वह कम्पनी अधिनियम में संशोधन करने के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं ताकि कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को दिये जाने वाले धन पर रोक लगाई जा सके। जो कोई भाषण उन्होंने जनता में दिया है उससे पता चलता है कि वह इस काम के लिये कम्पनी अधिनियम में संशोधन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने सरकारी तौर पर ऐसा निश्चय कर लिया है या नहीं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इस मामले के बारे में मैं पहले ही ब्यान दे चुका हूं और मैं उस पर तत्पर हूं। उसी के अनुसरण में हम एक विधेयक संसद् में ला रहे हैं।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : इस निगम से कितने टन उत्पादन बढ़ाये जाने की आशा की जाती थी तथा यह खाई कितनी देर में पूरी होने की सम्भावना है। यह भी जानना चाहता हूं कि इस संगठन से 39 लाख रुपये की देय राशि वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इस काम को सीमेंट निगम ने अपने हाथ में ले लिया है और हमें आशा है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा देय राशि निगम द्वारा शीघ्र ही दी जायेगी। हम दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में भी कार्यावाही कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या सीमेंट उद्योग के विकास और विस्तार के लिये व्यय की गई धनराशि की जानकारी सरकार को है जिसे विशेष प्रयोजन से इस निगम को बनाया गया था ? दूसरे, मंत्री महोदय ने कहा है कि जैसे ही सरकार को इसका पता लगा उसने कार्यवाही की। मैं यह जानना चाहता हूं कि वास्तव में उन्हें कब पता लगा। क्या उन्हें इस बात का तब पता लगा जब उन्हें यह मालूम हो गया कि स्वतंत्र दल को कांग्रेस दल से अधिक धन दिया गया है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह आरोप निराधार है। जब लेखापरीक्षित लेख हमें भेजे गये थे तो हमें पता चला कि कुछ धनराशि राजनीतिक कोषों में दी गई है। सरकार को तब इसका पता लगा।

Shri Bhola Nath : In part (c) of the reply given by the hon. Minister a mention has been made regarding good arrangements for the ruralites. But there are three categories in ruralites also. One is what is known as seal quota. Secondly quota is given for agricultural purposes such as for the digging of wells. Since the Corporation has taken over the cement industry they have been taking the seal quota because there was black marketing in it and the quota which was given for agrcultural purposes that was distributed either through Sarpanches or B.D.Os. on the basis of permits. It may be that the same was not terkenover as a result of which cement was not available for wells. Now since the summer has set in what arrangements are being made to give cement to the agriculturists according to their requirements.

Shri F. A. Ahmed : As far as rural areas are concerned we are prepared to give this charge to the nominee of State Government who may distribute the same where required.

Shri Raghubir Singh Shastri : May I know whether the ratio of population of the rural areas will also be taken into consideration at the time the quota of cement is allotted ?

Shri F. A. Ahmed : In case the State Government requires it. They may nominate a person if they want to give more quota to the rural poeple. We will try our best to supply cement according to their requirement.

Shri Raghubir Singh Shastri : This was not my question. I wanted to know whether the ration of rural and urban population will be taken into account while allotting cement?

Shri F. A. Ahmed : It is allotted taking into consideration the requirements of the rural areas.

Shri Rabi Ray : While giving answer to the question of Shri Banerjee he has said that he is not cousidering to reduce the price of cement.' So may I know the cost price per bag of cement and the price at which it is being sold ? I would also like to known the rate of tax charged on it as well as its cost and selling price ?

Shri F. A. Ahmed : It is different in different units. The figures are not available which are not present.

Shri Prem Chand Verma : May I know whether, since January 1968, when the distribution of cement was taken over from cement Allocation and Coordination organisation, the accounts of this organisation have been checked and whether they have found out as to how much amount was misappropriated by them? If they have done so then what is the detail in regard there to and if not whether they propose to enquire into the same?

Shri F. A. Ahmed : It has worked for one year or one and a half. So many question were asked on its account for 1966 and we will see it when the accounts for 1967 are submitted.

श्री पाशाभाई पटेल : माननीय मंत्री ने एक विधेयक प्रस्तुत करने का वचन दिया है जिससे कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को धन देने के बारे में नियम बनाये जायेंगे ।

श्री स० कंडप्पन : नियम नहीं बनाये जायेंगे, प्रतिबन्ध लगाये जायेंगे ।

श्री पाशाभाई पटेल : क्या वह हमारे मित्रों को रूस के अंशदान पर प्रतिबन्ध लगवाना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसका कैंको से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Shri Bibhuti Mishra: When Late Shri Lal Bahadur Shastri was the Prime Minister and was visiting his area then the people had complained to him that there is acute shortage of cement and it is being sold at the rate of Rs. 15, 20 or 25 per bag. Then he pondered over the matter and came to the conclusion that it should be decontrolled and some profit be given to cement producers so that they may increase its production. I had opposed that thing even then. The position today is that cement is available at villages at Rs. 15 or 20 per bag. Hence I would like to know as to how the profit gained by decontrolling the cement has been distributed to different parties?

Secondly, I would like to know the State Government is going to take to see that cement is available to the people at reasonable rates?

अध्यक्ष महोदय : वह ये आंकड़े पहले ही बता चुके हैं । उस समय माननीय सदस्य सभा में उपस्थित नहीं थे । अतः वह कार्यवाही वृत्तान्त से देख सकते हैं । माननीय मंत्री को पुनः आंकड़े दोहराने की जरूरत नहीं ।

Shri F. A. Ahmed : I have already given those figures and I have also said that as far as the question of rural population is concerned we are prepared to supply special quota of cement provided the State Governments choose their nominees to whom the same may be supplied.

अध्यक्ष महोदय : अभी पांच अथवा छ सदस्य और रहते हैं । इस प्रश्न पर पहले ही 35 मिनट लग चुके हैं । अगले 10 मिनट भी इस पर लगाऊंगा । परन्तु मैं यह पूछना चाहता हूं कि हम इस तरह से प्रश्न काल में कैसे काम कर सकते हैं । ऐसी बात नहीं है कि प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण होता है । इससे अध्यक्ष को नुक्सान नहीं होता है बल्कि इस सभा को । मुझे कोई आपत्ति नहीं कि ऐसी ही इच्छा प्रकट की जा रही है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : आप प्रत्येक प्रश्न के लिये अपने विवेक से समय दे सकते हैं । यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो दो अथवा तीन से अधिक प्रश्न नहीं लिये जा सकते ।

श्री स० कुन्दु : माननीय मंत्री के उत्तर से कुछ बातें स्पष्ट नहीं होती हैं। मैं यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री ने कैको संगठन को पूर्णतया समाप्त करने का निश्चय कर लिया है और यदि हां, तो इस समय सीमेंट को सप्लाई करने की क्या व्यवस्था है। दूसरी बात यह है कि मंत्री महोदय ने कहा था कि दो लाख रुपये जन कांग्रेस को दिये गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह राशि किस जन कांग्रेस को मिली। तीसरे, क्या मंत्री महोदय यह भी बतायेंगे कि अधिक धन स्वतंत्र दल को क्यों दिया गया और कांग्रेस दल को नहीं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हमने कैको से पहले ही काम ले लिया है तथा उसे भारत का सीमेंट निगम कर रहा है। कैको द्वारा इस समय कुछ काम नहीं किया जा रहा है।

श्री देवकीनन्दन पटोदिया : इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि भारत का सीमेंट निगम सीमेंट बनाने के मुख्य उद्देश्य से स्थापित किया गया था तथा इस संस्था के ज्ञापन और धाराओं में निहित कुछ उद्देश्यों का संरक्षण लेने में कोई औचित्य नहीं है। अतः क्या मैं जान सकता हूं कि यह संस्था सीमेंट बनाने के मुख्य उद्देश्य से कब स्थापित की गई थी तथा उसे वितरण का काम क्यों सौंपा गया ? दूसरे, मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि उत्पादन से नियंत्रण नहीं हटाना चाहते हैं। अतः क्या मैं जान सकता हूं कि इस बारे में मांग कब कम होती है और उत्पादन कब अधिक होता है और उसका निर्यात किया जाता है तथा वितरण पर नियंत्रण लगाये रखने में क्या औचित्य है और क्या सरकार वितरण पर से नियंत्रण हटाने की बात पर विचार करेगी ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह कहना सही नहीं है कि सीमेंट निगम का उद्देश्य उस सीमा तक सीमित था जो माननीय मंत्री ने बताई है।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मुख्यतः वह।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : निगम का एक उद्देश्य सीमेंट का उत्पादन, निर्माण, उसे तैयार करना साफ करना, खरीदना, बेचना, निर्यात करना तथा आयात करना तथा ऐसे और काम करना था।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : यह तो सामान्य परिभाषा है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है हमने उस पर से नियंत्रण हटा दिया है। जहां तक वितरण का सम्बन्ध है, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं उस पर अभी नियंत्रण इसलिये रखा जा रहा है ताकि वह सभी क्षेत्रों में मिल सके।

श्री वासुदेवन नायर : अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय माननीय मंत्री ने एकाधिपत्यों तथा सीमेंट व्यापारियों के एक बेगुनाह पीड़ित व्यक्ति का दिग्दर्शन कराया है परन्तु मैं उन्हें यह स्मरण कराना चाहता हूं कि संसद् के दोनों सदनों में जब निर्णय किया गया था तो उन्हें यह चेतावनी दी गई थी कि इसके परिणाम भयंकर होंगे। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह लोगों के मन से इस बात को दूर कर सकते हैं कि यह मामला सरकार तथा सीमेंट व्यापारियों के बीच कपट सन्धि का

मामला था तथा क्या वह निष्पक्ष रूप से जांच कराने को तैयार है तथा वह जो सजा दे उसे भुगतने को तैयार है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : किस बात की जांच ? कोई कपटपूर्ण सन्धि नहीं हुई है। अतः इसका प्रश्न नहीं उठता।

श्री जी० एस० रेड्डी : क्या माननीय मंत्री को इस बात का पता है कि विनियंत्रण और मूल्य निर्धारण के बावजूद भी सीमेंट अधिक दामों पर बिक रहा है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

श्री बलराज मधोक : मंत्री महोदय ने कहा है कि हमारे पास आवश्यकता से अधिक सीमेंट है, हम उसका निर्यात कर रहे हैं ताकि आयात तथा सीमेंट निगम द्वारा कुछ और कारखाने खोले जा रहे हैं, आदि। मैं यह जानना चाहता हूं कि नये कारखाने कहां खोले जा रहे हैं तथा क्या सीमेंट के कारखाने खोलने के लिये गैर-सरकारी कम्पनियों को और लाइसेंस दिये जायेंगे ? जब इतना अधिक सीमेंट उपलब्ध है तो इसके क्या कारण हैं कि सरकार उसे समूचे देश में निर्धारित मूल्यों पर बेच नहीं सकती है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : सीमेंट का मूल्य सारे देश में एक समान है। यदि कहीं पर इसकी कमी है तो मैं उसे सीमेंट निगम के ध्यान में लाऊंगा और वह इस बात पर ध्यान देगा कि उस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में सीमेंट उपलब्ध हो। हम उन परियोजनाओं को सीमेंट निगम के अन्तर्गत लाने का विचार कर रहे हैं जहां कच्चा माल उपलब्ध नहीं है तथा जहां सीमेंट के ऐसे कारखाने नहीं हैं ताकि समूचे देश में सीमेंट उपलब्ध हो सके।

रेलवे के गेंज तथा वर्क्स निरीक्षक तथा सहायक निरीक्षक

+

*574 **श्री नम्बियार** : **श्री मोहन स्वरूप** :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : **श्री चक्रपाणि** :
श्री राजा राम : **श्री किंकर सिंह** :
श्री अ० कु० गोपालन : **श्री प्र० न० सोलंकी** :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 से लेकर 10 वर्ष तक की नौकरी पूरी करने के बाद भी विभिन्न रेलों में कई वेंज तथा वर्क्स निरीक्षकों तथा सहायक निरीक्षकों की छटनी की गई है अथवा पदावनति की गई है यद्यपि उन्होंने स्थायी पदालि में काम किया था;

(ख) यदि हां, तो कितने;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन व्यक्तियों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें अन्यत्र नौकरी पर लगाने अथवा उनके लिये विकल्प रोजगारों की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (घ). निर्माणकार्यों के पूरा हो जाने और अस्थायी तथा कार्य प्रभृत पदों (work-charged Posts) के समाप्त कर दिये जाने से वर्ग में परिणामी छटनी के कारण विभिन्न रेलों में कुछ निर्माण निरीक्षकों और सहायक निर्माण निरीक्षकों के पद फालतू हो गये हैं। इनमें से कुछ को समतुल्य अथवा निम्नतर ग्रेड के पदों पर लगाया गया है। जहां ऐसा सम्भव नहीं है, स्थायी कर्मचारियों को, जो उच्चतर ग्रेडों में स्थानापन्न रूप से काम कर रहे थे, उनके मूलपदों पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया है और सीधी भर्ती वाले कनिष्ठतम कर्मचारी फालतू हो गये हैं। उन्हें तकनीकी और गैर तकनीकी कोटियों में, जहां खाली जगहें उपलब्ध हैं, वैकल्पिक नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रक्रिया में यह देखा गया है कि कुछ कर्मचारियों ने वैकल्पिक नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया।

(ख) रेलों से सूचना मंगायी जा रही है और सभा पटल पर एक विवरण रख दिया जायेगा।

(ग) जैसा कि नियमों में निर्धारित है, सीधी भर्ती वाले कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रोन्नत कर्मचारियों को ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता क्योंकि उन्हें उनके अनुभव और उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है।

श्री नम्बियार : क्या सरकार के लिये फालतू हुए लगभग 50 सहायक निर्माण निरीक्षकों को रोजगार देना संभव नहीं है; आखिर, उनकी संख्या बहुत कम है और रेलवे बहुत बड़ा संगठन है ?

श्री परिमल घोष : बहुत-से निर्माण कार्यों तथा परियोजनाओं के पूरा हो जाने के परिणामस्वरूप कुछ सहायक निर्माण निरीक्षकों तथा निर्माण निरीक्षकों के पद फालतू हो गये हैं। धन की कमी के कारण, विकास की गति में भी शिथिलता आ गई है जिससे स्थिति और भी खराब हो गई है। इन सभी कर्मचारियों के लिये अन्यत्र रोजगार की व्यवस्था करने का हर प्रयत्न किया गया है। उन सभी कर्मचारियों को, जिन्होंने वैकल्पिक रोजगार का प्रस्ताव स्वीकार किया है, रोजगार दिया गया है।

श्री नम्बियार : क्या उन कर्मचारियों को जिन्होंने वैकल्पिक रोजगार स्वीकार किया है, भविष्य में सहायक निर्माण-कार्य निरीक्षकों के पद रिक्त होने पर उन पदों पर पुनः लिया जायेगा ?

श्री परिमल घोष : जब कभी सहायक निर्माण कार्य निरीक्षकों के पद रिक्त होंगे, इन लोगों को निश्चित रूप से अवसर दिया जायेगा ?

रेलवे पर दिये जाने वाले भोजन के स्तर का घटिया होता जाना

*575 **श्री स० चं० सामन्त :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि रेलवे के खान-पान विभाग के विभिन्न एककों द्वारा निरन्तर घटिया किस्म का भोजन परोसा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो भोजन की किस्म में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) रेलवे खान-पान विभाग के विभिन्न यूनिटों में खराब किस्म के भोजन के बारे में कभी कभी शिकायतें मिलती हैं।

(ख) प्रत्येक विशिष्ट शिकायत की जांच करने और उपचारी कार्रवाई करने के अलावा भोजन की किस्म में सुधार करने के लिये जो दूसरी कार्रवाइयां की जाती हैं वे आमतौर पर इस तरह हैं :—

(i) खान-पान यूनिटों में काम करने वाले रसोइयों और दूसरे कर्मचारियों का समुचित प्रशिक्षण;

(ii) खान-पान यूनिटों में आधुनिक उपस्कर और सामान की व्यवस्था;

(iii) भोजन बनाने के लिये अपेक्षित अच्छी किस्म के कच्चे सामान की खरीद; और

(iv) कर्मचारियों के काम के पर्यवेक्षण में कड़ाई

श्री स० च० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि आचार्य जी० भा० कृपालानी की अध्यक्षता में रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति ने रेलवे में भोजन व्यवस्था के बारे में पूरी तरह जांच की थी और विभागीय खान-पान यूनिटों तथा गैर-सरकारी ठेकेदारों द्वारा दिये जाने वाले भोजन की किस्म में सुधार के बारे में कुछ उपाय सुझाये थे ? उन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ? रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री की अध्यक्षता में भोजन-व्यवस्था सम्बन्धी एक समिति हाल में बनाई गई थी क्या वह भी इन सिफारिशों पर विचार कर रही है।

श्री परिमल घोष : विभागीय भोजन व्यवस्था के सम्बन्ध में इस प्रश्न को और भी कई माननीय सदस्य पहले उठा चुके हैं। इस बारे में जो कुछ भी सिफारिशें की गई हैं रेलवे उन्हें क्रियान्वित कर चुकी है। फिर भी भोजन की किस्म तथा विभागीय भोजन-व्यवस्था की सेवा में और अधिक सुधार करने की दृष्टि से एक समिति बनाई गई थी उसने इस मामले पर विचार किया है और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं जिन पर सरकार विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हो चुका है अल्प सूचना लेने से पहले में सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रश्न-काल में प्रति दिन कम से कम छः प्रश्न समाप्त करना चाहता हूं अतः हम एक प्रश्न को 10 मिनट से अधिक समय नहीं दे पायेंगे इसलिये सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस सम्बन्ध में सहयोग दें।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्रियों को भी ठीक उत्तर देने का अनुदेश दीजिये।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

पेंसिलीन के टीके के कारण एक लड़की की मृत्यु

+

अ० सू० प्र० 7. श्री मनूभाई पटेल : श्री देवेन सेन :
श्री म० ला० सोंधी : श्री महन्त दिग्विजय नाथ :

क्या **स्वास्थ्य परिवार नियोजन एवं नगरीय** विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 3 मार्च, 1968 को नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना के एक डाक्टर द्वारा पैंसलीन का टीका लगाये जाने से जगजीत कौर नामक एक लड़की की मृत्यु हो गई थी ;

(ख) यदि हां तो क्या टीका गलत लगाया गया था या पैंसिलीन के टीके के निर्माण में कुछ त्रुटि थी ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी हां रोगिणी की मृत्यु 2-3-1968 को हुई।

(ख) और (ग) पांच दिन के इलाज के दौरान यह चौथा पैनिसिलीन इंजैक्शन था और रोगी पर इसकी प्रतिक्रिया की जांच करने के बाद ही इसे लगाना शुरू किया गया था। चौथे इंजैक्शन से प्रतिक्रिया हुई। इस प्रतिक्रिया को दूर करने के लिए आवश्यक पूरा-पूरा इलाज किया गया था। पैनिसिलीन इंजेक्शनों का वह बैच जिससे यह इंजैक्शन लगाया गया था जांच के लिए रोक लिया गया है।

श्री मनुभाई पटेल : क्या ऐसी कोई स्थायी हिदायत है कि पैंसिलीन का टीका केवल डाक्टरों द्वारा लगाया जाये और न कि नर्सों द्वारा ? क्या यह टीका एक नर्स द्वारा लगाया गया था, उसके बाद यह बताया गया कि डाक्टर टीका नहीं लगा सका यद्यपि डाक्टर आया और उसने इसे इतना गंभीर मामला नहीं समझा और वहां आक्सीजन सिलिन्डर जैसा आपात उपकरण भी नहीं था ?

श्री सत्यनारायण सिंह : यह सच है कि ऐसे अनुदेश दिये गये हैं कि डाक्टर की उपस्थिति में अर्हता-प्राप्त नर्स पैंसिलीन का टीका लगा सकती है इस मामले में उपरोक्त हिदायत के अनुसार तीन टीके दिये गये थे।

श्री मनुभाई पटेल : किसके द्वारा ?

श्री सत्यनारायण सिंह : डाक्टर की उपस्थिति में नर्स द्वारा दो टीकों के बाद उस (रोगी) पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ा था। जो डाक्टर उसका इलाज कर रहा था उसने उसकी हालत में सुधार होते देखा। इसलिये उसने पैंसिलीन के दो और टीके लगाने का सुझाव दिया। तीसरा टीका भी डाक्टर की उपस्थिति में दिया गया। दुर्भाग्यवश, जब चौथा टीका लगाया जाना था, प्रभारी डाक्टर किसी के घर रोगी देखने चला गया। इस लड़की ने उस नर्स से, जिसने पहले तीन टीके लगाये थे आग्रह किया और कहा कोई बात नहीं। "आप तीन टीके तो लगा चुकी हैं। मुझे

जल्दी है। श्राप मुझे यह टीका भी जरूर लगा दीजिये।" इसलिये डाक्टर की गैर-मौजूदगी में चौथा टीका लगा दिया गया। **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। कई माननीय सदस्य बैठ रहे हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं। मंत्री जी के लिये ऐसी स्थिति में उत्तर देना संभव नहीं होगा। उन्हें पूछे गये प्रश्न का उत्तर देने दीजिये और उसके बाद मैं सदस्यों को एक-एक करके अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दूंगा।

श्री सत्यनारायण सिंह : मैं तथ्य पेश कर रहा हूं। मैं वास्तविक घटना का ब्यौरा दे रहा हूं। जब चौथा टीका लगाया गया, तो उसकी प्रतिक्रिया बुरी हुई। तुरन्त कृत्रिम रूप से श्वास दिया गया। इस बीच डाक्टर भी आ गया और यथासंभव जो कुछ हो सकता था किया गया। इस बीच अस्पताल-गाड़ी (ऐंम्बुलैंस) मंगाई गई और एम्बलैंस के पहुंचने से पहले उसकी मृत्यु हो गई।

इसके साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमने नर्स को निलम्बित कर दिया है। सभा को एक बात महसूस करनी चाहिए। उसी स्टाक से रोगियों को पैंसिलीन के सैकड़ों टीके गये। इस मामले में भी तीन टीके लगाने तक उसकी हालत में सुधार होना गया। लेकिन चौथा टीका अन्यथा सिद्ध हुआ। मैं समझता हूं यह उसके भाग्य की बात थी, और मैं क्या कह सकता हूं।

श्री मनुभाई पटेल : माननीय मंत्री जी ने कहा कि चूंकि डाक्टर अनुपस्थित था और रोगी के अनुरोध पर नर्स ने उसे टीका लगाया था। इस बात का फैसला रोगी को तो नहीं करना है कि टीका डाक्टर लगाये या नर्स। फिर, केवल नर्स को ही क्यों दण्डित किया जाये? डाक्टर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? इसके बाद, फिर, आक्सीजन सिलिन्डर उपलब्ध नहीं था और कृत्रिम श्वास दी गई; उनका मंत्रालय, उस डाक्टर, इस व्यवस्था तथा अनिवार्य स्वास्थ्य योजना के विरुद्ध, जो इतनी अधिक दोषपूर्ण है, क्या कार्यवाही कर रहा है? क्या वह कोई जाँच करा रहा है जैसा कि उसने आम अस्पतालों के मामले में किया है?

श्री सत्यनारायण सिंह : जहाँ तक आक्सीजन सिलिन्डर का सम्बन्ध है, वह वहाँ उपलब्ध था। जो कुछ संभव था, किया गया। जहाँ तक डाक्टर के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न है, वह उस समय वहाँ उपस्थित नहीं था, किसी रोगी को देखने बाहर गया हुआ था।

श्री म० ला० सोंधी : दिल्ली में डाक्टर लोहिया की मृत्यु के पश्चात् ऐसी धारणा बन गई है कि दिल्ली में चिकित्सा सेवाएं, विशेषतः आपात् चिकित्सा सेवाएं, अव्यवस्थित, असुरक्षित तथा अपर्याप्त हैं। पेंसिलीन के टीकों की अधिकतर जो प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है, उसे निष्प्रभावी करने तथा रोगी को उसके प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिये हमारे अस्पतालों में क्या व्यवस्था की गई है?

श्री सत्यनारायण सिंह : मैं माननीय सदस्यों से एक बात महसूस करने का अनुरोध करूंगा इस मामले में, जैसा कि मैं बता चुका हूं, पहले तीन टीकों से उसे फायदा हुआ। इसलिये डाक्टर ने उसे चौथा टीका देने का सुझाव दिया। उस टीके के बाद उस पर उसकी प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर, वे सभी दवाइयाँ दी गईं जो ऐसे मामलों में दी जाती हैं। आक्सी-जन दिया गया और कृत्रिम श्वास दी गई। बावजूद इन सभी पूर्वोपायों के रोगी की मृत्यु हो गई

यह सारी घटना केवल 20 मिनट में हो गई। हर संभव प्रयत्न किये जाने के बाद भी वह बच नहीं सकी और जब मौत आती है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं रोक सकती।

Shri Deven Sen : I want to know whether any big doctor came there within 20 minutes; whether it is a fact that no big doctor was available there and Shri Sarkar, the only doctor who came there went back just after examining her pulses saying that she was not his patient and it was the case of the lady doctor.? May I know whether it is further a fact that no information was given to the police and the police on their part did not register the case when the parents of the deceased went to them for lodging the report? As it also a fact that the nurse has been suspended despite the fact that the doctor was responsible for all what had happened? May I know whether an enquiry will be instituted with a view to fix responsibility and punish the guilty?

Shri Satya Narayan Sinha : I have already stated that in this case the patient had already been given three penicillin injections previously and she was reacting very favourably. But after the fourth injection which proved otherwise, her condition became worse and she reacted adversely. So far as the availability of the doctors in the meantime is concerned, Dr. Miss Arora who had gone on a domiciliary visit had reached these within ten minutes.

Shri Mahant Digvijai Nath : I want to know whether is it a fact that the nurse who has been suspended was forced to write that the patient had requested her to give her that injection, and whether it is also a fact that Dr. Sarkar who came there had stated that he would not attend to the patient as it was the case of the Lady Doctor?

Shri Satya Narayan Sinha : Sir, I am sorry to say that so far as these allegations are concerned. I am not in a position to say anything about them at the moment as I am not in the know of the facts. However, as they have made these allegations, I will certainly enquire into the matter and find out the viracity thereof.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि रोगी को उसी बैच से तीन टीके पहले लग चुके थे, इसलिये चौथा टीका देने से पहले परीक्षण करना आवश्यक नहीं समझा गया। मैं जानना चाहती हूं इस सम्बन्ध में स्थायी हिदायतें क्या हैं। एक बार में समूचे बैच का परीक्षण करना जरूरी होता है या रोगी को टीका लगाने से पहले प्रत्येक इंजैक्शन का परीक्षण करना आवश्यक होता है?

श्री सत्यनारायण सिंह : पहला इंजैक्शन देते समय सुग्राह्यता-परीक्षण (सेंसिटिविटी टैस्ट) किया जाता है। यदि कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं होती, तो उस स्थिति में आगे परीक्षण की आवश्यकता नहीं समझी जाती।

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, a large number of cases of this nature take place in the capital every month although, only one or two are reported in the Press. The Statement of the Minister that no amount of precaution could save her life is an encouragement to the negligence of the doctors and nurses. This is a dangerous statement. I want to ask the hon. Minister what suggestions and steps have been recommended in their report, already submitted to the Government, to avoid recurrence of such cases by the Committed which was appointed to go into the working of the general Hospitals in the capital as also the causes of the death of Dr. Lohia.

अध्यक्ष महोदय : यह पूर्णतया एक भिन्न प्रश्न है। इसके बाद इस तरह के बहुत-से प्रश्न पूछे जायेंगे। नहीं, नहीं। डा० मैत्रेयी बसु।

डा० मैत्रेयी बसु : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि सुग्राह्यता के सम्बन्ध में कैसा परीक्षण किया जाता है। "सुग्राह्यता" (सेंसिटिवीटी) से उनका मतलब, मैं समझता हूं,...... (एलर्जी) से है। नये रोगी को इस औषधालय में पेंसिलीन का पहला इंजैक्शन देने से पहले क्या परीक्षण किया जाता है? यह मेरा पहला प्रश्न है।

दूसरा प्रश्न मेरा यह है--बीमार तो अब मर चुका। उसकी ओर क्या ध्यान दिया गया। क्या नलियों का परीक्षण किया गया था? क्या सिरीन्ज तथा इंजैक्शनों के समुचे बैच का परीक्षण किया गया था?

श्री सत्यनारायण सिन्हा : जैसा कि मैं बता चुका हूं, पेंसिलीन का समूचा बैच, जिसमें से वह टीका लगाया गया था, रख लिया गया है और परीक्षण के लिये भेजा गया है। जहां तक सिरीन्ज का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं, उसे अवश्य ही शुद्ध (स्टेरिलाइज़) किया गया होगा...... (अन्तर्बाधाएं)

Shri D. N. Tewary : One hon. Member of this House had died immediately after he was given a penicillin injection he died within five minutes and the enquiry into the matter revealed that a batch of injections, even if the sample of the stock stands tested, could contain defective injections. I want to know whether it is not necessary to test each and every ampoule or injection before it is given to the patient with a view to avoiding its adverse reaction, if any.

Shri Satya Narayan Sinha : It is true that this incident took place 4 or 5 years ago and the member died. As I have said, hundreds of injection of penicillin are given to patients out of batch every day. So far as the case in question is concerned, the entire batch of penicillin out of which this injection was given has been impounded and sent for test. It will be known only after completion of the enquiry whether it was defective and if so, to what extent.

श्री प्र० के० देव : पेंसिलीन की जब प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है तो उस हालत में तुरन्त एन्टीटोड, एड्रेनालीन दिया जाना चाहिए। मंत्री महोदय के उत्तर से मालूम हुआ है कि ऐम्बुलैंस बुलाई गई थी, जिसका मतलब यह है कि उस डाक्टर के पास, जो वहाँ गया, एन्टीटोड नहीं था। यदि ऐसी बात थी, तो पेंसिलीन का इंजैक्शन दिये जाने के बाद कितने समय बाद एन्टीटोड दिया गया था और विलम्ब का क्या कारण था?

श्री सत्यनारायण सिन्हा : जैसा मैं बता चुका हूं, सभी एन्टीटोड्स दिये गये थे, लेकिन ऐम्बुलैंस इसलिये बुलाई गई थी कि रोगी को विलिंग्डन अस्पताल भेजना बेहतर समझा गया, क्योंकि वहाँ रोगी को होश में लाने वाली मशीन उपलब्ध है जो सभी औषधालयों में उपलब्ध नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Industrial Policy of Orissa

*569. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Orissa have announced their industrial policy in the State Legislative Assembly on the 22nd February, 1968 which envisages various concessions to the industrialists with a view to attracting private investment; and

(b) if so, the details thereof and Government's reaction thereto ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) and (b): A statement will be laid on the Table of the House as soon the information in respect of part (a)of the Question is received from the Government of Orissa.

Running of Special Trains for Annual Session of Bhartiya Jana Sangh at Calicut

*571. **Shri O.P. Tyagi :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a special train for the last Annual Session of Jana Sangh held at Calicut was deliberately delayed by the Railway authorities and as a result of which the Ministers and other distinguished persons of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh who were travelling by that train could not participate in the Session held on the 28th December, 1967.

(b) whether it is also a fact that a coal engine instead of a diesel engine was used for hauling the special trains; and

(c) if so, whether Government propose to enquire into the matter?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) No, Sir.

(b) It was made clear to the sponsors of the special that it would be worked by steam power. In spite of this, out of the total run of about 3000 Kms. from New Delhi to Calicut, the special train was hauled by diesel locomotives for about 2125 Kms. and steam locomotives for about 875 Kms.

(c) The matter has been investigated and a statement showing the detentions of this train with reasons therefor is laid on the Table of the Sabha. [Placed in Library *see* No. LT-428/68]

पटसन के सामान पर निर्यात शुल्क

*572. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पटसन मिल्ज संस्था ने पटसन की वस्तुओं के निर्यात शुल्क में हाल ही में की गई कमी के बारे में असंतोष व्यक्त किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त कमी के बावजूद पटसन की बनी भारतीय वस्तुएं विदेशी बाजारों में सस्ती पाकिस्तानी वस्तुओं से प्रतियोगिता नहीं कर सकतीं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या अग्रेतर कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) पता लगा है कि पाकिस्तान ने पटसन के माल के निर्यात के लिये दिये जाने वाले प्रोत्साहनों को और भी बढ़ा दिया है । सरकार स्थिति पर निरन्तर विचार करती रहती है ताकि यथावश्यक कदम उठाये जा सकें ।

मुग़लसराय स्टेशन से माल की चोरी

*576 **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** **श्री ना० स्व० शर्मा :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : **श्री कंवरलाल गुप्त :**
श्री सीताराम केसरी : **श्री बाल्मीकि चौधरी :**
श्री क० प्र० सिंह देव : **श्री यशपाल सिंह :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 फरवरी, 1968 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आरोप के समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि मुगलसराय स्टेशन पर रेलवे मालडिब्बों

से प्रतिदिन 1 लाख रुपये के माल की चोरी हो रही है और जिसे स्थानीय बाजार में बेचा जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस नगर की कोयले की पूरी आवश्यकता रेलवे यार्ड से चोरी के जरिये पूरी होती है ;

(ग) क्या हाल में इस यार्ड से एक पूरे माल-डिब्बे में लदे सिगरेटों की चोरी हुई थी लेकिन इस मामले में कोई विस्तृत जांच नहीं की गई थी ;

(घ) क्या रेलवे पुलिस वहां इन चोरियों को रोकना तो दूर की बात रही, सह-अपराधियों के रूप में काम करती है; और

(ङ) यदि हां, तो रेलव तथा रेल प्रयोक्ताओं को इतने बड़ पैमाने पर हो रहे नुकसान को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : जी हां। लेकिन स्थिति वैसी नहीं है जैसी कि समाचार-पत्र में बतायी गयी है। 1967 में मुगलसराय की सरकारी रेलवे पुलिस ने मुगलसराय स्टेशन पर माल डिब्बों से माल की चोरी के 18 मामले दर्ज किये थे जिनमें 8,983 रुपये 30 पैसे की सम्पत्ति चोरी हुई थी जब कि 1966 में ऐसे 50 मामले दर्ज किये गये थे जिनमें 27,507 रुपये की सम्पत्ति चोरी हुई थी। पुलिस द्वारा की गयी जांच के परिणामस्वरूप 1967 में 32 और 1966 में 21 आदमी पकड़े गये थे।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं। सही स्थिति यह है कि वाडी बन्दर (बम्बई) से वाराणसी को एक माल डिब्बा बुक किया गया था जिसमें पनामा सिगरेट के 99 पैकेज लदे थे। ऐसा दिखायी पड़ता है कि जब यह माल डिब्बा वाराणसी यार्ड में खड़ा था तब उसके साथ छेड़-छाड़ की गई और धोखा-धड़ी से उसे पंजाब स्थित चिहेरू रेलवे स्टेशन को भेज दिया गया। अंत में जब माल डिब्बे को वहां खोला गया और उसकी जांच की गयी तो उसमें माल नहीं पाया गया। इस मामले की जांच सरकारी रेलव पुलिस, मुगलसराय के सेक्शन अफसर द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 / 479 के अन्तर्गत अपराध संख्या 228 के रूप में की गयी।

(घ) जी नहीं।

(ङ) अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए कई निरोधात्मक उपाय किये जा रहे हैं, जैसे भरे हुए मुहरबंद डिब्बों की रखवाली करना, जिन जगहों पर चोरियां होती हैं वहां सशस्त्र पहरा लगाना, अपराध सम्बन्धी आसूचना इकट्ठी करना, और जाने-पहचाने संदिग्ध व्यक्तियों और अपराधियों पर निगरानी रखना।

री-रोलिंग मिलें

*577. श्री द० रा० परमार : श्री रा० कि० अमीन :
श्री रामचन्द्र ज० अमीन : श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत-सी री-रोलिंग मिलों में निर्मित वस्तुओं का बहुत सा माल जमा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सरकार को री-रोलिंग मिलों में निर्मित वस्तुओं का स्टाक जमा हो जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे में स्वचालित मशीनों का प्रयोग

*578. श्री नम्बियार : श्री अनिरुद्धन :
श्री चक्रपाणि : श्री वि० कु० मोडक :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 जनवरी, 1968 को चित्तरंजन में अपने संवाददाता सम्मेलन में रेलवे मंत्री ने यह संकेत दिया था कि रेलवे में स्वचालित मशीनें लगाने तथा आधुनिकीकरण योजना लागू करने के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह संसद् में और रेलवे कर्मचारियों के विभिन्न प्रतिनिधि-मण्डलों को किये गये आश्वासन के विरुद्ध नहीं है कि स्वचालित मशीनों के प्रयोग के परिणामस्वरूप किसी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जायेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Manufacture of Tractors

*579. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of tractors and power tillers manufactured and sold in the country last year and the profitable figures of production and sale during the current year ;

(b) whether it is a fact that the tractors manufactured in the country are costlier than the imported ones; and

(c) if so, the reasons therefor and the efforts being made to bring down their prices?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :

(a) The figures for production and sale of indigenous tractors and power tillers during the year 1967 are as under :—

	Production Nos.	Sale Nos.
(i) Tractors	10,526	10,329
(ii) Power tillers	264	128

During the year 1968, the production and sale of tractors and Power tillers is likely to be as under :

(i) Tractors	15,000	15,000
(ii) Power tillers	500	400

(b) Yes.

(c) The cost of indigenous tractors is higher for various reasons such as high cost of imported and indigenously bought out components, high cost of raw materials, higher over-heads and other charges on account of the low volume of production, incidence of customs/excise duty on certain components/raw materials, etc.

In order to bring down the cost of production, the indigenous manufacturers are being encouraged to increase production to the maximum extent possible.

In order to determine the fair selling prices of tractors manufactured in the country, a cost examination of the manufacturing units was undertaken by the Government Cost Accounts Officers. On the basis of these recommendations the selling prices of all makes of tractors currently under production in the country were notified under the Essential Commodities Act, 1955. As a second check, the Tariff Commission was also requested to make a formal enquiry and recommend reasonable selling prices. The report of the Commission has been received and is under examination.

उड़ीसा में एक पटसन मिल का स्थापित किया जाना

†580. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री का० रा० सिंह देव :
श्री दे० अमात :
श्री गु० चं० नायक :
श्री म० शास्त्री :
श्री धीरेन्द्रनाथ देव :
श्री प्र० वीपा :
श्री जेना :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में एक पटसन मिल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार को मिला है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उड़ीसा में पैदा होने वाली पटसन की किस्म और मात्रा एक से अधिक पटसन मिल के लिये काफी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तुत दावे को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार ने दिसम्बर, 1965 में, उस राज्य में 600 करघों की क्षमता वाले एक सहकारी पटसन मिल की स्थापना के लिये एक प्रस्ताव रखा था। उड़ीसा राज्य में लगभग 3–4 लाख गांठ पटसन तथा मेस्टा पैदा होता है। पटसन उद्योग की विद्यमान क्षमता और चौथी योजना के समस्त लक्ष्यों पर सविस्तार विचार करने के उपरान्त सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि नयी संयुक्त मिलों की स्थापना में चालू मूल्यों के हिसाब से पर्याप्त धन लगेगा, अतः उनकी स्थापना करना इस समय वांछनीय नहीं है। इन परिस्थितियों में नए मिलों की स्थापना करना, विशेषतः सरकारी धन से, विवेकपूर्ण विचार नहीं माना गया। उड़ीसा सरकार को इस निर्णय की सूचना दी गई तथा उन्हें कहा गया कि राज्य में सहकारी पटसन मिल की स्थापना के प्रस्ताव को छोड़ दें। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को पुनः नहीं भेजा है।

हरिद्वार में हैवी इलेक्ट्रिकल प्लांट

*581. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री अम्बचेजियान :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के बिजली उद्योग उप-मंत्री की अध्यक्षता में एक बारह-सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने हरिद्वार स्थित हैवी इलैक्ट्रिकल प्लांट को शीघ्र पूरा करने के उपायों का अध्ययन करने के लिये उसका दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो उस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिये उस दल ने क्या उपाय सुझाए हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) जी, हां। रूस से विद्युत् उद्योग उप मंत्री की अध्यक्षता में 13 सोवियत विशेषज्ञों के एक दल ने हरिद्वार स्थित हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट का उसकी उत्पादन सम्बन्धी समस्याओं की जांच करने और विभिन्न भारी विद्युत् संयंत्रों में उत्पादन को युक्तिसंगत किये जाने के मामले में विचार-विमर्श करने के लिए दौरा किया था। दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

मोटर गाड़ियों के पुर्जों का निर्माण

*582. **श्री रा० बरुआ :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विभिन्न राज्यों में मोटर गाड़ियों का प्रयाग बढ़ रहा है, विभिन्न राज्यों में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में मोटर गाड़ियों के पुर्जे बनाने वाले कारखाने स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या ऐसे किसी निर्माण कारखाने को स्थापित करने की किसी राज्य की पेशकश पर उस राज्य को ऐसा करने की सुविधायें देने का सरकार का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) इस क्षेत्र में और अधिक संयंत्र लगाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसर्स भारत बैरल कम्पनी

*583. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स भारत बैरल कम्पनी का नाम अब काली सूची से निकाल दिया गया है ;

(ख) क्या ऐसा उच्च न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप किया गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस फर्म को भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिये कहा गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफैक्चरिंग कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड को काली सूची में रखने का तारीख 25 जनवरी 1964 का आदेश 23–6–66 से भूतपूर्व पंजाब उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन करते हुए आस्थगित कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं ।

Import of Groundnut and Groundnut Oil by France

*584. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that France has removed all restrictions on the import of groundnut and its oil from India ;

(b) whether it is also a fact that a French delegation, which visited India recently, has negotiated about the import of groundnut and groundnut oil from India ; and

(c) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) The French Government has lifted restrictions on import of groundnut kernel and oil from 12th January, 1968.

(b) No official French Delegation has visited India recently to negotiate the import of the groundnut and groundnut oil from India.

(c) In view of a good groundnut crop this year, Government have released substantial quantities of H.P.S. variety of groundnut kernel for export.

व्यापारिक मोटर-गाड़ियों का निर्माण

*585. **श्री रानेन सेन :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967 में व्यापारिक मोटर-गाड़ियों का निर्माण कम हुआ है था;

(ख) यदि हाँ, तो उत्पादन कितना कम हुआ था ;

(ग) उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) व्यापारिक मोटर गाड़ियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हाँ ।

(ख) 1967 में वाणिज्यिक गाड़ियों का उत्पादन 31,462 हुआ जब कि 1966 में यह संख्या 35,159 थी।

(ग) वाणिज्यिक गाड़ियों के उत्पादन में कमी माँग गिर जाने के कारण हुई ।

(घ) वाणिज्यिक गाड़ियाँ खरीदने के लिए बैंक द्वारा अग्रिम राशि पर लगाये गये प्रतिबन्ध में छूट दे दी गई है । यह कदम अन्य वित्तीय उपायों के साथ साथ सरकार द्वारा अर्थ व्यवस्था को पुन: कायम करने की दृष्टि से उठाया गया है । इससे वाणिज्यिक गाड़ियों की माँग बढ़ जाने के कारण उनका उत्पादन बढ़ जाने की आशा है ।

ऊन के आयात के लिये नियतन

*586. **श्री मधु लिमये** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय ने अक्तूबर, 1967 से सितम्बर, 1968 तक की अवधि में ऊन के आयात के हेतु उन के मंत्रालय को 12 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि अक्तूबर, 1967 से मार्च, 1968 तक की अवधि के लिये अब तक इस उद्योग को इस नियतन में से केवल 6 करोड़ रुपये की राशि दी गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ऊन उद्योग को वार्षिक आधार पर नियतन करने की पिछले दो वर्षों से उनके मंत्रालय की प्रथा रही है ;

(घ) यदि हाँ, तो चालू वर्ष में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या 6 करोड़ रुपए की शेष राशि चालू वर्ष की दूसरी छमाही में दे दी जायेगी?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) से (ङ). अक्तूबर, 1967 से मार्च, 1968 तक की अवधि के लिए वित्त मंत्रालय ने ऊन के आयात के लिए 6 करोड़ रु० का नियतन किया था तथा उद्योग को इसी अवधि के लिए यह राशि दे दी गई है। चूंकि विदेशी मुद्रा का नियतन केवल छः महीनों की अवधि के लिए हुआ था इसलिए उद्योग को वार्षिक आधार पर लाइसेंस नहीं दिए जा सके। उद्योग को अप्रैल, 1968 से सितम्बर, 1968 1968 की अवधि के लिए नियतन शीघ्र ही घोषित किया जायेगा ।

सरकारी क्षेत्र के तीन इस्पात कारखानों में लगी पूंजी

*587. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर, रूरकेला और भिलाई स्थित इस्पात कारखानों में से प्रत्येक में अब तक कुल कितनी पूंजी लगाई जा चुकी है ;

(ख) इन में से प्रत्येक कारखाने को अब तक कितना अतिरिक्त ऋण दिया जा चुका है ;

(ग) इन में से प्रत्येक कारखाने को उस की स्थापना से अब तक की अवधि में कितनी हानि हुई है ; और

(घ) प्रत्येक मामले में ऐसी हानि होने के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) सरकार द्वारा दी गई धन-राशि (ईक्विटी और ऋण) के आधार पर 31-3-1967 को दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई इस्पात कारखानों में लगाई गई कुल पूंजी निम्नलिखित थी :—

	(मिलियन रुपये)
दुर्गापुर इस्पात कारखाना .	2467
राउरकेला इस्पात कारखाना . . (उर्वरक कारखाने को निकाल कर)	3390
भिलाई इस्पात कारखाना . . .	3291

(ख) वर्ष 1966-67 तक कोई अतिरिक्त ऋण नहीं दिये गये हैं।

(ग) 31 मार्च, 1967 तक प्रत्येक कारखाने का कुल घाटा इस प्रकार था :—

	(मिलियन रुपये)
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	325.82
राउरकेला इस्पात कारखाना . . . (उर्वरक कारखाने को निकाल कर)	288.47
भिलाई इस्पात कारखाना . . .	92.04

(घ) हानि के भिन्न भिन्न और कई कारण हैं। इन में से कुछ मूल कारण हैं और कुछ अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग हैं। मूल कारणों में एक बात यह है कि इस्पात उद्योग को लाभप्रद बनने के लिए बड़ा लम्बा समय लगता है और इकाइयों का उत्पादन आरम्भ करने के पश्चात् निर्धारित क्षमता तक पहुंचने में समय लगता है, पूंजीगत लागत अधिक होती है, एक मिलियन टन स्तर पर और क्षमता के लिए रखी गई गुंजाइश पर किया गया व्यय (जिस गुंजाइश का वर्तमान विस्तार कार्यक्रम में उपयोग किया जाएगा), बस्तियों पर होने वाला भारी खर्च जिन में शिक्षा, चिकित्सा और अन्य सुविधाओं पर होने वाला खर्च भी शामिल है, सम्बन्धित पूंजीगत व्यय और वर्तमान मूल्य-ढांचा, जो कैपिटल ब्लाक के बहुत निम्न स्तर पर आधारित है, शामिल है। वर्ष 1966-67 में हानि के मुख्य कारण निम्नलिखित थे :

(1) बाज़ार में इस्पात की माँग का कम होना जिस से 1965-66 की तुलना में कम्पनी की कुल बिक्री में 78 मिलियन रुपये की कमी हुई।

(2) बाज़ार में मन्दी आ जाने के कारण कम्पनी को अपने उत्पादन में फेर-बदल करना पड़ा और मध्यवर्ती वस्तुओं को अपेक्षाकृत अलाभकर दामों पर बेचना।

(3) कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि।

(4) अवमूल्यन के पश्चात् आयात किये जाने वाले सामान और पुर्जों की कीमत में में वृद्धि।

(5) कुछ कारखानों जैसे राउरकेला का सिंटरिंग संयंत्र और पूर्णपानी की चूना पत्थर की खान और दुर्गापुर इस्पात कारखाने में काम ओवन में खराबी/कांबमिंग होना।

Small Car Project and other Industrial Schemes in Madhya Pradesh

*588. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have submitted certain schemes to the Central Government with regard to the establishment of small car project and other industrial schemes including those regarding cement factories in the state ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) to (c) So far as Small Car project and Cement factories are concerned, no scheme has been received from the Government of Madhya Pradesh. It is, however, not necessary now for any party to approach the Government of India for licence to undertake manufacture of cement.

As regards other industrial schemes, the information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Railway Service Commission on S. E. Railway

***589. Shri Lakhan Lal Gupta :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any Railway Service Commission has been set up for making appointments of staff on the South Eastern Railway ;

(b) if so, the names of its members and since when they have been working as Members ;

(c) whether any non-official member of Madhya Pradesh has been included in the aforesaid Railway Service Commission ; and

(d) if not, for how many years any resident of Madhya Pradesh has not been appointed on the Commission ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes, Sir. The Railway Service Commission at Calcutta recruits staff for South Eastern and Eastern Railways, Chittaranjan Locomotive Works and Railway Electrification ;

(b) The Chairman of the Commission is Shri P. C. Vaish. The post of Member is vacant ;

(c) No, Sir ;

(d) Chairman and Members of Railway Service Commissions are appointed on the recommendation of the Union Public Service Commission and are not selected on a regional basis.

घाटे पर चलने वाली कपड़ा मिलें

***590. श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन घाटे पर चलने वाली सूती कपड़ा मिलों की कोई सूची तैयार कर ली है, जिन्हें वह सूती कपड़ा (उपक्रमों का प्रबन्ध तथा समापन) अधिनियम, 1968 के उपबन्धों के अनुसरण से अपने हाथ में लेगी ;

(ख) क्या ऐसे मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिये आवश्यक वित्तीय तथा संगठनात्मक व्यवस्था कर ली गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें सरकार द्वारा कब तक अपने हाथ में लिया जा सकता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) ऐसा अनुमान है कि "घाटे पर चलने वाली सूती कपड़ा मिलों" से माननीय सदस्य का आशय उन सूती कपड़ा मिलों से है जो वित्तीय तंगी के कारण अथवा अकुशल प्रबन्ध के कारण कठिनाई में हैं। सूती कपड़ा कंपनियां (उपक्रमों का प्रबन्ध तथा परिसमापन अथवा पुनर्स्थापन) अधिनियम, 1967 में केवल उन्हीं मिलों को लेने की व्यवस्था है जिनका प्रबन्ध पहले ही उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हो रहा है अथवा जो इसके पश्चात् उस अधिनियम के अन्तर्गत हाथ में ली

जायें । ऐसी मिलों के मामलों पर उन के परिसमापन अथवा पुनर्स्थापन के उद्देश्य से, 1967 के अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विचार किया जायेगा । शीघ्र ही एक वस्त्र निगम की स्थापना की जाने वाली है जो उन मिलों का प्रबन्ध करेगा जिन्हें उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत सरकार अधिकार में ले । अन्य व्यौरों पर विचार हो रहा है ।

कच्चे लोहे का उत्पादन

*591. **श्री दामानी :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कच्चे लोहे के बहुत से भावी उत्पादकों ने अपने लाइसेंस और आशय-पत्र वापिस दे दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं, और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) हाल में कच्चे लोहे के उत्पादन की तीन योजनाओं का परित्याग किया गया है । एक मामले में कम्पनी ने अन्य कारणों के साथ एक कारण यह भी बताया है कि देश में वातावरण उत्साहजनक नहीं है । शेष दो मामलों में सम्बन्धित कारखानादारों को देशीय उपकरणों का प्रयोग करने में संकोच था जिस के लिए सरकार ने शर्त लगा रखी है । संभवत: कच्चे लोहे की वर्तमान अधिक उपलब्धि का भी उनके निर्णयों पर प्रभाव पड़ा है ।

(ग) ऐसी आशा की जाती है कि इन योजनाओं को क्रियान्वित न करने से कच्चे लोहे की सामान्य उपलब्धि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वर्तमान और निकट भविष्य में मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है ।

Translators at UNCTAD II

*592. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Chandra Shekar Singh :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is only one Indian national among the persons appointed for translating the speeches made in different languages at UNCTAD II ;

(b) whether it is also a fact that there is no provision for translating the speeches into Hindi at the said Conference ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) Only one Indian national has been accepted as suitable to act as translator by the U.N. authorities in replacement of a regular staff member.

(b) and (c) No provision has been made by the UNCTAD for translation into Hindi, as it is not one of the languages recognised by the United Nations for their official work.

लघु उद्योग क्षेत्र

*593. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योग क्षेत्र में "पूंजी निर्माण" को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या सरकार ने जापान की तरह की विद्युत्-संचालित लघु उद्योग स्थापित करने के लिए तकनीकी परामर्श तथा अन्य सुविधायें देने की योजनाएं आरम्भ की हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं पर नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) स्टेट बैंक आफ इण्डिया के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा किश्त ऋण योजना की शर्तों के अधीन किराया खरीद के आधार पर मशीनें प्राप्त करना लघु औद्योगिक क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से पूंजी निर्माण करने की दिशा में सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयों में से है।

(ख) जी, हां ।

(ग) यह एक बड़ी उत्साहवर्धक योजना है विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों के लिए ।

थाईलैण्ड से पटसन का आयात

*594. **श्री उमानाथ :**
श्री अनिरुद्धन :
श्री रमानी :
श्री भगवान दास :

क्या **वाणिज्य** मंत्री थाईलैण्ड से पटसन के आयात से सम्बन्धित 13 फरवरी, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के जाँच सम्बन्धी प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच पूरी कर ली है और उसका विचार ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में जिन के विरुद्ध प्रत्यक्षतः मामले हैं, सम्बद्ध राज्य सरकार तथा प्रवर्तन निदेशालय के परामर्श से आगे कार्यवाही करने का है।

मद्रास प्रदर्शनी

*595. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास प्रदर्शनी का आयोजन करने के लिये केन्द्रीय, राज्य और विदेशी सरकारों द्वारा और गैर-सरकारी उद्योगपत्तियों द्वारा पृथक-पृथक कितना धन व्यय किया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि विदेशों में से साम्यवादी गुट के देशों ने अधिक रुचि दिखाई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ये देश रुपये में भुगतान के आधार पर मशीनें बेच रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो देश की बेकार औद्योगिक क्षमता के संदर्भ में इन मशीनों को बेचने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

मद्रास में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा उद्योग मेले का आयोजन अखिल भारतीय निर्माता संघ द्वारा किया गया है । मेले के लिये भूमि, मेले तक पहुंचने के लिये सड़कों, जल, बिजली नालियों आदि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था मद्रास सरकार द्वारा की गई है, जिसको इस हेतु भारत सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि दी गई है जो बाद में मद्रास सरकार को वापिस लौटानी होगी । अखिल भारतीय निर्माता संघ को भी मेले का खर्च उठाने के लिये मार्गोपायों के रूप में 10 लाख रुपये की अग्रिम राशि दी गई है । केन्द्रीय सरकार के भाग लेने वाले मंत्रालयों और राज्यों तथा विदेशी सरकारों तथा गैर-सरकारी उद्योगपतियों द्वारा किये गये व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । वाणिज्य मंडप के लिये 15 लाख रुपये की बजट व्यवस्था की गई हैं ।

मेले में भाग लेने वाले 17 देशों में से 8 पूर्वी यूरोप से हैं । अन्य देशों ने बिना कोई कारण बताये मेले में भाग लेने में अपनी असमर्थता प्रकट की है ।

अंतर्राष्ट्रीय मेलों की सामान्य प्रथा के अनुसार मेले के अंत में विदेशी भाग लेने वालों के लिये अपनी प्रदर्शित वस्तुओं को बेचने की अनुमति एक ऐसी धन-सीमा तक दी जाती है जिसका हिसाब उनके द्वारा बुक किये गये प्रदर्शनी स्थान के 50 रुपये प्रतिवर्ग फुट पर लगाया जाता है । ये बिक्री विद्यमान आयात नियंत्रण नीति के अनुसार तथा आवश्यक सीमा शुल्क के भुगतान किये जाने पर की जा सकती है थी । केवल उन मामलों में, जहां स्वदेशी दृष्टिकोण से बेची गई प्रदर्शित वस्तुओं के आधार पर मेले का कोटा उपयोग में न लाया जा सका, अन्य प्रदर्शित वस्तुओं की बिक्री शामिल करने की छूट दी गई है । ऐसी बिक्री का परिमाण बहुत कम है और स्वदेशी उद्योगों पर उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

बीकानेर और दिल्ली के बीच रेलवे लाइन में दरार

†596. डा० **कर्णी सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 11 जनवरी, 1968 को बीकानेर और दिल्ली के बीच रेलवे लाइन में दरारें देखी गई थीं जिन के कारण उस रात बीकानेर-दिल्ली मेल गाड़ी पटरी से उत्तर सकती थी और भयानक दुर्घटना हो सकती थी ;

(ख) क्या 26 दिसम्बर, 1965 को ऐसी ही परिस्थितियों के कारण दिल्ली-बिकानेर मेल गाड़ी पटरी से उत्तर गई थी ; और

(ग) इन आश्वासनों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि रत्नगढ़ और बीकानेर के बीच समूची रेलवे लाइन पुनः बिछाई जायेगी और ऐसी दरारों का पता लगाने के लिए अन्य पूर्वोपाय किये जायेंगे ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी नहीं । 10-1-1968 को एक चाभी-वाले ने एक दरार देखी थी और बीकानेर डाकगाड़ी को नेलासर और नापासर के बीच 18 मिनट के लिये रोक लिया था। पटरी की देख भाल कर लेने के बाद डाकगाड़ी को गुज़रने की अनुमति दे दी गयी ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) रत्नगढ़ और बीकानेर के बीच 137 किलोमीटर के पूरे खण्ड पर अधिक भारी रेलें बिछाने की मंजूरी दी जा चुकी है । 68 किलोमीटर के फासले में ऐसी रेलें पहले ही बिछायी जा चुकी हैं और शेष 69 किलोमीटर में यह काम हो रहा है और 1969 तक इस काम के पूरा हो जाने की आशा है । पटरी की दरारों का पता लगाने के लिए पहले ही विशेष पूर्वोपाय किये गये हैं ।

स्कूटरों, मोटर साइकिलों तथा मौपेड़ों के निर्माण के लिये नये लाइसस

*597. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने स्कूटरों, मोटर साइकिलों और मौपेड के निर्माण के लिए नये लाइसेंस जारी करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). स्कूटरों की बढ़ती हुई माँगों और विक्रेताओं के पास बाकी आर्डरों की लम्बी सूची को देखते हुए सरकार स्कूटर बनाने के लिए एक अतिरिक्त कारखाने को लाइसेंस देने पर विचार कर रही है फिर भी, मोटर साइकिलों और मौपेडों का निर्माण करने के लिए नया औद्योगिक लाइसेंस देने का कोई विचार नहीं है ।

कीनिया में औद्योगिक कारखाने

*598 **श्री रा० कि० अमीन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कीनिया में औद्योगिक कारखाने स्थापित करने के लिए भारतीय उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार उन्हें प्रोत्साहन देने का है ; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) नैरोबी स्थित हमारे मिशन के माध्यम से पूछताछ प्राप्त हुई कि क्या "नैरोबी औद्योगिक बस्ती" में, जो पूरी होने वाली है, कुछ छोटी औद्योगिक मदों के औद्योगिक कारखाने स्थापित करने के लिए उपयुक्त भारतीय

पार्टियाँ भाग आ सकेंगी । यह पूछताछ भारत में वितरित की गई है। कुछ भारतीय भी कीनिया में उद्योग स्थापित कर रहे हैं।

(ख) और (ग). भारतीय उद्यमियों द्वारा विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार प्रोत्साहन देती है बशर्ते उनका भाग लेना स्वदेशी मशीनों, उपकरणों और तकनीकी जानकारी के निर्यात के रूप में हो ।

टीनबन्द खाद्य पदार्थों तथा अचार का निर्यात

3637. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रति वर्ष कितने मूल्य के टीनबन्द खाद्य पदार्थ तथा अचार का निर्यात किया जाता है और पिछले तीन वर्षों में वर्षवार हमारे टीनबन्द उत्पाद किन-किन देशों को भेजे गये थे?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है । [पुस्कालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 429/68]

कपास का आयात

3638. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देशवार किन-किन देशों से देशवार कुल कितनी कपास आयात की गई ; और

(ख) उस पर कितनी मुद्रा व्यय की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). गत तीन वर्षों में विदेशी मुद्रा में भुगतान के आधार पर निम्नांकित परिमाण में कपास का आयात किया गया :—

मात्रा लाख गांठों में

मूल्य करोड़ रूपये में

	1964-65		1965-66		1966-67	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
संयुक्त अरब गणराज्य .	1.58	15.87	1.81	16.59	1.76	25.46
सूडान . .	0.98	8.34	1.31	12.89	1.26	14.15
पूर्वी अफ्रीका .	1.03	6.62	0.37	3.85	0.85	8.03
पाकिस्तान . . .	0.56	2.70	नगण्य	नगण्य	0.29	2.02
अन्य . . .	0.43	3.66	0.01	0.10	0.34	4.20
योग : .	4.58	37.19	3.50	33.43	4.51	53.86

नोट:— इन आंकड़ों में सं० रा० अमरीका से पी० एल० 480 के अन्तर्गत विशाल मात्रा में आयात की गई कपास शामिल नहीं है क्योंकि उस में विदेशी मुद्रा नहीं लगती ।

खादी उद्योग

3640. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1967 को देश में खादी किस किस्म की तथा कितने रुपये के मूल्य की खादी का उत्पादन हुआ, बिक्री हुई तथा कितना माल स्टाक में बचा हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के पास 15 करोड़ रुपये से अधिक का माल बिना बिका पड़ा हुआ है ;

(ग) खादी का उत्पादन करने के लिए देश में राज्यवार कुल कितने तकुए हैं और 31 मार्च, 1967 को कितने तकुओं का उपयोग नहीं किया गया ;

(घ) देश में खादी के उत्पादन-कार्य में राज्यवार कितने-कितने श्रमिक तथा कारीगर लगे हुए हैं और उनका वार्षिक मजदूरी बिल क्या है ; और

(ङ) खादी उद्योग को स्थिर बनाने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ङ) : जानकारी एकत्र की जा रही हैं और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी। ।

त्रिवेन्द्रम में बुनकर सेवा केन्द्र

3641. **श्री मंगलाथुमाडोम :**
श्री विश्वम्भरन :

क्या वाणिज्य मंत्री 24 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 19 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम में एक बुनकर सेवा केन्द्र स्थापित करने का इस बीच कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). त्रिवेन्द्रम में एक बुनकर सेवा केन्द्र खोलने का प्रश्न विचाराधीन है ।

केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन

3642. **श्री मंगलाथुमाडोम :**
श्री वासु देवन नायर :
श्री विश्वम्भरन :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन के अधीन तिरुवाला, एत्तूनूर तथा मुवत्तापुज्हा में निर्माण तथा विस्तार केन्द्रों के कर्मचारी अपनी शिकायतों को दूर कराने के लिये सत्याग्रह कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के लिये कोई कार्यवाही की है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन केन्द्रों के क्रिया-कलापों में विस्तार करने तथा इनके काम में अधिक कार्य-कुशलता लाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(घ) क्या इन केन्द्रों को राज्य सरकारों को सौंपने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इन केन्द्रों में इस समय कार्य कर रहे कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) कर्मचारियों द्वारा रखी गई मांगों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(ग) इन केन्द्रों के कार्य-कलापों को बढ़ाने का कोई भी विचार नहीं है किन्तु उनकी कार्य कुशलता बढ़ाने की जांच की जा रही है।

(घ) जी, हां।

(ङ) सरकारी नियमों और विनियमों के अनुसार कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जायगी।

कर्मशियल क्लर्क

3643. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में कुल कितने कर्मशियल क्लर्क हैं ;

(ख) प्रत्येक रेलवे (जोन) में पृथक्-पृथक् 110—200, 150—240, 205—280, 250—380, 335—425, 370—475 और 450—575 रुपये के ग्रेड में कितने कर्मशियल क्लर्क काम कर रहे हैं और ग्रेडवार उनकी संख्या क्या है;

(ग) प्रत्येक रेलवे जोन में पृथक्-पृथक् 250—380, 335—425, 370—475 और 450—575 के ग्रेडों में काम कर रहे कर्मशियल इंस्पैक्टरों की संख्या क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि एक रेलवे जोन से अन्य रेलवे जोन में कर्मशियल क्लर्कों के अपग्रेडिड पदों में बड़ी असमानता है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) से (ङ). सूचना मंगायी जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Import of Iron for Manufacture of Motor Cars

3644. **Shri Nitiraj Singh Chaudhary :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether iron is being imported from the foreign countries for the manufacture of motor cars ;

(b) whether such iron cannot be manufactured in the country ; and

(c) if so, when it is likely to be manufactured ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (**Shri F.A. Ahmed**) : (a) Steel materials, and not iron, are being imported for the manufacture of cars.

(b) and (c). Only a small portion of the requirements is being obtained from the Rourkela Steel Plant at present.

Efforts are being made, in consultation with the Department of Iron & Steel, to arrange for the production of adequate quantities of the steel materials and the special sheets by the indigenous Steel Plants.

Trade Agreement with Rumania

3645. Shri Nitiraj Singh Chaudhary : Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 222 on the 13th February, 1968 and state :

(a) the details of the trade and payment agreement with Rumania which has been extended upto the 31st December, 1968 ; and

(b) the goods to be imported and exported under the said agreement ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (**Shri Mohd. Shafi Qureshi**) : (a) The long term Trade and Payments Agreement between the Government of India and the Government of Socialist Republic of Rumania, which was concluded on 30-11-1962, was originally valid for a period between 1-1-1963 and 31-12-1967. This validity period has since further been extended upto 31-12-1968. The main features of this Agreement are (i) all imports from Rumaina are to be balanced with exports from India ; (ii) there will be most favoured nation treatment on both sides ; (iii) all payments of commercial and non-commercial nature are to be made in Indian repuees ; and (iv) any balances in the rupee accounts are to be used for the purchase of Indian goods.

Copy of this Agreement is already available in the Parliament Library.

(b) A list indicating the goods which are available to be imported into India from Rumania and exported from India to Rumaia is enclosed. [*Placed in Library. See no. LT—430/68*]

बिड़लाओं के बैंक

3646. श्री जुगल मण्डल : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 24 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1928 के उत्तर के सम्बन्ध में बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिड़लाओं के बैंकों के बारे में जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने बैंक अथवा अन्य समवाय है जिनमें बिड़ला बन्धु एक साथ डायरेक्टर हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) हाँ, श्रीमान्। बिड़लाओं की कोई अपनी बैंक नहीं है।

(ख) सूचना संग्रह की जा रही है, यह शीघ्र ही सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

दिल्ली में दस्तकारी केन्द्र

3647. **श्री वे० अमात :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों के लिये दिल्ली में एक दस्तकारी केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इनके लिये कौनसा स्थान निश्चित किया गया है; और

(ग) क्या इनके निर्माण का खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकारों द्वारा दिया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां। परन्तु एक ही दस्तकारी केन्द्र नहीं खोला जायेगा अपितु प्रत्येक राज्य का अपना-अपना एक-एक एम्पीरियम होगा।

(ख) ईर्विन रोड, नई दिल्ली ।

(ग) भवनों के निर्माण की लागत का व्यय सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा उठाया जायेगा।

दस्तकारी के उद्योगों के लिये भूमि

3648. **श्री वे० अमात :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों को औद्योगिक प्रयोजन के लिये नई दिल्ली कनाट प्लेस में भवनों का निर्माण करने हेतु मुफ्त भूमि दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इनके नाम क्या हैं; और

(ग) किन राज्यों ने हस्तशिल्प के लिये किराये पर भवन लिये हैं तथा उनका मासिक किराया क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

3649. **श्री वि०ना० शास्त्री : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में 31 मार्च, 1967 तक कुल कितनी पूंजी लगाई गई थी;

(ख) विनियोजित पूंजी का कितने प्रतिशत शुद्ध लाभ हुआ है; और

(ग) अन्य मुख्य सरकारी उपक्रमों में यह लाभ इससे कम हुआ है अथवा अधिक ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) सरकार द्वारा दी गई धन राशि के आधार पर, 31 मार्च, 1967 तक हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में लगाई गई कुल पूंजी 10,285 मिलियन रुपये थी (इक्विटी 5,280 मिलियन रुपये और सरकारी ऋण 5005 मिलियन रुपये)

(ख) वर्ष 1966—67 के अन्त तक कम्पनी का कुल घाटा 823 मिलियन रुपये था।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

छोटी कार परियोजना

3650. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्बन्धी सम्मेलन के लिये आये कुछ विदेशी प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली में अपनी उपस्थिति का उपयोग प्रस्तावित छोटी कार परियोजना के लिये सहयोग से सम्बन्धित मामले पर सरकार के साथ विचार-विमर्श करने के लिये किया था;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों के प्रतिनिधियों ने सरकार के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श किया था;

(ग) क्या इससे छोटी कार का निर्माण करने के बारे में कोई निर्णय करने में सरकार को मदद मिली; और

(घ) यदि हां, तो सरकार को कौन से प्रस्ताव पसन्द आये और ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

मद्रास से रामेश्वरम तक रेलवे लाइन

3651. **श्री किरुत्तिनन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास से रामेश्वरम तक एक रेलवे लाइन बिछाने के लिये दक्षिण रेलवे के महाप्रबन्धक ने निरीक्षण किया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) और (ख). मद्रास एवुम्बूर से रामेश्वरम् तक मीटर आमान की एक रेलवे लाइन पहले से मौजद है, और उसके बिछाने के लिए महाप्रबन्धक द्वारा निरीक्षण का सवाल नहीं उठता। सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय मद्रास और रामेश्वरम् के बीच विभागीय प्रधानों के साथ महाप्रबन्धक के निरीक्षण से है। यह निरीक्षण नीचे लिखे अनुसार विभिन्न चरणों में किया गया था:—

खण्ड	निरीक्षण की तारीख
(i) मद्रास-वृद्धाचलम	21-2-1967
(ii) वृद्धाचलम-मदुरै	22-2-1967
(iii) विलुपुरम-तिरुच्चिराप्पल्ली (बरास्ता मुख्य लाइन) . .	25-8-1967
(iv) तिरुच्चिराप्पल्ली-मानमदुरै . .	30-1-1968
(v) मानमदुरै-रामेश्वरम्	31-1-1968

इन निरीक्षणों के बाद जारी की गयी निरीक्षण टिप्पणियों पर कार्रवाई की गयी है।

हिमाचल प्रदेश में स्थापित किये गये उद्योग

3652. **श्री ललित सेन** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पाँच वर्षों में हिमाचल प्रदेश में कितने और किस प्रकार के नये उद्योग स्थापित किये गये;

(ख) क्या यह औद्योगिक विकास निश्चित समय के अनुसार हो रहा है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र तथा ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में कौन-से नये उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

Contributory Provident Fund in Khadi and Village Industries Commission

3653. **Shri J. Sundar Lal :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Khadi and village Industries Commission have framed some rules in regard to contributory Provident Fund for their employees ;

(b) if so, the reasons for which this facility has not been extended since 1957 to the employees working in the Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi; and

(c) the time by which the Commission proposed to extend the benefit of Contributory Provident Fund to these employees ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Payment of D.A. to Khadi Gramodyog Bhawan Employees

3654. **Shri J. Sundar Lal :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the rates of Dearness Allowance paid to the employees o Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi were reduced some time back and the amount thus reduced was shown against city compensatory allowance;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) the date from which City Compensatory Allowance is being paid to them and the date with effect from which orders for payment of City Compensatory Allowance were issued by the Khadi and Village Industries Commission ;

(d) the steps proposed to be taken by the Khadi and Village Industries Commission to make good the loss suffered by the employees as a result of the aforesaid action ; and

(e) the part of Dearness Allowance which the Khadi and Village Industries Commission proposes to merge in the basic pay of their employee ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (e) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Pay Scales in Khadi and Gramodyog Bhawans

3655. **Shri J. Sundar Lal :** Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether the employees of all Khadi Bhawans under the Khadi and Village Industries Commission are allowed uniform grades of pay scale and other facilities ;

(b) if not, the full details of pay scales and facilities offered by different Khadi Bhawans for dffierent posts ; and

(c) the action proposed to be taken by Government or Khadi and Village Industries Commission in regard to the welfare of the employees of Khadi Bhawans ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c): Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Bonus to Employees of Khadi Gramodyog Bhawan

3656. Shri J. Sundar Lal : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether any bonus is being paid to the employees of Khadi Gramodyog Bhawan under the Bonus Act ;

(b) if not, the reasons therefor ; and

(c) when the Commission propose to give bonus to its employees ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No, Sir.

(b) and (c). The matter is under consideration.

Deposits of Cement Stone in Karauli area in Rajasthan

3657. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are large deposits of cement stone in tne Karauli area of Swai Madhopur District in Rājasthan ;

(b) if so, the quantity thereof ; and

(c) the nature of scheme formulated in this regard ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) and (b). Yes, Sir. Limestone deposits between Maholi and Kelandevi are estimated at 100 million tonnes.

(c) Cement Industry has been delicensed in May, 1966 and no industrial licence is now required for setting up a cement plant.

Retrenchment of Railway Employees of Kotah Division

3658. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of the Kotah Division of Western Railway, who have been in service for the last so many years, are bing retrenched and removed from service ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether it is proposed to provide them with alternative jobs ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

"गोशिन नामक जहाज का हटाया जाना"

3659. श्री सम्बधन : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि "गोशिन" नामक जहाज जो कि इस समय मंडप्पम में पड़ा है के न हटाये जाने के कारण हानि हो रही है;

(ख) इस जहाज के न हटाये जाने का गोदी के वर्कशाप पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या; और

(घ) इस नष्ट हुए जहाज को कब तक हटाये जाने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) सरकार को इस बात का पता है कि टी०एस०एस० "गोशिन" नामक जहाज; जो 1964 के तूफ़ान में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, मण्डपम की सूखी गोदी में पड़ा हुआ है। चूंकि यह जहाज़ अब किसी काम में नहीं आ सकता इसलिए इसे रद्दी बना कर बेच दिया जायेगा। जब तक यह बेचा नहीं जाता तब तक जहाज़ को सूखी गोदी में रखना होगा। जब रेलवे की कोई अपनी परिसम्पत्ति रेलवे की अपनी सूखी गोदी में पड़ी होती है तब उसे वहाँ से न हटाये जाने के कारण होने वाली किसी प्रकल्पित हानि या प्रभाव का सवाल नहीं उठता।

(ग) इस जहाज़ को बेचने के लिए सभी सम्भव कार्रवाई की गयी है और की जा रही है, अतः किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने का सवाल नहीं उठता।

(घ) रेल प्रशासन इसे एक वास्तविक और उचित आरक्षित मूल्य पर बेचने का प्रयत्न कर रहा है। इसे बेचने के लिए अभी कोई अंतिम तारीख निश्चित नहीं की गयी है।

Import of Rice

3660. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the names of countries from where the imports of rice would be made this year in exchange of commodities to be exported by India to the countries concerned?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): At present there is no arrangement to import rice in exchange of commodities to be exported by India.

Recovery of Bomb Near Bargaon (Central Railway)

3661. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the news appearing in the daily 'Swadesh' of the 11th January, 1968 that some bombs were recovered near Bargaon on the Bhusaval-Nagpur Railway section and near Dolaria and Dharamkundi Railway Stations on the Itarsi-Bombay Railway section; and

(b) if so, whether an enquiry has been made as to the name of the Ordnance Factory in which these bombs were manufactured and the weight of these bombs together with other results of the enquiry?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha): (a) Yes.

(b) Yes. A shell weighing about 1300 grams, bearing foreign marking was found on Railway track between Achegaon and Hodwad on Bhusaval-Nagpur Railway lines on 20th December, 1967. Enquiries are being made by Government Railway Police, Bhusaval, and they are in progress. No sabotage is suspected.

आय-व्ययक पेश किये जाने से पूर्व की जाने वाली चोर बाजारी को रोकना

3662 **श्री वी० च० शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को कोई निदेश दिये गये हैं कि आय-व्ययक पेश किये जाने से पूर्व अत्यावश्यक वस्तुओं की चोर बाजारी को रोका जाये; और

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या निदेश दिये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) आय-व्ययक से पूर्व, बाजार में उतार-चढ़ाव प्रतिवर्ष की सामान्य बात है । अत्यावश्यक माल में चोर-बाजारी को, यदि कोई हो, हमेशा ही, जिसमें आय-व्ययक के पूर्व का समय भी शामिल है, रोकने के लिये राज्य सरकारों को अधिकार सौंपे गये हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Export of Coal

3663. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the names of countries to which coal is being exported and the quantity thereof exported to each of them during the years 1965-66 and 1966-67; and

(b) the reasons for decline in the exports of coal during the year 1966-67 as compared to that of 1965-66?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Coal is exported to Burma, Ceylon and Japan. The exports of coal to these countries is as under:—

	Burma	(Qty. Lakh Tons) Ceylon	Japan	Total
1965-66	1·40	.59	..	1·99
1966-67	1·93	1·65	·05	3·63

(b) Does not arise. The exports during 1966-67 are higher as compared with those of 1965-66.

Visit by a Soviet Delegation to Cimmco Ltd., Bharatpur

3664. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) wheter it is a fact that a Soviet Delegation recently visited the Central India Machinery Mfg. Co. Ltd., Bharatpur; and

(b) if so, the outcome thereof?

The Minister of Ralways (Shri C. M. Poonacha): (a) It is a fact that a Soviet Delegation headed by H.E. Mr. Patolichev, Minister for Foreign Trade, USSR visited the Works of M/s. Central India Machinery Mfg. Co. Ltd., (CIMMCO), Bharatpur on 3rd February, 1968.

(b) There were some general discussions mainly in regard to supply of railway wagons to U.S.S.R. There was no direct outcome but it is hoped that the visit was of interest to the delegation.

उत्तर रेलवे दिल्ली का डिवीजन लेखा कार्यालय

3665. **श्री बेणी शंकर शर्मा**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन के डिवीजनल लेखा अधिकारी के कार्यालय में कार्य करने वाले कुछ लेखापालों और वरिष्ठ लेखापालों के विरुद्ध उनकी आय से अधिक सम्पत्ति बना लेने के मामले हैं;

(ख) क्या कोई विभागीय जाँच की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) मंडल लेखा अधिकारी, दिल्ली के कार्यालय के केवल एक वरिष्ठ लेखापाल पर उसकी आय से अधिक परिसम्पत्तियाँ बना लेने का सन्देह किया गया।

(ख) इस मामले की जाँच विशेष पुलिस स्थापना, दिल्ली द्वारा की गयी थी।

(ग) अनुशासन और अपील नियमों के अधीन घोर दण्ड देने के लिए आरोप-पत्न के आधार पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है।

ट्रैक्टरों का निर्माण

3666. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्न में ट्रैक्टर बनाने के लिये चेकोस्लोवाकिया सरकार के साथ बातचीत कर रही है;

(ख) करार की शर्तें क्या होंगी तथा निर्माण सम्बन्धी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) खेती में काम आने वाले जीटर 2011 ट्रैक्टरों और औजारों का निर्माण करने के लिये सरकारी क्षेत्न में एक परियोजना स्थापित करने के प्रायोजन से एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में चेकोस्लोवाकिया के मेसर्स मोटोकोव के साथ एक करार किया गया था। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का पहला भाग, जिसमें परियोजना का तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन दिया हुआ है, पिछले वर्ष प्राप्त हो गया था। सरकार ने रिपोर्ट की जाँच करके बाद में चेक एजेंसी के प्रतिनिधियों से इस पर चर्चा की थी। इस चर्चा में परियोजना के क्षेत्न में कुछ संशोधन करने के सुझाव दिये गए थे। सुझाये गए कुछ संशोधन करके एक अनुपूरक रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसकी जाँच की जा रही है। रिपोर्ट की छानबीन कर लने के बाद ही परियोजना का ठीक-ठीक क्षेत्न और लागत का पता लग सकेगा।

नेपा नगर में वृक्ष लगाया जाना

3667. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत वर्ष पहले मध्य प्रदेश के नेपा नगर में कागज और अखबारी कागज बनाने के लिये उपयोग वृक्ष लगाने का कार्य आरम्भ किया गया था;

(ख) क्या यह परियोजना पूरी हो गई है और यदि हाँ, तो कब पूरी हुई थी और यदि नहीं, तो उसमें कितना समय और लगने की सम्भावना है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये कितना वित्तीय परिव्यय, कितने कर्मचारी, निरीक्षण कर्मचारी और कौन-कौन से उपकरण लगाये गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

महाराष्ट्र में औद्योगिक उत्पादन में हानि

3668. **श्री क० लकप्पा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयना भूकम्प के कारण महाराष्ट्र राज्य में औद्योगिक उत्पादन में हुई हानि का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कम्पनी सेक्रेटरी शिप

3669. **श्री विश्वम्भरन :**
श्री मंगलाथुमांडम :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 के अन्त तक कुल कितने व्यक्तियों को कम्पनी सेक्रेटरीशिप में सरकारी डिप्लोमा दिया गया है;

(ख) ऐसे डिप्लोमाधारी कितने हैं जिन्हें अभी तक सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र के निगमित उपक्रमों में उपयुक्त रोजगार नहीं मिला है;

(ग) क्या इन डिप्लोमाधारियों को सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में उपयुक्त पदों पर नियुक्त करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही आरम्भ की गई है और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) क्या सरकार ने कम्पनी सेक्रेटरीशिप में सरकारी डिप्लोमे के बराबर किस अन्य अर्हता को स्वीकार किया है और यदि हाँ, तो वे कौन सी अर्हताएं हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 116।

(ख) सूचना प्राप्त नहीं है।

(ग) सरकार पर योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों को नौकरी देने का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। फिर भी डिप्लोमा प्राप्त लोगों के ब्यौरे लोक उपक्रमों के कार्यालयों को भेजे जाते हैं, जो उन्हें बारी से अपने अन्तर्गत उपक्रमों के सचिवीय विभागों में अन्तर्लीन करने के लिये भेजते हैं। मंत्रालयों/विभागों के सचिवों द्वारा, उनके अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों के लिये सचिवीय पदों की भर्ती के मामलों में, योग्यता प्राप्त कम्पनी सचिवों को अधिमान देने के लिये अलग से अनुदेश प्रेषित किये गये हैं।

(घ) नहीं, श्रीमान् । फिर भी, व्यापार में तकनीकी अध्ययन के अखिल भारतीय बोर्ड ने, 30 जून, 1967 तक (क) कारपोरेशन आफ सेक्रटरीज, लंदन तथा (ख) चार्टर्ड इन्स्टीट्यूट आफ सेक्रटरीज, लंदन की अन्तिम परीक्षा पास करने वालों को, उच्च पदों की भर्ती के लिये, जहां कम्पनी सचिवों के कार्य से सम्बन्धित, विशेष ज्ञान अपेक्षित है, पर्याप्त योग्यता के लिये मान्यता दे दी है। यह भी निर्देश करना आवश्यक है कि परिनियम (कम्पनी विधि), एक निगम में सचिव की नियुक्ति के लिये, कोई विशिष्ट योग्यता उपबन्धित नहीं करता ।

Industries in Maharashtra

3670. **Shri Dheorao Patil :** Will the Minister of **Industrial Development and Compnay Affairs** be pleased to state :

(a) the number and types of industries proposed to be set up in Maharashtra in 1968-69; and

(b) the amount of financial assistance proposed to be given to Maharashtra during the above period?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Besides the project of Hindustan Organic Chemicals on which work is in progress, the projects to be taken up in Maharashtra in the Central sector during 1968-69 are;

(i) Koyna Aluminium project,

(ii) Expansion of Trombay Fertiliser project.

The following schemes under Large and Medium industries have been included in the State Plan for 1968-69:—

1. State Textile Corporation.
2. Basic Facilities to public sector undertakings.
3. Development of Industrial Areas.
4. Maharashtra Industrial & Investment Corporation.
5. State Finance Corporation.
6. Preparation of technical project reports.
7. Co-operative spinning mills.
8. Industrial Research and Pilot Plant.
9. Permanent Industrial Museum-*cum*-Exhibition.

(b) There is no set pattern of assistance for financing large and medium industrial projects in the State setor. However, the State Government can finance these schemes out of the overall Central assistance available for Miscellaneous Development Schemes.

दक्षिण-पूर्व रेलवे में निराकारपुर पर एक्सप्रेस गाड़ियों का रुकना

3671. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के निराकारपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं के लिये एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रुकवाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : 1-4-1968 से लागू होने वाली समय-सारणी में 38 डाउन मद्रास-हावड़ा जनता एक्सप्रेस को निराकारपुर स्टेशन पर ठहराने की व्यवस्था की जा रही है । निराकारपुर स्टेशन पर अप दिशा में लम्बी दूरी का यातायात बहुत कम होने के कारण हावड़ा से मद्रास जाने वाली 37 अप जनता एक्सप्रेस को वहां ठहराने का औचित्य नहीं पाया गया है ।

खुरदा डिवीजन में रेलवे के कर्मचारियों और उनके बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाएं

3672. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67 और 1967–68 के दौरान दक्षिण-पूर्व रेलवे के खरदा डिवीजन में बच्चों और कर्मचारियों की शिक्षा के लिये कर्मचारी कल्याण निधि में से कितनी धनराशि उपलब्ध हुई;

(ख) उसके लिये कितने व्यक्तियों ने आवेदन पत्र भेजे थे; और

(ग) इस निधि से ऐसे कितने बच्चों और कर्मचारियों को लाभ पहुंचा है जो उड़ीसा के रहने वाले हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० बु० पुनाचा) :

(क) वर्ष	धन-राशि रु०
1966-67	22,568.00
1967-68	21,347.00

(ख) वर्ष	संख्या
1966–67	588
1967–68	807

(ग) वर्ष	संख्या
1966–67	243
1967–68	327

महालक्ष्मी कपड़ा मिल्स लिमिटेड, भावनगर

3673. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री काशीनाथ पाण्डेय :
श्री किंकर सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महालक्ष्मी कपड़ा मिल लिमिटेड, भावनगर में उत्पन्न गम्भीर स्थिति के बारे में उनको अवगत कराने के लिये संसद् सदस्यों के एक प्रतिनिधि मण्डल ने मंत्री महोदय से दिसम्बर, 1967 में भेंट की थी;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). संसद् के पांच सदस्यों ने मिलकर वाणिज्य मंत्री को एक पत्र भेजा था और उनमें से कुछ

सदस्यों ने उनसे भेंट भी की थी तथा मिल को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया था।

(ग) मिल के कार्यों की देखभाल करने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 15 के अन्तर्गत एक जांच समिति नियुक्त कर दी गई है।

महालक्ष्मी कपड़ा मिल, भावनगर

3674. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री द० रा० परमार :
श्री रा० कि० अमीन :
श्री छ० म० केदारिया :
श्री काशीनाथ पाण्डेय :
श्री रामचन्द्र ज० अमीन :
श्री किकर सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1968 में महालक्ष्मी कपड़ा मिल्स लिमिटेड भावनगर में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो आग लगने के कारण अनुमानतः कितने रुपये की हानि हुई;

(ग) क्या आग के कारणों का पता लगाने के लिये सरकार का कोई जांच करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) भिन्न-भिन्न अनुमानों के अनुसार हानि 25 से 35 लाख रुपये है।

(ग) और (घ). राज्य सरकार आग लगने के कारणों की जांच कर रही है।

रेलवे में स्थायी मार्ग निरीक्षक

3675. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री राजाराम :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री किकर सिंह :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री द० रा० परमार :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1962 में कुंजरू समिति ने सिफारिश की थी कि स्थायी मार्ग निरीक्षकों के लिये एक मापदंड निश्चित किया जाना चाहिये और रेलवे ने उस सिफारिश को स्वीकार कर लिया था;

(ख) क्या दक्षता (एफीशेंसी) ब्यूरो ने भी ये मापदंड बनाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो मार्ग तथा निर्माण निरीक्षकों के सम्बन्ध में इस मापदंड को क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) रेल-पथ कर्मचारियों के लिए की गयी सिफारिशों को एक कार्यक्रम के आधार पर लागू किया जा रहा है ।

जोधपुर डिवीजन के कर्मचारियों को उच्चतर ग्रेड दिया जाना

3676. **श्री नायनार :**
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री अब्राहम :
श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या रेलवे मंत्री 22 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5639 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर डिवीजन के कर्मचारियों को उच्चतर ग्रेड का लाभ देने के बारे में सूचना एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां । जोधपुर मंडल में स्नातकों के लिए आरक्षित 20 प्रतिशत जगहों पर 1-4-1956 से पात्र कर्मचारियों को उच्चतर ग्रेड के पदों का लाभ दिया गया है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

लोहा और इस्पात नियंत्रक का कार्यालय

3677. **श्री नायनार :**
श्री पी० राममूर्ति :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री ग्र० क० गोपालन :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री 22 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5464 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहा और इस्पात नियंत्रक के कार्यालय के पुनर्गठन के प्रश्न पर इस बीच सरकार विचार कर चुकी है;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) से (ग) लोहा और इस्पात नियंत्रक के कार्यालय के पुनर्गठन के बारे में अभी कोई अन्तिम

निर्णय नहीं किया गया है क्योंकि कार्यालय के पुनर्गठन के पश्चात् कर्मचारियों की संख्या, पदों के वेतनमान आदि पर और आगे विचार किया जा रहा है ।

Quota of Reservation in 1st class in frontier Mail

3678. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the quota of reservation in first class fixed for Frontier Mail at Shamgarh station of the Western Railway is not fully availed of;

(b) if so, the number of first class tickets for Frontier Mail sold during 1967;

(c) the number of first class tickets sold from Bhawani Mandi during 1967; and

(d) whether Government propose to provide a halt at Bhawani Mandi for the Frontier Mail in view of the income accruing from the sale of tickets ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) No quota in Ist class has been allotted to Shamgarh station by 3 Dn./4 Up Frontier Mails.

(b) 87 by 3 Dn. Frontier Mail and 14 by 4 Up Frontier Mail.

(c) 276 in the Down direction, i.e. toward Delhi, and 261 in the Up direction, i.e. toward Bombay.

(d) No, as there is no adequate justification for providing a halt to these trains at Bhawani Mandi.

Tractor Factory with Russian Collaboration

3679. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Birlas have submitted a proposal to Government suggesting the setting up of a Tractor Factory in India with Russian collaboration; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) No.

(b) Does not arise.

Incident on Railway Bridge over Anderi River (W. Rly.)

3680. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 8 labourers died while lifting iron girders on the Railway bridge over Anderi river near Salpura on the Western Railway, around the 23rd December, 1967;

(b) If so, the age of each of them; and

(c) the amount of compensation paid by Government ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Distribution of Cement

3681. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to introduce some changes in regard to the distribution of cement; and

(b) if so, what are the proposed changes?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) and (b). There is no change in the distribution system for the 1st quarter of 1968. However, the arrangement for the distribution of cement in 2nd quarter of 1968 is yet to be decided.

Cement Factory in Bundi District

3682. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government had issued a licence to a private firm for setting up a cement factory in Bundi District;

(b) If so, the progress of work in the said factory; and

(c) the reasons as to why the work is not progressing?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c). In November, 1965, the scheme of a private party (of the Birla Group) for setting up a cement factory at Bundi in Rajasthan with an annual capacity of 200,000 tonnes was approved and a letter of intent was also issued. The cement industry has been exempted from the Licensing provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 with effect from 13th May, 1966, and it is no longer necessary for anyone to obtain a licence for the setting up cement factories. The party is understood to have completed detailed prospecting operations for lime stone and applied for loans to the financial institutions. It has also placed a provisional order on the machinery manufacturer for the supply of plant and machinery. In the meantime the Ministry of Railways have informed that the proposed Kota-Bundi-Chittorgarh line will be heavily unremunerative and hence the railway line from Kotah to Bundi and Chittorgarh has been dropped for the present. In view of the above, the party has now informed that they have deferred the idea of setting up of a cement factory at Bundi till the construction of a railway line materialises.

Railway Guards

3683. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that previously trains consisted of eight bogies only and they were controlled by Guards, Conductor Guards and Commercial Guards jointly but now the number of bogies has risen from eight to eighteen and the Guard alone has to look after the whole train *i.e.* he is not assisted by a Commercial Guard and a Conductor Guard;

(b) if so, how far it has affected the efficiency, order and punctuality of trains; and

(c) the steps proposed to be taken by Government for improving the situation?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) There is no reduction in staff strength. Guards are assisted by Brakesman/Conductor Guard according to the needs on different types of passenger trains.

(b) and (c). Do not arise.

xport Duty on Leather

3684. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to reduce the duty imposed on the exports of leather from India;

(b) if so, whether the exports of leather goods are likely to receive a set back as a result thereof; and

(c) the reasons for the promotion of export of leather instead of goods manufactured from leather?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) The export duty on finished leather of goat, sheep and bovine animals and of their young ones and on tanned hides of bovine animals, ecxcluding calf skins has been abolished.

(b) No sir, the duty was abolished primarily to guard against a possible fall in the export earnings from leather.

(c) Exports of leather are not standing in the way of increased exports of finished leather goods. The demand in the foreign markets is for sophisticated leather products. As India steps up production of the high quality leather goods, their exports are expected to go up.

Industries run by Harijans

3685. **Shri O. P. Tygai :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Government aided industries in India which are being completely run by Harijans; and

(b) the measures adopted by Government for attracting Harijans towards industries and success achieved in this regard?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the table of the House in due course.

सीमेन्ट संयंत्रों का निर्यात

3686. **श्री अदिचन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में सीमेंट संयंत्रों के निर्यात की सम्भावना का पता लगा लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क और (ख). हाल में इंजीनियरी निर्यात संवर्द्धन परिषद् ने अपने विदेशी कार्यालयों के जरिये, दक्षिण पूर्वी एशिया, अफ्रीका तथा मध्य-पूर्वी देशों में सीमेंट संयंत्रों के निर्यात के लिये बाजार सर्वेक्षण शुरू किये हैं। इस मद के बाजार सर्वेक्षण के सम्बन्ध में कुछ अन्य प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

केरल में नारियल जटा उद्योग का विकास

3687. **श्री अदिचन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में घटते जा रहे नारियल जटा उद्योग के विकास के लिये एक व्यापक पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और उस पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत किस प्रकार की तथा कितनी सहायता की गई है; और

(घ) क्या सरकार ने योजना की स्वीकृति दे दी है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

Expenditure on Railway Line from Katni to Mirzapur

3688. **Shri Shashibhushan Bajpai :** Will the Minister of **Railways be** pleased to state:

(a) the estimated expenditure on the construction of the Railway line from Katni to Mirzapur;

(b) the revenue likely to accrue to Government after the commissioning of the said line;

(c) whether the said Railway line is mainly meant for carrying bauxite to the Aluminium Factory, Mirzapur; and

(d) the reaction of the Commercial Department of the Railways in regard to the construction of the said line?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No direct rail link between Katni and Mirzapur has been constructed or such a link is under construction at present. However, the following two railway lines which will link the two places referred to via Chunar, are under construction:—

(i) a new BG line from Obra (a station on the newly constructed Robertsganj-Garhwa Road line) to Singrauli-estimated cost Rs. 10·71 crores.

(ii) a new BG line from Singrauli to Katni—estimated cost Rs. 14·38 crores.

(b) The earnings on these new lines will depend upon the movement of coal from Singrauli deposits, definite indications about which are not yet available.

(c) No. These lines are meant for coal traffic mainly.

(d) From the Commercial point of view these lines are likely to become remunerative when large scale coal traffic from Singrauli materialises on them.

Foreign Companies

3689. **Shri Shashibhushan Bajpai :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state the number of licences issued for the expansion of factories established by foreign countries during 1967-68 so far?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Dunlop Company

3690. **Shri Shashibhushan Bajpai :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether a licence has been issued to the Dunlop Company to import machinery for the manufacture of cycle spare parts; and

(b) the extent of contribution made by the Dunlop Company so far in the cycle spare parts trade ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed) : (a) Yes, sir. A licence for the import of equipment valued at Rs. 1,65,430 for the manufacture of special type of bicycle rims for the export market was issued in favour of Dunlop India Limited, Calcutta in December last.

(b) As against an installed capacity of 2.63 million Nos. of rims per annum, Dunlops have reported the following production during the last three years:

1965	25,25,218 Nos.
1966	20,07,793 Nos.
1967	22,06,369 Nos .

Import of Soyabean, Edible Oil, Nylon and Stainless Steel

3691. **Shri Shashibhushan Bajpai :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the quantity of Soyabean, edible oil, nylon, Stainless steel, nylon wool and the number of cotton bales proposed to be imported during 1968; and

(b) the quantities imported during the last year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) The quantum of imports is determined from time to time according to the needs of the Industry and as such it is not possible to forecast the import of these items during 1968 at this stage .

(b) Total quantity of import of Soyabean, Edible oils, Nylon fibre and Nylon yarn, Row Cotton etc. during 1966-67 is as follows :—

	Quantity in tonnes
Soyabeans (excluding flour and meal).	..
Edible Oils	29209
Nylon fibre (wool) and Nylon yarn . .	4818
Raw cotton, other than linters, sweepings, yellow pickings and other unspinnable fibres. .	92636
Stainless Steel	Not separately classified in the Revised Indian Trade Classification.

चतुर्थ श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों की पदोन्नति

3692. **श्री प० गोपालन :** **श्री प्र० क० गोपालन :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री चक्रपाणि :**

क्या रेलवे मंत्री 15 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4649 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1960–67 के दौरान चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों सम्बन्धी सिफारिश करने वाली समिति की सिफारिशों के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों की पदोन्नति के बारे में इस बीच सूचना इकट्ठी कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां । चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति सम्बन्धी समिति की सिफारिशों पर जो निर्णय किये गये थे वे रेलों पर लागू कर दिये गये हैं। कुछ रेलों पर गेंगमैनों और सफ़ाई वालों में से कम लोगों की पदोन्नतियां हुई हैं जिसके कारण हैं निरक्षरता, सामान्य अनुपयुक्तता और अपेक्षित डाक्टरी मानकों को पूरा न कर सकना तथा कुछ मामलों में कुछ पदों के लिये उम्मीदवार बनने के लिए इच्छुक न होना ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

Issue of Licences to Commercial Establishments

3693. **Shri R.S. Vidyarthi:**
Shri N. S. Sharma:
Shri Kanwar Lal Gupta:

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of those three commercial establishments to which maximum number of licences have been issued during the last three years;

(b) the value of those licences ;

(c) the number of licences used and remaining ones out of the aforesaid licences;

(d) whether any complaints have been received against the said commercial establishments during the last three years ; and

(e) if so, the nature thereof and whether any action has been taken thereon ?

The Minister of Industrial Development and Company affairs (Shri F.A. Ahmed): (a) to (e) : in the absence of any indication as to whether the reference is to industrial licences, import licences or any other type of licences, it is not possible to furnish the information.

पूर्वोत्तर रेलवे पर वातानुकूलित डिब्बों के इंचार्ज/अटेंडेंट

3694. **श्री पी० राममूर्ति :**
श्री नम्बियार :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री अब्राहम :

क्या रेलवे मंत्री 8 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3569 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर रेलवे के वातानुकूलित डिब्बों के इंचार्जों/अटेंडेंटों द्वारा उनकी सेवा की शर्तों, वेतन आदि में सुधार के लिये किये गये अभ्यावेदनों पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). यह मामला अभी विचाराधीन है ।

माल डिब्बों का निर्यात

3695. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ एशियाई, अफ्रीकी, पूर्वी यूरोपीय तथा लैटिन अमरीकी देशों से रेलवे माल डिब्बों के निर्यात के लिये अधिक क्रयादेश प्राप्त होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप माल डिब्बा निर्माण उद्योग की बेकार पड़ी सारी क्षमता को प्रयोग में लाया जायेगा;

(ग) इससे माल डिब्बा निर्माण उद्योग में मंदी की प्रवृत्ति कहां तक कम होने की संभावना है; और

(घ) क्या सरकार का विचार माल डिब्बों के निर्यात के लिये और प्रोत्साहन देने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां। माल डिब्बों के निर्यात के लिये कई देशों से बातचीत चल रही है और यह आशा है कि और अधिक आर्डर प्राप्त करना संभव होगा।

(ख) और (ग). प्राप्त निर्यात आदेशों तथा 1968-69 के लिये भारतीय रेलवे की मांग के आधार पर यह आशा की जाती है कि माल डिब्बा उद्योग की स्थापित क्षमता का पूर्णत: उपयोग हो सकेगा।

(घ) माल डिब्बा उद्योग को दी जाने वाली सहायता पर, भिन्न भिन्न मामलों के आधार पर विचार किया जाता है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाना

3696. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 फरवरी, 1968 के "पैट्रियट" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्रधान द्वारा यह कहा बताया गया है कि मन्दी तथा परियोजना में होने वाले भ्रष्टाचार के कारण कम्पनी को 8 से 9 लाख रुपये प्रति मास की हानि हो रही है;

(ख) क्या परियोजना के प्रधान ने आगे कहा है कि परियोजना उचित ढंग से नहीं बनायी गयी थी और इसका प्रशासनिक व्यय बहुत अधिक था;

(ग) परियोजना में सरकार द्वारा कितनी पूंजी लगाई गई है; और

(घ) क्या परियोजना के कार्य संचालन में सुधार करने के लिये सरकार का कोई पहल करने का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) से (घ). जी, हां। 13 फरवरी, 1968 के "पैट्रियट" में जो समाचार छपा था वह दुर्गापुर प्राजेक्ट्स लिमिटेड के बारे में था, जो पश्चिमी बंगाल सरकार का एक उपक्रम है। उसका सम्बन्ध दुर्गापुर इस्पात कारखाने से नहीं था।

पटसन की बनी वस्तुओं के निर्यात मूल्य

3697. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री रा० बरुआ :
श्री रवि राय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार से अनुरोध किया है कि पटसन से बनी वस्तुओं के निर्यात मूल्यों को गिरने से रोकने के लिये दोनों देशों के प्रयत्नों के सम्बन्ध में बातचीत की जानी चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) : जी, नहीं। किन्तु नई दिल्ली में इस समय हो रहे व्यापार तथा विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में पाकिस्तान तथा भारतीय प्रतिनिधियों के बीच मूल्यों की स्थिरता के प्रश्न पर अनौपचारिक रूप से विचार विनिमय हुआ है।

उत्तर रेलवे के यातायात प्रशिक्षार्थी

3698. **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री रमानी :
श्री एस्थोस :

क्या **रेलवे** मंत्री 22 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5470 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर रेलवे के यातायात प्रशिक्षार्थियों द्वारा भेजे गये ज्ञापन पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : यह मामला अभी समुचित प्राधिकारियों के विचाराधीन है।

गुजरात में छोटी लाइनों का बन्द किया जाना

3699. **श्री द० रा० परमार :**
श्री रा० कि० अमीन :
श्री रामचन्द्र ज० अमीन :
श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने गुजरात सरकार को यह आश्वासन दिया है कि उसकी पूर्व सम्मति के बिना गुजरात में छोटी लाइनों को बन्द नहीं किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

भावनगर में कच्चे लोहे तथा मशीनी औजार कारखाने की स्थापना

3700. श्री द० रा० परमार : श्री रा० कि० अमीन :
श्री रामचन्द्र ज० अमीन : श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में भावनगर में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कच्चे लोहे तथा मशीनी औजार कारखानों की स्थापना का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इसे गुजरात राज्य के बाहर कहीं स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो मशीनी औजार कारखाने के सम्बन्ध में कार्य कब शुरू होने की सम्भावना है और उसका क्रमबद्ध कार्यक्रम क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हाल ही में मशीनी औजारों की मांग गिर जाने के कारण भावनगर में सरकारी क्षेत्र में ग्रे आयरन फाऊंड्री सहित मशीनी औजारों के कारखाने की स्थापना करने के प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इस प्रस्ताव पर एक वर्ष या इसके लगभग मांग के रुख को देखते हुए पुनर्विचार किया जायेगा।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

India's Foreign Trade

3701. **Shri Bhogendra Jha :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of countries with which India has an adverse balance of trade ;

(b) the names of the countries out of them which are not prepared to import manufactured goods from India;

(c) The measures being adopted by Government in this regard ?;

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce(Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) The countries with which India has an advance adverse balance of trade are :—

France, Italy, Federal Republic of Germany, Netherlands, Austria, Denmark, Norway, Portugal, Sweden, Switzerland, , Finland, Spain, Turkey, Afghanistan, Australia, Burma, Malayasia, (excluding Singapore), Cambodia, Iran, Nepal, Pakistan, Thialand,. Saudi Arabia, U.A.R., Kenya, Other East African Countries, Tanzania, Uganda, Canada, U.S.A., Argentina, Maxico, Peru, Puerto Rico, Hungary and Poland.

(b) None of the aforesaid countries has shown unwillingness to import manufactured goods from India. However, it is understood that U.S.A., Canada, Argentina and some other Latin American countries have imposed certain restriction e.g. import-quota system, on the import of non-essential items from India and other countries.

(c) India is persistently striving through international forums like the UNCTAD, GATT etc., as also through direct approaches to the concerned Governments for greater access of Indian products to the markets of those countries.

Introduction of High Speed Train on Delhi-Howrah Line

3702. **Shri Bhogendra Jha :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the experiments in regard to the running of Express trains at the speed of 120 kilometeres per hour have since been completed and if so, the result thereof ;

(b) whether the said express trains are proposed to be introduced on the Delhi-Howrah lines in the near future and if so, when it would be introduced ;

(c) whether the said train would run via Patna; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The trials and investigations of the running of trains at 120 kilometeres per hour are still in progress.

(b) Yes, but no precise date regarding introduction of this train can be given at this stage.

(c) No.

(d) The proposed train is intended to provide a fast inter-city service between Howrah and Delhi and the shorter route has been preferred.

Slump in various Industries

3703. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that with a view to face the slump in various industries in the country, Government have approached foreign countries tp buy the goods manufactured by the said industries;

(b) if so, the results thereof; and

(c) the names of countries which propose to buy the goods along with the quantity thereof, separately?

The Minister of Industrial Development & Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) One of the important steps intiated to combat the effect of recession on various industries, is the stepping up of exports through stronger marketing structures both for the public and the private sector. A special appeal has been issued to the selected units in the major sectors of the Industry, for cooperation in the matter. In addition, the desirability of stepping up exports of various stores manufactured in India has been prominently kept in view while discussing the possibilities of further collaboration in the economic and industrial fields with countries like Czechoslovakia, USSR, UAR, Yugoslavia etc.

(b) and (c) : It is a little too early to indicate in exact terms the results achieved so far particularly as some of the proposals are at negotiation stages.

Jobs for Unemployed Small Traders

3704. **Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme to rehabilitate or provide alternative jobs to small traders who have been rendered jobless as a result of state trading and Cooperative trading;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether any provision has been made for rendering financial grants to the poor traders to enable them to carry on their trade ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Government have no information that small traders have been rendered jobless by state trading & Cooperative trading.

(b) Does not arise.

(c) No., Sir.

Industrial Development of Rajasthan

3705. **Shri Onkarlal Bohra.** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the steps being taken by Government for the industrial development of Rajasthan;

(b) whether it is a fact that the investment in industry in Rajasthan in very low as compared to that in Maharashtra, West Bengal and other States which has affected the living standard of Rajasthan; and

(c) if so, the details in regard to the policy, if any, formulated by Govenrmnet to promote investment in private and public sector industries in Rajasthan ?

The Minister of Industrial Develcment and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) (a) to (c): The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Broad Gauge Line in Rajasthan

3706. **Shri Onkar lal Bohra :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the per capita length of railway tracks and that of broad gauge line in Rajasthan as compared to those in other States ;

(b) the steps which are being taken to provide broad gauge railway lines connecting big cities of Rajsthan; and

(c) the amount provided in the budget for increasing Railway amenites in Rajasthan ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The information about length of Railway lines is not compiled State-wise but Railway-wise. Full particulars of the route and track length of the Railway zones are given in Statement No. 8 of the 'Supplement to the Report by the Railway Board on Indian Railways—Statistical Statements for the year, 1966-67' copies of which are available in the Library of Parliament.

(b) Rajasthan is well served by a net-work of metre gauge lines. Recently a new metre gauge line ; Jaisalmer-Pokaran (105 km), has been opened to traffic in Rajasthan. In addition, a braod gauge line from Hindumalkot to Sriganganagar (27.56 km) is under construction.

(c) The proposed outlay in the Budget for 1968-69 for Jaislamer-Pokaran is Rs. 49.60 lakhs, and for Hindumalkot-Sriganganagar is Rs. 20.06 lakhs. Regarding expenditure on other Railway facilities, it is not possible to isolate the works undertaken in Rajasthan, which, along with adjoining States, is served by the Nothern and Western Railways. The development works in progress and those proposed to be undertaken in 1968-69 on these Railwasys, together with the financial outlay, are contained in the "Works, Machinery and Rolling Stock programmes of the Railways for 1968-69" presented to Parliament along with the Railway Budget.

Thacker Committee

3707. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether all the facilities are not being provided by Government to the Industrial Licencing Policy Enquiry Commission headed by Prof. M. S. Thacker ; and

(b) whether any proposal to dissolve this Committee is under the consideration of Government ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) All necessary facilities are being provided in the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee headed by Prof. M. S. Thacker.

(b) No. Sir.

Small Scale Industries Corporation

3708. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether any scheme to form a consortium of Small Scale Industries Corporation is under consideration; and

(b) if so, when the said consortium is porposed to be formed ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) & (b). The Ad Hoc Committee set up by the Small Scale Industries Board to study the working of State Small Industries is understood to have suggested the formation of a Consortium of State Small Industires Corporations with a view to ensuring availability of raw materials to small scale units at a more reasonable price. Their report is expected shortly.

तकनीकी विकास महानिदेशालय

3709. **श्री राम चरण :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तकनीकी विकास महानिदेशालय में काम कर रहे विकास अधिकारियों / सहायक विकास अधिकारियों / कनिष्ठ क्षेत्र अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उपरोक्त अधिकारियों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित आदिम जातियां के अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ग) औद्योगिक सलाहकारों की संख्या कितनी है; और

(घ) औद्योगिक सलाहाकारों में अनुसूचित जातियां/अनुसूचित आदिम जातियों की संख्या कितनी है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ): अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण साथ में नत्थी है ? **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 431/ 68]।**

बेबी कारों का निर्माण

3710. श्री राम चरण : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि पूना के श्री एस० डी० कुलकर्णी ने एक बेबी कार बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसी कारों का निर्माण करने के लिए उनकी सहायता करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) श्री एस० डी० कुलकर्णी ने बेबी कार का एक आद्यरूप तैयार किया है ।

(ख) इसी प्रकार की अन्य योजनाओं के साथ श्री कुलकर्णी की योजना भी सरकार के विचाराधीन है । इस पर निर्णय करने में कुछ समय लगने की सम्भालवना है ।

महेश्वरी देवी पटसन मिल, कानपुर

3711. श्री रमानी : श्री भगवान दास :
श्री गणेश घोष : श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महेश्वरी देवी पटसन मिल, कानपुर के चालू करने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस मिल के कब तक चालू किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : महेश्वरी देवी जूट मिल, कानपुर को 27 सितम्बर, 1967 को नीलाम किया गया था । चूंकि अधिकतम बोली मिल के ऋणों के भुगतान के लिए अपर्याप्त समझी गयी अतः उसे बेचने की पुष्टि नहीं की गयी । इस बिक्री के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा आपत्ति उठाने का विचार था । ऐसा समझा जाता है कि कम्पनी ने भी आपत्ति की है । ऐसी परिस्थितियों में यह बताना संभव नही कि मिल दुबारा कब खुलेगी ।

टसर रेशम का निर्यात

3712. श्री धीरेश्वर कलिता : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हाल के वर्षों में टसर रेशम का निर्यात कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उसका निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) जी, हां ।

(ख) टसर के निर्यातों में गिरावट के कुछ कारण ये हैं :—

(1) अमरीकी बाजारों में, जहां हमारे टसर के कुल निर्यात का 70—75 प्रतिशत भाग बिकता था, हमारे माल की बिक्री में भारी गिरावट;

(2) फैशन में परिवर्तन ;

(3) अन्य देशों की मारफत चीनी टसर का बाजार में आना ; तथा

(4) संश्लिष्ट टसर से प्रतियोगिता ।

(ग) जिन कारणों से टसर के निर्यात में गिरावट हुई, उनका अध्ययन करके टसर के निर्यात को बढ़ाने के उपाय सुझाने हेतु जनवरी, 1968 में एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल अमरीका तथा छः अन्य देशों को भेजा गया । प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है ।

रेयन और सिन्थेटिक टैक्सटाइल का निर्यात

3713. श्री धीरेश्वर कलिता : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967 में रेयन और सिन्थेटिक टैक्सटाइल का निर्यात कम हो गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) उनका निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) जी हां ।

(ख) कतिपय प्रतिकूल बाह्य कारणों से, जैसे कि आयात करने वाले कुछ देशों में राजनीतिक गड़बड़ी बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा आदि, भारत से रेयन तथा कृत्रिम धागे के कपड़े का कुल निर्यात 1964 से कम होता जा रहा है । जून, 1966 से आर्ट सिल्क कपड़े के लिये निर्यात संवर्धन योजना की समाप्ति के कारण निर्यात व्यापार को और भी धक्का लगा है ।

(ग) रेयन तथा सिन्थेटिक कपड़े के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्न कदम उठाये गए हैं :—

(1) सेलूलोज आर्ट सिल्क कपड़ों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने एक योजना चालू की है, जिसमें जहाज तक निःशुल्क मूल्य के 25 प्रतिशत से अनधिक नकद सहायता देने का उपबन्ध है । यह सहायता राज्य व्यापार निगम द्वारा दी जाती है ।

(2) सिन्थेटिक कपड़े के निर्यात को बढ़ाने के लिए हाल ही में यह निर्णय किया गया है कि यदि कोई निर्यातक निर्यात किये गये कपड़े में 1 किलोग्राम नाइलोन

यार्न सिद्ध करता है तो उसे 1.2 किलोग्राम नाईलोन यार्न आयात करने की अनुमति दी जायेगी ।

(3) आर्ट सिल्क कपड़े के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये तीन सदस्यों के एक विपणन दल ने हाल ही में कनाडा, ब्रिटेन हालैंड, बेल्जियम, इटली, ईराक और कीनिया का दौरा किया था ।

लोहे और इस्पात का निर्यात

3714. श्री धीरेश्वर कलिता : क्या **इस्पात, खान** तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोहे और इस्पात के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ;

(ख) क्या उन उपायों के फलस्वरूप पिछले दो वर्षों में लोहे और इस्पात के निर्यात में कोई वृद्धि हुई है, यदि हाँ, तो कितनी मात्रा में ;

(ग) 1966–67 में लोहे और इस्पात के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है; और

(घ) 1968–69 के दौरान लोहे और इस्पात के निर्यात की क्या संभावनाएं हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) निर्यात को बढ़ाने के लिए स्टील एक्सपोर्टरस एसोसीएशन के नाम से उत्पादकों और निर्यातकों की एक संस्था बनाई गई है । विदेशों में लोहे और इस्पात के लिए मार्केट बनाने के उद्देश्य से सरकार सर्वेक्षण दल भेजने में प्रोत्साहन दे रही है। इसी उद्देश्य से स्टील एक्सपोर्टरस एसोसीएशन की एक टीम आजकल दक्षिण पूर्वी एशिया का दौरा कर रही है । हल्के इंजीनियरी उत्पादकों की जिनमें इस्पात भी शामिल है, खपत के लिए हालही में एक टीम ने संयुक्त राष्ट्र अमरीका के बाजारों का अध्ययन किया है । हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने भी अपने उत्पादों के लिए कई बाजारों का सर्वेक्षण किया है। संयुक्त राष्ट्रों के व्यापार और विकास सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हुए कुछ शिष्ट मंडलों को इस्पात कारखाने दिखाये गये हैं जिससे हमारे इस्पात उत्पादों में उनकी रुचि बढ़े ।

इसके अलावा लोहे और इस्पात के निर्यात के लिए राज-सहायता भी दी जा रही है ।

(ख) और (ग) : 1965–66 में लोहे और इस्पात के निर्यात से 10 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई । 1966–67 में यह बढ़कर 20 करोड़ रुपये हो गई। आशा है कि 1967–68 में यह 50 करोड़ रुपये से ऊपर हो जाएगी ।

(घ) ऐसी संभावना है कि 1968–69 में लगभग 19.5 लाख टन लोहे और इस्पात का निर्यात होगा जिससे 80 करोड़ रुपये के लगभग विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी ।

Foundry in Punjab

3715. **Shri Yashpal Singh :** Will the Minister of **Industrial Develpoment and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Punjab Government proposed to set up a Foundry in Punjab;

(b) whether any assistance has been sought by the Punjab Government from the Central Government in this regard ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Export of Crushed Bones

3717. **Shri Maharaj Singh Bharti :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some foreign countries have complained that the crushed bones exported from India contain human bones ;

(b) whether they have also complained that the mixing of bones of diseased human beings has had adverse effects on the health of their workers ; and

(c) if so, the names of Countries which have complained and the action taken by Government in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c) It was reported in certain section of press in] U. K., Paris, Brussels and U. S. A., that crushed bones exported from India were mixed with human bones. It was also reported that a docker at Dunkirk port died of Anthrax which he was alleged to have contracted by unloading crushed bones from a ship from India. Dr. Harvey, a British medical authortiy, along with a delegation visited India, studied the manufacturing process at various units in India, and returned satisfied that crusehd bones from India did not contain human bones. Moreover, Indian missions in Loindoin, Paris, Brussels and USA have been informed that the press reports were totally false and they have countered the propaganda suitably.

Rock Phosphate

3718. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether Government have entered into "Operation Soft Rock" agreement with the G overnment of U.S.A. in January, 1968;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether exploration analysis and exploitation of phosphate deposits fall within the p urview of that agreement; and

(d) whether the technical know-how for converting rock phosphate of low percentage into a more useful quality is also a part of the agreement ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) and (b) An agreement was signed between the Government of India and the U.S.A. I. D. on 5-1-1968 for the exploration of rock phosphate deposits in the country. The agreement provides for

reconnaissance Geology of the Potential Phosphate Bearing Areas, Detailed Strat igraphic and Structural Mapping, Trenching, Drilling and Sampling of the Phosphate Horizons, Chemical Analysis and Beneficiation Tests, Training of Indian Personnel on the job by the American expets in the latest phosphate rock reconnaissance methods, chemical analysis and beneficiation techniques. The Government of India will appoint the counterpart Indian officials on the project and their assistants.

The agreeement will terminate at the expiry of about twenty months.

The United States Government will provide one short-term Consultant for four months, two geologists, one physical Stratigrapher, one Extractive Metallurgist for twenty months each and one Chemist for 2½ months.

The dollar cost to the extent of $250,000 will be financed under the Agency for International Development Constultancy Services Loan No. 386-H-115. The rupee cost of the project of not more than Rs. 10,23,000 will be financed by India.

(c) The agreement provideds only for Chemical analysis of the rock phosphate samples obtained from various areas. The exploitation does not fall within its purview.

(d) Yes, Sir.

दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) के कमर्शियल इन्सपेक्टर

3719. **श्री बेणीशंकर शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन के कुछ कमर्शियल इन्सपैक्टरों का, जो अम्बाला-शिमला सैक्शन पर कार्य कर रहे हैं सब्जी मंडी दिल्ली में मुख्यालय है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्हें ए श्रेणी के नगर के भत्ते और रेलवे क्वार्टर की सुविधा दी जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) सूचना मंगायी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

3720 **श्री प्र० कु० घोष** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री 7 जुलाई, 1967 के अल्प सूचना प्रश्न संख्या 25 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कर्मचारियों की 52 मांगों में से किन 16 अथवा 17 मांगों को स्वीकार किया गया है ; और

(ख) उनको क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

अन्तर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भारत द्वारा भाग लेना

3721 **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 के दौरान भारत ने विदेशों में कितने मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लिया और यह किस किस स्थान पर हुए ;

(ख) विदेशी मुद्रा के रूप में प्रत्येक मेले और प्रदर्शनी पर कितना कितना धन व्यय हुआ ;

(ग) प्रत्येक मेले और प्रदर्शनी से कुल कितनी कितनी आय हुई; और

(घ) भारतीय उत्पादों के लिये क्रयादेश लेने के रूप में इन मेलों में भाग लेने से क्या लाभ प्राप्त हुए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने 1967 के वर्ष में वाणिज्य मंत्रालय के प्रदर्शनी निदेशालय के माध्यम से 10 अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लिया। इन मेलों, प्रदर्शनियों तथा प्रत्येक में भाग लेने की व्यवस्था पर हुए विदेशी मुद्रा में व्यय की एक सूची (अंग्रेजी में) संलग्न है।
[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 432/68]

(ग) और (घ) इन मेलों/ प्रदर्शनियों में लगभग 108 लाख रु० मूल्य के व्यापार की बातचीत हुई। इस के अतिरिक्त मौके पर लगभग 128 लाख रु० की मूल्य की बिक्री हुई। परम्परागत एवं अपरम्परागत, दोनों प्रकार की मदों के लिये व्यापार संबंधी अनेक पूछताछें हुई जिन्हें अनुवर्ती कार्यवाही के लिये भारत के संबद्ध निर्यातकों, निर्माताओं तथा संगठनों को भेज दिया गया है। इन के परिणामस्वरूप काफी अतिरिक्त व्यापार होने की आशा है।

विदेशों में कुछ मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने की व्यवस्था, व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों की भारतीय परिषद्, बम्बई, विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों, वस्तु बोर्डों तथा निगमों द्वारा की जाती है। इन के भाग लेने संबंधी जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है ; अतः उन से प्राप्त करने के बाद में दे दी जायेगी।

तेनालि-रेपल्लि और वर्दवान कठवा रेलवे लाइनें

3722. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेनालि-रेपल्लि और वर्दवान-वठवा रेलवे लाइनों के खरीदने पर कितना मूल्य दिया गया ;

(ख) आगामी दो वर्षों में इन लाइनों पर कितना धन व्यय होने की संभावना है ; और

(ग) इस अवधि में इन लाइनों से कितनी आय होने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) तेनाली-रेपल्लि रेलवे और बर्दबान-क्टवा रेलवे पर क्रमशः 18.19 लाख रुपये और 26.25 लाख रूपये के क्रय मूल्य की अदायगी की गयी ;

(ख) और (ग) आगामी दो वर्षों में इन दोनों रेलों पर खर्च और आमदनी के आंकड़ों का अनुमान इस प्रकार है :—

		(लाख रूपयों में)	
		बर्दधान-कटवा रेलवे	तेनाली-रेपल्लि रेलवे
आमदनी	1968–69	10.00	16.93
	1969–70	10.18	17.77
खर्च	1968–69	13.08	12.50
	1969–70	13.20	13.00

रेलवे कमीशियल क्लर्क

3723. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कामर्शियल क्लर्कों की पदालि के वार्षिक पुनरीक्षण के आधार पर रेलवे बोर्ड ने 15 मार्च, 1958 के पत्र सं० ई (एस) 1—57/टी० आर० बी० 19 में आदेश दिया था कि कमर्शियल क्लर्कों के कुछ पदों का दर्जा बढ़ा दिया जाये परन्तु उन पदों के दर्जे को अप्रैल, 1963 तक बढ़ाया नहीं गया था और इस प्रकार कमर्शियल क्लर्कों को बहुत हानि हुई ;

(ख) क्या यह भी सच है कि डिवीजनों ने अपनी 1 अप्रैल, 1961 की पदालियों की स्थिति में उन पदों को बढ़ाया हुआ दिखाया था परन्तु वास्तव में कमर्शियल क्लर्कों को अप्रैल, 1963 से पदोन्नत किया गया था ; और

(ग) इन पदों के दर्जा बढ़ाने में विलम्ब के कारण कमर्शियल क्लर्कों को कितनी हानि हुई थी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) सूचना मंगायी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय रेलों में कमर्शियल क्लर्कों के पास यातयात सम्बन्धी देनदारी

3724. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 के दौरान लेखा कार्यालय द्वारा भारतीय रेलवे के कमर्शियल क्लर्कों के विरुद्ध कितनी देनदारी डाली गई थी ;

(ख) उक्त अवधि में यातायात के रूप में कमर्शियल क्लर्कों के वेतन से कितनी राशि काटी गई है ;

(ग) रेलवे के कर्मचारियों के नाम इतनी अधिक राशि डालने के क्या कारण हैं ; और

(घ) कर्मचारियों के नाम कम राशियां डाली जायें, इसके लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा : (क) से (घ) सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलो में कमर्शियल क्लर्क वर्ग के लिये छुट्टी रिजर्व कर्मचारी

3725. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने अपने दिनांक 12 जुलाई, 1948 के पत्र संख्या ई० 48 डी०एस०आई०—2 (आर) के अनुसार कमर्शियल क्लर्क 62 वर्ग के लिये 24 प्रतिशत छुट्टी रिजर्व कर्मचारियों की सिफारिश की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे प्रशासन बहुत कम प्रतिशत छुट्टी रिजर्व कर्मचारी रख रहे हैं जिसके फलस्वरूप कमर्शियल क्लर्कों को समय पर छुट्टी लेने में बहुत मुश्किल होती है; और

(ग) क्या यह सच है कि रेलवे प्रशासन रिक्त स्थानों को खाली रखता है और छुट्टी रिजर्व कर्मचारियों को लम्बे समय तक इन स्थानों पर लगाये रखता है जिसके कारण कर्मचारियों को आवश्यकता के समय छुट्टी नहीं मिलती है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं। लेकिन रेलवे बोर्ड के 14-8-1951 के पत्र संख्या ई(ए०डी०जे०) 48 एल०आर-1 के अनुसार वाणिज्यिक क्लर्कों के मामले में एवजी कर्मचारियों की प्रतिशतता 15 से 25 तक निर्धारित की गयी थी जो आमतौर पर न्यूनतम निर्धारित तिशतता के अनुसार ही रखे जाते हैं।

(ख) और (ग). सूचना मगायी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे में कमशियल क्लर्क

3726. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के परिवहन, यातायात तथा कमशियल विभागों में कई उच्च श्रेणी के पदों को खाली रखा जाता है तथा इस प्रकार कमशियल क्लर्क संवर्ग के वरिष्ठ व्यक्तियों को उनकी पदोन्नति के अवसर से वंचित कर दिया जाता है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि पूर्व तथा पश्चिम रेलवे में कमशियल क्लर्कों को चार अथवा पांच वर्ष तक लगातार काम करने पर भी स्थायी नहीं बनाया गया है जबकि नियमों के अनुसार 18 महीने काम करने पर उन्हें स्थायी बनाया जाना चाहिये था ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). सूचना मगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

खादी के माल का निर्यात

3727. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत एक वर्ष में खादी के माल का निर्यात, विशेषतः पश्चिमी विकसित देशों को, कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं और उन से अब तक कितनी सफलता मिली है; और

(ग) यदि नहीं, तो वर्ष 1967 के दौरान पश्चिम के विकसित देशों को देश वार कितना खादी का माल निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

धातु मिश्रित इस्पात का उत्पादन

3728. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने धातुमिश्रित इस्पात के उत्पादन के सम्बन्ध में कोई नई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो देश में इस समय धातु मिश्रित इस्पात का कितना उत्पादन होता है तथा यदि इसकी देश व विदेश में कोई मांग है तो कितनी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में इसका कितना उत्पादन होता है; और

(घ) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में 1967 में धातुमिश्रित इस्पात का उत्पादन बढ़ा अथवा कम हुआ था ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). अबले कुछ वर्षों के लिए मिश्रित इस्पात की मांग का पुन: अनुमान लगाया जा रहा है। मिश्रित इस्पात के उत्पादन की अब तक अधिष्ठापित की गई क्षमता 150,000 टन प्रति वर्ष से ऊपर है। लगभग आधी क्षमता निजी क्षेत्र में है। वर्ष 1967 में निजी क्षेत्र की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है।

धातु मिश्रित इस्पात का उत्पादन

3729. **श्री शिवचन्द्र झा:** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि धातुमिश्रित इस्पात का उत्पादन करने के लिये टाटा बन्धुओं को लाइसेंस दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा यह लाइसेंस किस शर्त पर दिया गया है; और

(ग) क्या टाटा बन्धुओं ने उस लाइसेंस का प्रयोग किया है और यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) से (ग). मिश्रित इस्पात के लिए लाइसेंस देने का काम उद्योगों की अग्रता-सूची (merit list) में है और टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के आवेदन-पत्र पर उन्हें प्रति वर्ष 50,000 टन मिश्रित और विशेष इस्पात के उत्पादन के लिए एक नया कारखाना लगाने हेतु आशय-पत्र दिया गया था। टाटा कम्पनी स योजना को स्थगित करना चाहती थी, अतः उन्हें सूचित किया गया कि उनको दिये गये आशय-पत्र की अवधि समाप्त समझें।

सिगरेटों तथा अफीम का उत्पादन

3730. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सिगरेटों और अफीम के उत्पादन को बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो देश का सिगरेटों और अफीम का वर्तमान कुल कितना उत्पादन है और इसकी तुलना में इनकी देश में और विदेशों में कितनी मांग है; और

(घ) 1968-69 में इन दोनों के उत्पादन लक्ष्य क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ)
(1) सिगरेट उद्योग : योजना में सिगरेट उद्योग के लिये कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

फिर भी सिगरेटों की मांग के अनुरूप उत्पादन करने के लिये इस उद्योग को सहायता दी जाती है। पालियों के आधार पर इसकी स्थापित क्षमता 4918.9 करोड़ सिगरेटें प्रति वर्ष है। पिछले तीन वर्षों में सिगरेटों का वास्तविक उत्पादन नीचे दिया गया है —

वर्ष	उत्पादन (करोड़ में)
1965	5,543.9
1966	5,822.6
1967	5,381.5

सिगरेटों का बहुत थोड़ा निर्यात किया जाता है।

(2) अफ़ीम उद्योग : अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा के अनुसार अफीम की खपत केवल वैज्ञानिक कार्यों तथा औषधियों में इस्तेमाल तक सीमित है और अफीम के निर्यात/आयात का सरकार द्वारा नियन्त्रण किया जाता है। अतः विश्व में कच्ची अफीम की मांग केवल औषधियों तक सीमित है।

किसी वर्ष में कुल कितनी अफीम तैयार की जायगी तथा अगले वर्ष भारत द्वारा कितनी मात्रा में उसका निर्यात किये जाने की संभावना है यह मुख्यता औषधियों में इस्तेमाल किये जाने के लिये विश्व की मांग पर निर्भर करता है। 1964-65 से 1966-67 में तैयार की गई अफीम की मात्रा निम्न प्रकार थी:—

वर्ष	तैयार की गई मात्रा (टनों में)
1964-65	625
1965-66	436
1966-67	470

1968-69 में कुल 860 टन अफीम तैयार करने की योजना बनाई गई है।

Mineral Deposits in Bihar

3731. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Geological Survey of India and the Geological Department of Bihar Government have discovered Copper, Zinc and Lead deposits in village Baragunda in District Hazaribagh ;

(b) if so, the estimated quantity of the deposits of the above metals ;

(c) when this survey was conducted and the number of officials of the Geological Survey Department who were included in the team ; and

(d) the expenditure incurred by Government thereon ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) The old workings of copper, lead and zinc at Baragunda are known to the Geological Survey of India since 1850.

(b) and (c). Detailed geophysical surveys carried out earlier in the region of old workings and the adjacent neighbourhood did not indicate any extensive anomalies except few feeble anomalies. Drilling operations commeneed in the area in January, 1966

in collaboration with the Government of Bihar. 35 personnel of the Geological Survey of India and two offices of the Government of Bihar have been deployed for this investigation. Till the end of January, 1968, 14 bore holes were drilled in the main Baragunda Block and copper, mineralisation was intersected in 11 bore holes. The width of the mineralised zone varies from 2.5 to 3 metres with copper content ranging between 1.5 to 2%. Drilling operations are in progress. Estimated reserves of copper are approximately 2.5 million tonnes.

(d) No separate account is maintained of investigations carried out by the Geological Survey of India. The expenditure is met from the sanctioned budget of the Geological Survey of India.

Electrification of Stations on Western and South Eastern Railway

3732. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of railway stations on the Western and South Eastern Railways;

(b) the number of stations which are electrified and the number of stations without electricity; and

(c) the action being taken by Government to supply electrictiy to the stations which have not been electrified so far ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) 1369 on Western Railway. 681 on South Eastern Railway.

(b) 490 Electrified (Western Railway)
879 Un-electrified (Western Railway)
404 Electrified (S. E. Railway)
277 Un-electrified (S. E. Railway)

(c) Electrification of stations is done on programmed basis as and when power supply is readily available at economical rates.

Theft of Cash Boxes from Frontier Mail

3733. **Shri Hukum Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3675 on the 8th December, 1967 and state :

(a) the details of property stolen, the name of each item and the approximate value thereof ;

(b) the particulars of the five persons arrested and whether they have been convicted by the court; and

(c) the details in regard to sentences passed on each and the fine imposed on them ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The details of property stolen which was recovered in full are given below :

(i) *Travelling Cash Safe No. 119/Delhi.*

Cash	Rs. 48,384·42
Credit Note	Rs. 7,964·90
Bank Challans	Rs. 2,00,901·03
Cheques	Rs. 7,464·76
TOTAL	Rs. 2,64,715·11

(a) **Travelling Cash Safe No. 76/AF**

Cash	Rs.	6,722·51
Cheque	Rs.	245·32
TOTAL :	Rs.	6,967.83
GRAND TOTAL :	Rs.	2,71,682·94

(b) 1. Pooran *alias* Narain, ex-Waterman of Western Railway, Kota.
2. Ibrahim s/o Ramzani.
3. Kamal Singh s/o Panna Singh
4. Madan Singh s/o Gopi Singh
5. Tola Ram s/o Daya Ram

} All residents of Ujjain.

The accused have been challaned by Government Railway Police, Shamgarh in the court of Railway Magistrate, Indore and the case is pending trial.

(c) Does not arise.

दरमियाने तथा मोटे कपड़े का निर्यात

3734. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के दरमियाने तथा मोटे कपड़े के निर्यात में कमी आती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो कपड़ा उद्योग को अधिक निर्यात प्रोत्साहन देने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस संबंध में और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सूती कपड़े के निर्यात में कुछ गिरावट आई है जिसमें दरमियाना तथा मोटा कपड़ा भी शामिल है ।

(ख) सरकार की स्वीकृति से भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ ने 1-9-1967 से एक स्वैच्छिक निर्यात सहायता योजना आरंभ की है जिसमें चयनात्मक आधार पर सूती कपड़ों के निर्यात पर नकद सहायता की व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त कोरे कपड़े को छोड़कर अन्य सूती कपड़े के निर्यातकों को अपने निर्यात के जहाज तक निःशुल्क मूल्य पर 5 परसेंट तक रंजक तथा रसायनों के लिये पुनर्भरण आयात लाइसेंस प्राप्त करने का हक है ।

(ग) सूती कपड़े के निर्यातों में सुधार के लक्षण दिखाई देते हैं । यथावाश्यक कार्यवाही करने के लिये सरकार द्वारा स्थिति की निरंतर समीक्षा की जाती है ।

रेलवे विद्युतीकरण योजना के फालतू कर्मचारी

3735. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विद्युतीकरण योजना के फालतू कर्मचारियों को बरारबर की अन्य नौकरियां दे दी गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो कितने कर्मचारियों की छंटनी की जा चुकी है अथवा छंटनी किये जाने की संभावना है; और

(ग) उसको काम पर लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Prices of Jute

3736. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that jute is selling at a price much lower than the lowest price fixed by Government ;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action taken by Government to maintain the prices ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Safi Qureshi): (a) to (c). Prices of jute have at times been ruling slightly below the minimum support level. During January and February 1968 prices were more or less firm and ruled above these levels. Since then there has been a tendancy for prices to sag somewhat in the Calcutta market, although prices in the secondary markets were ruling at or above the derivative mi nima. The present weakness is largely due to expectations of an early crop in the next season due to timely rains and partly due to depressed conditions in the jute goods market. The State Trading Corporation has extensively publicised its readiness to buy at the minimum price and are also intensifying their purchase operations.

Soyabean Oil with S.T.C.

3737. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether soyabean oil worth about Rs. 13.50 crores is laying with the State Trading Corporation ;

(b) whether vansapati ghee manufacturers are not prepared to purchase it; and

(c) if so, the action taken by the Corporation for its disposal ?

The Deputy Minister of in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) 42,120 tonnes of soyabean oil valued at Rs. 10·31 crores approximately was in stock with the S.T.C. on 6-3-1968.

(b) Vanaspati manufacturers are, at present, not lifting soyabean oil due to the steep fall in the internal prices of groundnut oil since the start of the current groundnut oil season.

(c) The situation is being carefully watched by the Corporation and suitable action for disposal of the stocks will be taken as and when considered necessary, consistent with the necessity of maintaining a buffer stock of edible oils in the country to ensure stability in the internal prices for oils.

Export Incentive Scheme

3738. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state ;

(a) whether Government proposed to revive the export incentive scheme, which was withdrawn after the devaluation of the rupee ;

(b) whether Government also proposed to link imports with exports made by industries ;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) the other measures which Government propose to adopt to boost exports?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) The Government do not proposed to revive the export incentive scheme that was in force prior to devaluation of the rupee.

(b) and (c): Certain suggestions for correlation between the imports allow to sections industry and their export performance are under examination.

(d) Suggestions received by Government for boosting exports are considered carefully. Decisions recently announced include reduction or abolition of export duties, increase in cash assistance on selected export products and an income-tax concession to promote development of export marketing.

खेल कूद सामान का उद्योग

3739. **डा० रानेन सेन :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खेल-कूद सामान उद्योग संकट से गुजर रहा है और पिछले दो वर्षों में कई कारखाने बन्द पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्तमान संकट को दूर करने के लिये इस उद्योग को मदद देने के हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जी, नहीं। किन्तु इस उद्योग पर बड़े तथा छोटे क्षेत्र के अन्य बहुत से उद्योगों की भांति ही मन्दी का प्रभाव पड़ा है। और

(ग) मन्दी का सामना करने के लिये ऋण सुविधाएं बढ़ाना, निर्यात के लिये प्रोत्साहन देना, अधिक तकनीकी सहायता देना, बैंक दर में कटौती करना जैसे कई कारगर कदम उठाये गये हैं।

अलौह धातु

3740. **श्री जि० मो० विश्वास :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अलौह धातुओं की कितनी मांग है तथा यह मांग देशीय उत्पादन से कितनी पूरी हो जाती है;

(ख) अलौह धातुओं का प्रति वर्ष कितना आयात किया जाता है तथा 1966 और 1967 में अलौह धातुओं के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई;

(ग) 1968 में आयातित अलौह धातुओं की कुल कितनी मांग होने का अनुमान है तथा उनका मूल्य क्या होगा; और

(घ) देश में अलौह धातुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्याए** एल० टी० 433/68]]

Pilferage on Railways

3741. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the amount of goods pilfered from Railways and the amount of the pilfered goods recovered during the last one year ; and

(b) the total number of persons arrested in connection with the pilferage and the number of those among them who were Government servants ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) (i) Value of Goods stolen and pilfered.	Rs.	33,92,193
(ii) Value of goods recovered.	Rs.	7,44,369
(b) (i) Total number arrested		4,416
(ii) Number of Railwaymen arrested.		1,133

Industries in Delhi

3742. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have ascertained the nature of difficulties being faced by industries in Delhi ;

(b) if so, the measure proposed to be adopted in this regard ;

(c) whether Government have received any memorandum from industrialists in this connection; and

(d) if so, the details thereof and the action taken thereon?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed):

(a) to (f) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

छोटे पैमाने पर रबड़ की खेती

3743. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पैमाने पर रबड़ की खेती करने वाले व्यक्तियों की समस्याओं की जांच करने के लिये नियुक्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Industrial Production

3744. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the indices of the industrial production during the last six months;

(b) whether the recessionery trends have shown any decline ; and

(c) the measures being adopted by Government to step up industrial production ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A.) Ahmed (a) The indices of Industrial Production (Provisional) seasonally adjusted (Base 1956-100) since April 1967 are as follows :

April, 1967	186·2
May	194·3
June	199·1
July	192·1
August	195·9
September	197·6
October	196·1
November	197·3
December January, 1968 February	Not available

(b) The production in some of the worst affected industries due to recession, has started improving to some extent; although it is not possible to indicate yet the exact extent of improvement.

(c) The measures adopted by Government to step up production include the review of the various developmental programmes with a view to reviving the demand for capital goods to the extent possible ; encouraging diversification in the manufacturing programmes of the affected industries, emphasis on the development of regular export markets through stronger marketing structures both for the public and private sectors ; banning of imports to the extent the indigenous capacity can meet the requirements, including a review of imports already authorised but not irrevocably committed, and announcement of liberalised credit policy including the further announcement about the reduction in Bank Rate.

Expansion of TISCO and IISCO

3745. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the details of schemes sanctioned in regard to the expansion of IISCO and TISCO during the Fourth Five Year Plan ;

(b) whether the loans advanced to them after Independence (in regard to which new agreements for their repayment had been signed) have been fully repaid ; and

(c) if not, the present posibition in this regard ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) No expansions of Indian Iron and Steel Company Ltd. and Tata Iron and Steel Company Ltd. have been sanctioned during the Fourth Five Year Plan. Indian Iron and Steel Company. Ltd. are currently rengaged in expanding their yearly production capacity from 1 million to 1·3 million in got tonnes. The Draft Outline of the Fourth Five Year envisages a target capacity of 2·2 million in got tonnes per year for Tata Iron & Steel Co.

(b) No, Sir.

(c) The Companies are repaying the special advances granted to them as per the revised Agreements entered into with them in 1966. According to these Agreements, the final instalment of the principal ammount of the loan is payable on 31st March, 1972.

Educational facilities to Disabled Children of Railway Employees.

3746. **Shri Madhu Limaye.** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government have received any memorandum for providing educational facilities and special amenities in service to the disabled children of railway employees ;

(b) if so, the facilities which are available to them at present ; and

(c) the further facilities proposed to be provided to such children ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) (a) No.

(b) and (c). Nil.

हेयर बैल्टिक टाप्स का नियतन

3747. **श्री मधु लिमये :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा आयुक्त द्वारा हेयर बैल्टिग टाप्स की शीघ्र मंजूरी न देने में लापरवाही के कारण इस सामान का बड़ा भाग अभी मंजूर नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सामान खराब होता जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो लगभग कितने मूल्य की हानि हुई है; और

(घ) क्या सरकार इस मामले की जांच कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) वस्त्र आयुक्त ने उद्योग को हेयर बैल्टिग टाप्स की शीघ्र मंजूरी देने में कोई लापरवाही नहीं की। परन्तु दो मुकदमों के कारण—एक पंजाब उच्च न्यायालय में और दूसरा बम्बई उच्च न्यायालय में—नियतन रुक गया। इसी बीच कुछ हेयर बैल्टिग टाप्स के खराब हो जाने की सूचना मिली है। वस्त्र समिति को इसका पता लगाने के लिये कहा गया है कि आया यह माल खराब हो गया था और अभी उसके प्रतिवेदन मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है।

राजस्थान में जिन्क स्पैल्टर

3748 **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लौह अयस्क की कमी के कारण राजस्थान में जिन्क स्पैल्टर पूरे पैमाने पर कार्य नहीं कर रहा है; और

(ख) इस स्थिति में सुधार के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) नहीं, महोदय। जस्ता प्रद्रावक इस समय अपनी पूरी क्षमता के अनुसार काम

कर रहा है और इसकी जस्ता संकेन्द्रकों की आवश्यकताएं खानों के वर्तमान उत्पादन से तथा संयंत्र चालू होने के पहले से एकत्रित हुए संग्रह में से पूरी की जा रही है। उस कठिनाई को हल करने के लिये जो उस समय उत्पन्न हो सकती है जब इकट्ठे हुए संग्रह लगभग 6–7 महीनों में समाप्त हो जायेंगे; खानों से अयस्क/संकेन्द्रकों का उत्पादन बढ़ाने के लिये कार्यवाही की जा चुकी है। किसी भी कमी को पूरा करने के लिये आवश्यकतानुसार विदेशों से संकेन्द्रकों के आयात करने की संभावनाएं ढूंढने की कार्यवाही की जा रही है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाना

3749 **श्री श्रद्धाकार सूपकार :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन का एक विशेषज्ञ दल दुर्गापुर इस्पात कारखाने के विस्तार कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिये वहां गया था; और

(ख) क्या उस कारखाने का और विस्तार किये जाने की सम्भावना है तथा उस पर कितना धन व्यय होगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस समय दुर्गापुर इस्पात कारखाने का और अधिक विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Shortage of Battery Cells

3750. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state

(a) whether it is a fact that battery and torch and radio cells are not available in the capital and also in the country;

(b) if so, the action taken by Government in this regard;

(c) the names of factories which exported these cells to the foreign countries during the last two years as also the value of cells exported by them ; and

(d) the annual production of cells in the country at present ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b). While there has been some shortage during last year due to strike and lock out in one of the manufacturing units, the supply position has considerably improved now. It may also be stated that the shortage is more in respect of a popular brand of cells, the production of which was affected by the strike. The overall position is expected to improve soon with the commissioning of two new Plants, one at Hyderabad. and anothere at Allahabad.

(c) M/s. Union Carbide India Ltd., are the only exporters and value of exports was Rs. 55.61 lakhs in 1965-66 and Rs. 53·74 lakhs in 1966-67.

(d) The prodution in 1967 was 314.46 million cells.

Quarters for Railway Gangmen in U.P.

3751. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the quarters constructed for gangman in the rural areas of Uttar Pradesh are far away from the villages, as a result of which the incidents of thefts in their quarters is very common ;

(b) if so, the number of complaints received by Government regarding the incidents of theft that took place in the quarters of the railway employees working in the rural areas of Uttar Pradesh during the last three years ;and

(c) the action taken by Government to solve this problem ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Quarters for gangmen are generally constructed near a village or at a station or near a manned level crossing,but in some cases, where no suitable sites are available within or near about the middle of the jurisdiction of the gang, quarters have to be constructed away from any habitation also. The incidence of thefts in gangmen's quarters are only occasional and not common.

(b) No figures of incidence of thefts in gangmen's quarters are available with the Railways, as complaints are usually filed by the residents direct with the State Police.

(c) Prevention of thefts is a matter for State Police to deal with. However, when new gang quarters are constructed, feasibility of siting them near the existing places of habitation is always kept in view.

Accommodation in Trains

3752. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of 1st , IInd and IIIrd Class compartments, separately, in the Railway trains that run in the country ;

(b) whether it is a fact that in most of the passanger trains, the number of 1st and IInd class compartments is more than that of the IIIrd class compartments, due to which the passengers travelling in IIIrd Class do not get seats whereas the 1st and IInd Class compartments run comparatively vacant ; and

(c) if so, the action taken by Government in this matter ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the table of the Lok Sabha.

Ludlow Jute Company Calcutta

3753. **Shri Nihal Singh** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the value of goods exported by the Ludlow Jute Company, Calcutta during the last five years and the names of the countries to which the goods were exported ;

(b) the amount of foreign exchange earned by the Company during the above period; and

(c) the share of foreign exchange earned by Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd, Shafi Qureshi) : (a) to (c). The required information is not available as statistics are not compiled on a company-wise basis.

रेलों में रेल डिब्बा अटेन्डेन्ट

3754. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे को छोड़ कर उत्तर, पूर्वोत्तर, पूर्व तथा अन्य रेलों में रेल डिब्बा अटेन्डेन्टों को ठहरने की सुविधायें प्रदान की गई हैं;

(ख) क्या उत्तर रेलवे के इलाहाबाद डिवीजन में रेल डिब्बा अटेन्डेन्टों का वाणिज्यिक विभाग से मैकेनिकल विभाग में तबादला किया जा रहा है जिससे यात्रियों को असुविधा होती है तथा रेल डिब्बा अटेन्डेंटों के पदोन्नति के क्रम में बाधा होती है;

(ग) क्या रेल डिब्बा अटेन्डेंटों को यात्रियों के टिकट अथवा पास के क्रमांक देखने का अधिकार नहीं है तथा इसके परिणामस्वरूप उन्हें बिना टिकट वाले यात्रियों को रोकने की अनमति नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस असंगति को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं । सभी रेलों में डिब्बा परिचरों को विश्राम/परिचालन कमरों आदि में विश्राम करने की सुविधा प्राप्त है बशर्ते नियमित परिचालन कर्मचारियों की आवश्यकताएं पूरी करने के बाद उनमें जगह उपलब्ध हो ।

(ख) इलाहाबाद मण्डल के डिब्बा परिचरों को वाणिज्य विभाग से यांत्रिक विभाग में स्थानान्तरित कर दिया गया है । इस प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है कि रेलों में डिब्बा परिचर वाणिज्य विभाग के अधीन होने चाहिए या यांत्रिक विभाग के ।

(ग) और (घ) डिब्बा परिचरों को, उन डिब्बों में अनधिकृत यात्रियों को दाखिल होने से रोकना होता है, जिनमें उन्हें तैनात किया जाये । अपने इस कर्त्तव्य के पालन में वे आवश्यकता पड़ने पर गाड़ी के कंडक्टर गार्ड/गार्ड की सहायता लेते हैं, जिनके पर्यवेक्षण में उन्हें काम करना होता है । इस प्रश्न पर विचार हो रहा है कि यात्री अधिकृत हैं या नहीं इसकी जांच करने के लिए डिब्बा परिचरों को यात्रियों से टिकट/पास मांगने का अधिकार दिया जा सकता है अथवा नहीं ।

बिड़ला तथा टाटाओं के उद्योग

3755. श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री 24 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1638 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच बिड़ला टाटाओं के उद्योगों के बारे में पूछी गई जानकारी प्राप्त कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो बिड़ला तथा टाटा की फर्मों ने कितने तथा किस प्रकार के उद्योगों के लाइसेंस प्राप्त करने के बारे में आवेदन-पत्र दिये हैं तथा कितने लइसेंस उन्हें मिल गये हैं और कितने आवेदन-पत्र अभी विचारधीन हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) सूचना अब भी इकट्ठी की जा रही है ।

रूस के व्यापार मंत्री की यात्रा

3756. **श्री शीवीकन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस के विदेशी व्यापार के मंत्री ने उनके मंत्रालय से दोनों देशों में व्यापार बढ़ाने के बारे में बातचीत की थी;

(ख) यदि हा, तो किन विषयों पर विचार हुआ था;

(ग) क्या क्या निर्णय किये गये थे; और

(घ) रूस के साथ व्यापार बढ़ाने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बातचीत भारत-रूस व्यापार के संबंध में हुई तथा सामान्य प्रकार की थी । भारत में हाल ही के अपने दौरे में सोवियत प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों को क्रियान्वित करने के प्रश्न पर, इस्पात तथा रेल माल डिब्बों की खरीद के विशेष प्रसंग में, बातचीत हुई ।

(घ) (1) 1968—70 की अवधि में रूस को 600000 में टन इस्पात खंडों, जिनमें बीम, चैनल तथा ऐंगल शामिल हैं, के निर्यात के लिये एक संविदा पर हस्ताक्षर किये गये हैं ।

(2) निर्यात अभिमुख उद्योगों का उत्पादन स्तर बढ़ाने के लिये तथा ऐसी औद्योगिक क्षमताओं का अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त स्तर पर विचार विमर्श पहले ही प्रारम्भ हो चुका है । माल के अधिकाधिक आदान-प्रदान की संभावनाओं का पता लगाने के लिये विभिन्न सोवियत प्रतिनिधि मंडलों तथा विशेषज्ञों के साथ, जो पहले ही भारत में हैं, बातचीत प्रारम्भ कर दी गई है ।

सिलेसिलाये कपड़ों के निर्माताओं को प्रोत्साहनस्वरूप धन

3757. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या वाणिज्य मंत्री 15 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 692 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिले सिलाये कपड़ों के उन निर्माताओं के, जिन्हें प्रोत्साहनस्वरूप धन प्राप्त हुआ था, नामों तथा उन्हें प्राप्त हुए लाभ के बारे में, इस बीच जानकारी इकट्ठी कर ली गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख) एक विवरण (अंग्रेज़ी में) संलग्न है जिसमें पंजीकृत निर्याताकों/निर्माता निर्यातकों दोनों के नामों तथा साथ ही उन्हें प्राप्त लागों को दो सूचियां दी गई हैं । [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 434/68**]

पश्चिमी बंगाल में पटसन मिलें

3758. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या वाणिज्य मंत्री 8 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3518 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने गी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में जूट मिलों के संबंध में जानकारी एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इन मिलों में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा 1966–67 में पटसन उद्योग से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी । 1966–67 वर्ष में भारत से पटसन के माल का कुल निर्यात मूल्य 235.20 करोड़ रुपये अथवा 33.04 करोड़ डालर है ।

सहायक स्टेशन मास्टरों के लिये उच्च श्रेणी के पद

3759. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में सहायक स्टेशन मास्टरों के लिये नियत उच्च श्रेणी के पदों पर अन्य श्रेणी के कर्मचारियों में से भी, जैसे गार्ड, यार्ड-मास्टर तथा यातायात प्रशिक्षु नियुक्ति की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इससे सहायक स्टेशन मास्टरों की पदोन्नति का मार्ग रुक गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 250–380 रु० के वेतन मान में पदोन्नति के जरिए भरे जाने वाले सहायक स्टेशन मास्टरों के पद 205-280 रु० के वेत मान वाले सहायक स्टेशन मास्टरों तथा क्रमश: 205–280 रु० 150–240 रु०, और 130–225 रु० के वेतन मान वाले 'ए' 'बी' और 'सी' ग्रेड के गार्डों 205–280 रु० वेतन मान वाले सहायक यार्ड–मास्टरों की पदोन्नति द्वारा प्रवरण के आधार पर भरे जाते हैं, बशर्ते उनमें कुछ निर्धारित अर्हताएं हों ।

(ख) ऐसा इसलिए है ताकि परिचालन कुशलता बनी रहे और साथ ही विभाग में सभी कोटि के कर्मचारियों के लिए साम्यिक पदोन्नति सरणि की व्यवस्था की जा सके ।

(ग) जी नहीं, क्योंकि सहायक स्टेशन मास्टरों के पद, भारी प्रतिशत में निम्न ग्रेड के सहायक स्टेशन मास्टरों की पदोन्नति द्वारा भरे गये हैं और चूंकि वे सेक्शन कंट्रोलर जैसी अन्य कोटियों में पदोन्नति के पात्र होते हैं ।

पूर्वोतर सीमा रेलवे में स्टेशन मास्टरों के लिये क्वार्टर

3760. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा स्टेशन मास्टरों के संवर्ग को परमावश्यक कर्मचारी घोषित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें क्वार्टर न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में कितने प्रतिशत स्टेशन मास्टरों को क्वार्टर नहीं दिये गये हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं, वास्तव में कर्मचारियों की इस प्रकार की कोई कोटि नई है ।

(ख) क्वार्टरों का आवंटन करने के लिए स्टेशन मास्टर और सहायक स्टेशन मास्टर तथा कुछ अन्य कोटियों के कर्मचारियों का वर्गीकरण "अनिवार्य कोटि" के रूप में किया गया है । चूंकि इन कर्मचारियों को किसी भी समय ड्यूटो पर बुलाया जा सकता है इसलिए उनका कार्यस्थल के पास रहना जरूरी है ।

(ग) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के केवल 13. 6 प्रतिशत स्टेशन मास्टरों को क्वार्टर नहीं दिये गये हैं जिनमें छुट्टी रिज़र्व और विश्रामदाता भी शामिल है ।

स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों का नौकरी से निकाला जाना

3761. **श्री बे० कु० बासचौधरी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्घटनाओं के मामलों में कुल कितने स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों को नौकरी से निकाला गया है;

(ख) अब तक कुल कितने मामलो पर पुनर्विचार किया गया है;

(ग) क्या जिला रैंक अधिकारियों को एक स्टेशन मास्टर अथवा सहायक स्टेशन मास्टर को नौकरी से निकालने की शक्ति प्राप्त है; और

(घ) यदि हाँ, तो ऐसे मामलों में अनुशासन तथा अपील नियमों में लिखित नियुक्ति अधिकारी से क्या अभिप्राय है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

चित्तरंजन लोको-मोटिव वर्कशाप

3762. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप इंजन बनाने के उद्देश्य से ही स्थापित किया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उपर्युक्त वर्कशाप में व्यस्ततम काल में कम से कम कितने इंजन बनाये गये तथा गत वर्ष कितने इंजन बनाये गये ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) समय समय पर भारतीय रेलों की जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में रेल इंजनों की उत्पादन-क्षमता का क्रमशः विकास किया

गया है । उत्पादन शुरू होने से लेकर चित्तरंजन रेल-इंजन कारखाने में प्रतिवर्ष जितने इंजन बनाये गये उनका ब्यौरा इस प्रकार रहा :—

वर्ष	कितने इंजन बनाये गये		
	भाप	बिजली	डीजल
1950–51 . . .	7	—	—
1951–52 . . .	17	–	—
1952–53 . . .	33	—	—
1953–54 . . .	64	—	—
1954–55 . . .	98	—	—
1955–56 . . .	129	—	—
1956–57 . . .	156	—	—
1957–58 . . .	164	—	—
1958–59 . . .	165	—	—
1959–60 . . .	173	—	—
1960–61 . . .	173	—	—
1961–62 . . .	171	5	—
1962–63 . . .	169	14	—
1963–64 . . .	172	4	—
1964–65 . . .	153	27	—
1965–66 . . .	137	32	—
1966–67 . . .	112	57	—
1967–68 . . . (जनवरी 68 तक) .	78	24	1
जोड़ . .	2171	163	1

निर्यात के लिये प्रोत्साहन

3763. **श्री लीलो प्रभु :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिक उत्पादन लागत जो कभी-कभी उद्योगों में अकुशलता के कारण होती है, अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में हमारे माल के प्रतियोगिता में नहीं ठहर सकने के लिये उत्तरदायी है;

(ख) क्या इस प्रकार की वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने के परिणामस्वरूप कर-दाताओं पर भार पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो इस का औचित्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं; यह जरूरी नहीं है कि अधिक उत्पादन लागत के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में हमारे कुछ माल के प्रतियोगिता में न ठहर सकने के कारण उद्योगों में अकुशलता ही हो।

(ख) और (ग). जी, नहीं ; निर्यात के उन मामलों में सहायता दी जाती है जहां यह समझा जाता है कि वर्तमान में ऐसी सहायता के रूप में विनियोजन करने के फलस्वरूप भविष्य में काफी विदेशी मुद्रा अर्जित हो सकेगी ।

निर्यात के कारण मुद्रा स्फीती

3764. **श्री लोबो प्रभु :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम हैं कि निर्यात को प्रोत्साहन देने वाली विभिन्न योजनाओं के कारण कृत्रिम कमी हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप देश की मंडियों में मुद्रा स्फीति हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भविष्य में प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में निर्णय करने से पहले इस प्रकार के निर्यात के कारण मुद्रास्फीति के बारे में विशेषज्ञों की राय लेने का सरकार का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Issue of Licences in Madhya Pradesh

3765. **Shri G. C. Dixit.** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of licences given for the setting up of industries in Madhya Pradesh during the First Three Five Year Plans ;

(b) the amount given by the Central Government for the setting up of industries in that State during the three Plans; and

(c) the number of industrial licences given by the Central Government for the setting up of industries in Maharashtra and Gajarat during the three Plans and the expenditure incurred in connection therewith ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c). 126 licences in Madhya Pradesh, 782 in Maharashtra and 260 in Gujarat were granted for setting up new industrial units during the First Three Plan Periods. No expenditure is incurred by the Central Government for setting up industrial units in the private sector in any of the States.

Halt of Punjab Mail at Burhanpur Station

3766. **Shri G. C. Dixit.** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that ever since the diesel locomotive has been introduced to haul the Punjab Mail, the time of its halt at Burhanpur Railway Station (Madhya Pradesh) has been reduced, as a result of which the passengers have to face a good deal of inconvenience in boarding and alighting from the Mail ;

(b) if so, whether Government propose to take any action to increase the time of its halt at that station ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes, in the case of 5 Dn. Punjab Mail from Bombay to Delhi/Ferozepur, the halt at Burhanpur was reduced from 3 to 2 minutes.

(b) The original halt of 3 minutes at Burhanpur of this train is being restored with effect from 1-4-1968.

(c) Does not arise.

Nepa Paper Mills

3767. Shri G. C. Dixit. Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the percentage of persons belonging to each of the States, separately, among the employees working in the various categories in Nepa Nagar Paper Mills of Madhya Pradesh ; and

(b) whether the management have made any special arrangement for providing opportunities of employment to the residents of East Nimar District ?

The Minister of Industrial Development & Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

सहायक स्टेशन मास्टरों की पदोन्नति

3768. श्री अबदुल गनी दार : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली डिवीजन के कुछ कनिष्ठ सहायक स्टेशन मास्टरों को उनसे वरिष्ठ सहायक मास्टरों से वरीयता देकर स्टेशन मास्टरों के पद पर पदोन्नति कर दिया गया हैं ?

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सक्रिय युद्ध सेवा वाल सहायक स्टेशन मास्टरों तथा अन्य सहायक स्टेशन मास्टरों की 1 जून, 1942 से पहल भर्ती किये गये कर्मचारियों से वरिष्ठ बना दिया गया है जो रेलवे बोर्ड के 25 फरवरी, 1950 के पत्र संख्या ई/49/आर– सी– 1/8/3 तथा उत्तर-पश्चिम रेलवे, लाहौर के जनरल मैनेजर के 11 फरवरी, 1943 के पत्र संख्या 847 ई० का उल्लंघन है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ). सूचना मंगायी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Appointments on S. E. Railway

3769. Shri Lakhanlal Gupta: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of fresh appointment made on the South Eastern Railway during the last three years, category-wise, and the average number of Madhya Pradesh residents in each category ; and

(b) whether advertisement in regard to all the aforesaid appointments were published in the newspapers of Madhya Pradesh ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The number of fresh appointments is being collected and will be laid on the Table of the Sabha. However, figures of residents of Madhya Pradesh among them cannot be furnished as such statistics are not maintained State-wise.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Wagon Repair Factory at Raipur

3770. **Shri Lakhan Lal Gupta :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to open a factory for the repair of wagons at Raipur on the South-Eastern Railway ;

(b) if so, when the work would commence ;

(c) whether any staff has been appointed in the factory ; and

(d) if so, the percentage of local persons among the staff appointed ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) Yes.

(b) The regular repair of wagons is expected to commence by April 1969.

(c) No staff have yet been appointed for the repair of wagons. However, two miscellaneous items of work (namely, fitting 'Knorr' valves on BOX wagons and bulk heads on BRH wagons) are being undertaken in the Workshop at present and 68 staff spare to the requirements of Kharagpur & Nagpur Workshops and the Divisions of the South-Eastern Railway have been posted for this purpose.

(d) Amongst the 68 staff posted, 27 per cent are local persons.

Railway Line between Jagdalpur and Balod

3771. **Shri Lakhan Lal Gupta.** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the construction of a Railway line from Jagdalpur to Balod on the Southern Railway is considered necessary in the public interest on account of the requirements of Beladilla Iron Ore Project and Bhilai Steel Plant ;

(b) whether the requisite survey has been carried out by the Railway Board in this regard ; and..

(c) the reasons for not undertaking the construction work of this railway line at an early date ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c). Feasibility-cum-cost studies for a broad gauge rail link between Dantewara (near Jagdalpur) and Dhalli Rajhara (near Balod) carried out recently reveals that the line will not be financially justified and hence the prosposal was dropped.

Bhilai Steel Plant

3772. **Shri Lakhan Lal Gupta.** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the number of employees of different categories appointed in Bhilai Steel Plant during the last two years ; and

(b) the number of employees of different categories retired from service as a result of retreachment in the said factory during the last two years ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) (i) Regular establishment :

During 1966-67, recruitment to regular establishment was as follows :

	1966	1967	Total
Executive	6	4	10
Non-executive	228	370	598

In addition, the following staff was transferred from Construction Department to regular establishment :

	1966	1967	Total
Executive	51	14	65
Non-executive	1,840	1.439	3,279

(ii) Work charged categories : 132 persons were recruited during the two years (1966 and 1967). This number included 92 retrenched displaced persons who were re-employed.

(b) Total number of retrenched persons over this period is as follows :

Regular establishment	19
Work charged	3,926

The 3,926 work charged employees were retrenched in 1966 in one lot, due to surplus staff on the construction side and as the work on expansion was coming to a close.

समस्ती पुर डिवीजन के वैकल्पित विभाग के "केरिज" कर्मचारियों को रात्रि कार्य भत्ता

3773. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर पूर्व रेलवे के जनरल मैनेजर ने समस्तीपुर डिवीजन के बहुत से स्टेशनों तथा अन्य स्टेशनों के लिये मैकनिकल विभाग के "केरिज" कर्मचारियों को 1 अप्रैल, 1967 से रात्रि-कार्य भत्ते की बकाया राशि का भुगतान करने के आदेश दिये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे बोर्ड ने बकाया राशि का 1 अक्टूबर, 1962 से भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी थी; और

(ग) यदि हां, तो इस असंगति को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

Shed over Platform at Dhemangaon Station (C. Rly.)

3774. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether passengers at Dhamangaon station have to suffer considerable inconvenience during the rainy season and summer season due to the absence of any shed over the Plat form;

(b) whether it is a fact that the number of paseengers coming to and going from this station towards Nagpur, Calcutta, Bombay and Bhusawal is very large and they have requested for the construction of shed over the platform; and

(c) if so, the action taken by Government to construct the shed ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) No. Covered accommodation is available on the Up & Dn. platforms.

(b) Yes.

(c) Asstated in reply to part (a) of the question, covered accommodation on the Up & Dn platforms has already been provided. As regards extension of the existing shed such works are carried out on programmed basis in consu.ltation with Railway Uoers 'Amenities' Comm ittee after taking into consideration the availability of funds and comparative needs of various stations. Proposals in this regard would also be considered accordingly.

Restrictions on Cloths and Cotton

3775. **Shri Deotao Patil**: Willthe Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether the Cotton Advisory Board at a meeting held in Bombay recently has recommended the withdrawal of all the restrictions imposed on cloth and cotton; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Safi Qureshi) : (a) Presumably Hon'ble Member is referring to the metting of the Standing Committee of the Cotton Advisory Board held in Bombay on 15th February 1968. The Committee did not recommend the withdrawal of all the restrictions inposed on cloth and cotton. However, certain members of the Committee made suggestions for removal of restrictions on stock of cotton to be held by mills, credit restrictions imposed by the Reserve Bank of India on advances on cotton and decontrol of cloth.

(b) Restrictions on cotton have been imposed to safeguard the interests of all concerned and it has not been considered to be advisable to remove them at this stage. As regrads contol on cloth, since its removal is likely to hurt the poorer section of the population the matter is receiving carefyl consideration.

साम्राज्य संबंधी रियायती दर की नीति के स्थान पर नई नीति

3776. **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल्जियर्स के चार्टर के अनुसार साम्राज्य संबंधी रियायती दर की वर्तमान नीति इम्पीरियल (प्रीफ्रैंसेंज) के स्थान पर सामान्य दर की नीति लाग करने के बारे में हाल ही में राष्ट्र-मंडल के देशों के बीच कोई विचार विमर्श हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) हाल ही में, राष्ट्र मंडल के देशों के प्रतिनिधियों के बीच इस विषय पर प्रारंभिक रूप में बातचीत हुई थी। आगे वार्ताएं तब होंगी, जब व्यापक अधिमानों की योजना, जिस पर द्वितीय संयक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन में विचार किया जा रहा है का निरूपण हो जायेगा।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के कारखाने

3777. **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक मंदी के कारण मांग कम हो जाने से हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के विभिन्न कारखानों में मशीनी औजारों के निर्माण पर गम्भीर प्रभाव पड़ा है और वहां बहुत बड़ी मात्रा में माल जमा हो गया है;

(ख) क्या हिन्दुस्तान मशीन में निर्मित मशीनी औजारों के लिये विदेशी मंडियों में बेचने के लिए कोई विशेष निर्यात अभियान प्रारम्भ किया गया है; और

(ग) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने को अपने उत्पादों के लिये दक्षिण-पूर्व एशिया तथा अफ्रीकी देशों में नई मंडियों को ढूंढने में सफलता मिली है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) अपने उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, लिमिटेड ने न्यूयार्क (अमरीका) तथा फ्रेंकफर्ट (पश्चिमी जर्मनी) में अपने बिक्री कार्यालय खोले हैं। आस्ट्रेलिया में भी वे एक कार्यालय शीघ्र ही खोलेंगे। अपने उत्पादों की बिक्री के लिए उन्होंने कई देशों में एजेंट नियुक्त किए हैं।

(ग) दक्षिण-पूर्वी एशिया तथा अफ्रीकी देशों में से उन्होंने अब संयुक्त अरब गणराज्य तथा श्रीलंका में भी अपने एजेंट नियुक्त किए हैं। उन्होंने सिंगापुर को भी एक मशीन का निर्यात किया है। फिर भी उनके निर्यात बढ़ाने के प्रयत्नों के फलीभूत होने में कुछ समय लगेगा।

अलोह धातु

3778. **श्री दामानी :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन योजनाओं में अलौह धातुओं की खोज, परिष्करण तथा विकास के संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इनका उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या उपाय करने का सरकार का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक विभाग द्वारा योजना कालों में किये गये अन्वेषण कार्यों के परिणामस्वरूप, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश और मद्रास में सीसे और जस्ते के खनन योग्य निक्षेप पाये गये हैं।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक विभाग द्वारा देश के बहुत से भागों में अलौह धातुओं के भंडारों का अन्वेषण, महानुमाप मानचित्रण, गढ़े खोदना और खाइयां बनाना, भरसायनिक और भौतिकीय सर्वेक्षण, व्यधन और समन्वेषी खनन द्वारा जारी रखा गया है। अलौह धातुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिये निम्नलिखित विशेष कार्यवाही की जा रही है :—

1. **एल्यूमिनियम** : देश में एल्यूमिनियम की अधिष्ठापित क्षमता इस समय 115,800 मीट्रिक टन वार्षिक है। 327,500 मीट्रिक टन वार्षिक (150,000 मीट्रिक टन सरकारी क्षेत्र में और 177,500 मीट्रिक टन निजी क्षेत्र में) और क्षमता पूर्ण करने की विभिन्न अवस्थाओं में है। चौथी योजना के अन्त में अथवा पांचवी योजना के आरम्भ के समय में अधिष्ठापित क्षमता को, 443,000 मीट्रिक टन तक ले जाने की आशा है।

2. **तांबा** : इस समय देश में केवल एक तांबा प्रद्रावक है जो कि सिंघभूम के (बिहार) तांबा निक्षेपों पर आधारित है और 9,000 मीट्रिक टन वार्षिक धातु का उत्पादन करता है। इस एकक को जो कि निजी क्षेत्र में है तांबा उत्पादन करने के लिये, औद्योगिक अधिनियम के अधीन 16500 मीट्रिक टन वार्षिक प्रस्फुरण प्रद्रावक स्थापित करने के लिए एक लाइसेंस दिया गया है। खेतरी (राजस्थान) में एक 31,000 मीट्रिक टन वार्षिक तांबा प्रद्रावक सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया

जा रहा है। यह परियोजनाएं चौथी योजना के अन्त तक पूरी हो जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त, बिहार के राखा, आंध्र प्रदेश के अग्निगंडाला और राजस्थान के दरीबो क्षेत्र में तांबे के निक्षेपों को विकसित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

3. **सीसा और जस्ता** : देश में इस समय एक मात्र सीमा प्रद्रावक टुडू (बिहार) में स्थापित है जिसकी क्षमता लगभग 5,400 मीट्रिक टन वार्षिक है। तथापि, प्रद्रावक का वर्तमान उत्पादन केवल 2600 मीट्रिक टन वार्षिक के स्तर का है। प्रद्रावक जावर खानों (राजस्थान) के सीसा-जस्ता अयस्क निक्षेपों पर आधारित है।

मई-जून 1967 में आयतित संकेन्द्र को पर आधारित अलवेयी (केरल) के निजी क्षेत्र के एक 20,000 मीट्रिक टन वार्षिक जस्ता प्रद्रावक ने उत्पादन आरम्भ किया था। सरकारी क्षेत्र में एक और नया, जावर (राजस्थान) निक्षेपों पर आधारित, 18,000 मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला जस्ता प्रद्रावक अभी कुछ ही समय पहले चालू किया जा चुका है। सिद्ध करने तथा पूर्वेक्षण के सविस्तार कार्य जो कि इस क्षेत्र में अतिरिक्त अयस्कों को निर्धारित करने के लिये आरम्भ किये गये हैं, पता चला है कि ये संचय अन्त में 75,000 मीट्रिक टन वार्षिक धातु उत्पादन बनाए रख सकते हैं। अलवेयी (केरल) प्रद्रावक की 60,000 मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन तक वृद्धि करने (दो प्रावस्थाओं में) का एक प्रस्ताव और आयतित संकेन्द्र पर आधारित दूसरा एक नया 30,000 मीट्रिक टन वार्षिक जस्ता प्रद्रावक सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। ये सक्रियता से विचाराधीन है। देश के अलौह धातुओं के संगव्य खनिज संसाधन ढूंढने और विकसित करने के लिये, हवाई सर्वेक्षण और बाद के भूमि कार्य का एक सर्वतोमुखी कार्यक्रम बनाया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान के अरावली क्षेत्र—आंध्र प्रदेश के पूर्वी कुडापा नदी का क्षेत्र और बिहार पठार का हवाई सर्वेक्षण करना हैं जो कि 120,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में छाया हुआ है। आशा है कि हवाई सर्वेक्षण के अतिरिक्त, भारतीय भूवैज्ञानिक विभाग लगभग 234 पूर्वेक्षणों का भूमि सर्वेक्षण का कार्य हाथ में लेगी।

गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां

3779. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी कम्पनियों के डायरेक्टरों तथा प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन तथा परिलब्धियों के निर्धारण सम्बन्धी नियम बना लिये गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखने का सरकार का विचार है;

(ग) उन उच्च अधिकारियों की संख्या तथा ब्यौरा क्या है जिन्हें प्रतिवर्ष एक लाख से अधिक वेतन मिल रहा है ; और

(घ) क्या विदेशी अधिकारियों के सम्बन्ध में कोई भेदभाव किया जाता है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) निजी क्षेत्र की कम्पनियां, पब्लिक लिमिटेड अथवा प्राइवेट लिमिटेड होती हैं। पब्लिक कम्पनियों के निदेशकों का परिश्रमिक तथा पारिलब्धियां, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 309, 198, 269, 310 तथा 311 के उपबन्धों के अन्तर्गत शासित होती हैं। उक्त अधिनियम में प्राइवेट कम्पनियों के निदेशकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक विनियमित नहीं है। उस अधिनियम

में कम्पनियों के प्रशासनिक अधिकारी वर्ग को दिया जाने वाला पारिश्रमिक भी विनियमित नहीं हैं, जो केवल कर्मचारी हैं, प्रबन्धकों की स्थिति में नहीं। यह अधिनियम सरकार को, प्राइवेट कम्पनियों के निदेशकों अथवा पब्लिक व प्राइवेट कम्पनियों के प्रशासनिक अधिकारी वर्ग के वेतन को विनियमित करने के लिये नियम बनाने की शक्ति नहीं देता ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ). विभाग के पास सूचना प्राप्त नहीं है ।

रानी गुन्ता और तिरुपती के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

3780. **श्री गार्डिलिंगन गौड़ :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानी गुन्ता और तिरुपती तथा तिरुपती और काटपाड़ी के बीच छोटी छोटी लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) कार्य के कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) रानी गुन्ता और तिरुपति पूर्व के बीच एक अलग बड़ी लाइन की व्यवस्था की जा रही है। बड़ी लाइन को काटपड़ी तक बढ़ाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग). रानी गुन्ता और तिरुपति पूर्व के बीच बड़ी लाइन पर 30 लाख रुपये के खर्च का अनुमान है। इस परियोजना का काम शुरू किया जा चुका है ।

गाड़ियों में चोरियां तथा बिना टिकट यात्रायें

3781. **श्री गार्डिलिंगन गौड़ :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिना टिकट यात्रा के कारण सरकार को अनुमानतः कितनी वार्षिक हानि होती है;

(ख) बल्ब, पंखे तथा अन्य प्रकार की वस्तुओं की चोरी से रेलवे को अनुमानतः कितनी वार्षिक हानि होती है ;

(ग) क्या यह सच है कि बिना टिकट यात्राएं और चोरियां सम्बन्धित कर्मचारियों की साजिश से की जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) बिना टिकट यात्रा से सरकार को होने वाली वार्षिक हानि का सही अनुमान उपलब्ध नहीं है लेकिन मोटे तौर पर लगभग 10 करोड़ रुपये की हानि होती है ।

(ख) लगभग 16 लाख रुपये ।

(ग) जी हां, कुछ मामलों में।

(घ) बिना टिकट यात्रा और अनियमित यात्रा के अन्य तरीकों को कम करने तथा इस तरह की अनियमित यात्रा में रेल कर्मचारियों की साजिश को रोकने के लिए आये दिन कड़ी जांच की जाती है जिसमें उड़न दस्तों और रेलवे मैजिस्ट्रेटों द्वारा की जाने वाली गुप्त और अचानक जांच भी शामिल है।

गाड़ियों से बिजली और दूसरे फिटिंग की चोरी को रोकने के लिये नीचे लिखे उपाय किये गये हैं / किये जा रहे हैं :—

1. अपराधियों का पता लगाने के उद्देश्य से अपराध आसूचना इकट्ठी करने के लिये सादी पोशाक में रेल सुरक्षा दल के कर्मचारी तैनात किये जाते हैं।
2. जो लोग चोरी का माल खरीदते हैं उनके बारे में आसूचना इकट्ठी करने के लिये विशेष खुफिया कर्मचारी तैनात किये जाते हैं और पुलिस की सहायता से उनकी दूकानों पर छापे मारे जाते हैं।
3. क्षेत्रीय मुख्यालय और रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय अपराध ब्यूरो के कर्मचारियों को अचानक छापे मारने के लिये भेजा जाता है ताकि अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ा जा सके।
4. अपराधियों और चोरी का माल खरीदने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए रेलवे सुरक्षा दल और सरकारी रेलवे पुलिस और पुलिस अधिकारियों के बीच निकट सम्पर्क भी बनाये रखा जाता है।
5. डिब्बों में ताला लगाना, बिजली उपस्करों की वेल्डिंग और डिब्बा-बन्दी, ढांचे के नीचे के तारों की क्लीटिंग और ट्रफिंग, अक्सर चोरी जाने वाले उपस्करों को वर्तमान स्थान से हटाकर डिब्बों के भीतर लगाना आदि चोरी निरोधक उपाय किये गये हैं ताकि समाज विरोधी तत्वों द्वारा उन्हें हटाना कठिन हो जाये।

Export of Shoes

3782. **Shri Ram Charan**: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the number of shoe manufacturing companies in addition to State Trading Corporation which have been allowed to export shoes directly to U. S. S. R. and Europe; and

(b) the names of those companies and the number of pairs of shoes each company has been allowed to export and the basis thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b). Supply orders for export of shoes are annually obtained by S. T. C. from U. S. S. R. and other East European countries. All these countries are supplied samples by S. T. C. which are collected from their associates and fabricators on the basis of which they approve specific samples and determine quantities required. S. T. C. indicates the pattern and the quantity approved by these counties to the concerned firms, who arrange exports in accordance with the apporved samples to these countries. Details of supply orders recieved by S.T.C. During 1967 from U. S. S. R. and other East European countries as also the allocation of quantities made in respect of each supplier a re given in the attached statement. [*Placed in Library See* No. LT 435/68]

कोयला तथा अन्य खनिज पदार्थों की ढुलाई

3783. श्री सु० कु० तापड़िया :
डा० रानेन सेन :

क्या रेलवे मंत्री 13 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 95 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले तथा अन्य खनिज पदार्थों की ढुलाई के लिये जो परिवहन क्षमता बनाई गई थी, उसका उपयोग कितना कम हो रहा है;

(ख) 1966 और 1967 के दौरान कोयला तथा अन्य खनिज पदार्थों के लदान के आंकड़े क्या हैं;

(ग) कोयले तथा अन्य खनिज पदार्थों की ढुलाई के लिए कितने रेल के माल डिब्बों की मांग की गई और वास्तव में कितने डिब्बे सप्लाई किये गये; और

(घ) कम माल डिब्बे सप्लाई किये जाने के क्या कारण हैं, जबकि परिवहन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) चूंकि यह प्रश्न अतारांकित प्रश्न सं० 95 के उत्तर से सम्बन्धित है इसलिए अनुमान है कि अपेक्षित आंकड़ों का सम्बन्ध उक्त उत्तर में दिये गये परिवहन के आंकड़ों से है।। मांग-पत्रों की दैनिक औसत संख्या, मालडिब्बों की सप्लाई और इस्पात कारखानों को कोयले का लदान और बैलाडिल्ला से निर्यात अयस्क का जो लदान हुआ उसके आंकड़े नीचे दिये गये हैं। इन आंकड़ों से मालडिब्बों के अपूर्ण उपयोग की सीमा का पता चलता है।

	1966				1967			
	लक्ष्य	मांग-पत्र	सप्लाई	लदान	लक्ष्य	मांग-पत्र	सप्लाई	लदान
इस्पात कारखानों को भेजा गया कोयला	1600	1420	1406	1398	1600	1438	1366	1354
धुलाई कारखानों को भेजा गया कोयला	900	686	637	628	900	705	609	591
इस्पात कारखानों को भेजा गया कच्चा सामान	2428	2156	2172	2087	2426	2189	2166	2045

बैलाडिल्ला से निर्यात अयस्क का परिवहन अक्तूबर, 1967 में शुरू हुआ था। उसके लदान के लिए फरवरी/मार्च, 1968 तक प्रतिदिन तीन गाड़ी से लेकर 4 तक की योजना थी लेकिन मौजूदा मांग केवल एक गाड़ी की है।

(घ) टर्मिनल स्टेशनों पर मालडिब्बों की निकासी के अनुरूप ही उनकी सप्लाई का भी समय-समय पर विनियमन करना पड़ता है क्योंकि इस्पात कारखानों में मालडिब्बों से माल उतारे जाने और उनकी निकासी में बहुधा देर होती है। माल डिब्बों की सप्लाई कम नहीं है जैसा कि आंकड़ों से स्पष्ट होगा। डिब्बों की मांग लक्ष्य से कम थी और उतने मालडिब्बों का लदान नहीं हुआ जितने सप्लाई किये गये।

रेलवे सिगनलों का आयात

3784. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में कितने मूल्य के रेलवे सिगनलों का आयात किया गया;

(ख) देश में क्षमता उपलब्ध होने पर भी सिगनलों के आयात किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अपनी पूर्ण आवश्यक मात्रा देश में से ही खरीद कर सरकार ने मंदी तथा अप्रयुक्त क्षमता से लाभ उठाने का प्रयत्न किया है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क)

1965-66	1966-67
93,60,582 रुपये	1,23,88,202 रुपये

(ख) रेलवे सिगनल उपस्कर की केवल उन्हीं चीजों का आयात किया जाता है जिनके उत्पादन की देसी क्षमता अपर्याप्त है या है ही नहीं।

(ग) हमारी जरूरत की जो भी चीजें देश में बन सकती हैं वे सब देसी कारखानों से ही खरीदी जा रही हैं।

रक्त सुरक्षित रखने के रेफ्रीजरेटरों और फ्रीजर्स का निर्माण

3785. **श्री काशीनाथ पाण्डे : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 में सम्पन्न हुए सहयोग समझौते के अनुसार अमरीकी सहयोग से भारत में बनाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के फ्रीजर्स और रक्त सुरक्षित रखने के रैफ्रिजरेटरों की अश्व शक्ति और घन क्षमता कितनी होगी ; और

(ख) इस सहयोग के लिए अमरीकी फर्म को कितनी रायल्टी दी जायेगी।

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) 1/4 से 1 अश्व शक्ति और 10 से 35 घन फट और उससे अधिक क्षमता तक मांग के अनुसार फ्रीजर बनाने की एक योजना को स्वीकृति दी गई है और अमरीकी सहयोगियों को 5 प्रतिशत रायल्टी दी जायेगी। इस सहयोग करार में रक्त इकट्ठा करने के रेफ्रीजरेटर सम्मिलित नहीं हैं। ब्लड प्लाज़मा फ्रीज़र तथा ब्लड स्टोरेज रेफ्रीजरेटर (1/4 अश्व शक्ति 8 घन फुट तथा 15 घनफुट) में से प्रत्येक का एक एक नमूना बनाने के लिए एक दूसरी योजना के लिए स्वीकृति दी गई है जिस पर 3 प्रतिशत रायलटी और 2000 डालर की इकट्ठी रकम अमरीकी सहयोगियों को दी जायेगी। दोनों ही मामलों में रायलटी की अदायगी भारतीय करों के अधीन होगी और दोनों ही करार 5 वर्ष तक लागू रहेंगे।

डीमापुर मनीपुर रोड-नीचूगरोट रेलवे लाइन

3786. **श्री मेघचन्द्र :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर-सीमा रेलवे पर डीमापुर-मनीपुर रोड स्टेशन को नगालैण्ड के नीचूगरेट से मिलाने वाली एक ब्रांच रेलवे बिछाने का है; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बैटरी के सैलों का निर्माण

3787. **श्री गणेश घोष :**
श्री नम्बियार :
श्री अनिरुद्धन :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बैटरी के सूखे सैलों के कुछ विदेशी नियंत्रणाधीन निर्माताओं ने अपने माल की बड़े पैमाने पर चोरबाजारी करनी आरम्भ कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या एसे अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं। निर्माता किसी भी प्रकार की चोर बाजारी नहीं कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नर्सों के लिये रेलवे यात्रा सम्बन्धी रियायतें

3788. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री प० गोपालन :
श्री एस्थोस :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नर्सों को पहले रेलवे यात्रा सम्बन्धी रियायतें दी जाती रही हैं;

(ख) यदि हां तो कब से;

(ग) क्या ये रियायतें उन्हें अब भी प्राप्त हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चं० म० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) यह रियायत 1920 से पहले भी दी जाती थी।

(ग) यह रियायत छात्रा नर्सों को अब भी दी जाती है। लेकिन उन प्रशिक्षित नर्सों को नहीं दी जाती जो अस्पतालों में नियुक्त हों पर निजी प्रेक्टिस करती हों।

(घ) नियमतः अन्य व्यवसायों के स्त्री-पुरुषों को रियायत नहीं दी जाती। यह अनुभव किया गया था कि इस मामले में नर्सें कोई विशेष रियायत पाने की हक़दार नहीं हैं इसलिए यह रियायत वापिस ले ली गयी। फिर भी इस मामले में आगे और विचार किया जा रहा है।

जापान को निर्यात पर स्टर्लिंग के अवमूल्यन का प्रभाव

3789. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री अब्राहम :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पौण्ड स्टर्लिंग के अवमूल्यन से पहले और बाद में जापान को निर्यात किये गये लौह अयस्क तथा लौहमय मैंगनीज अयस्क निर्यात का प्रति टन मूल्य क्या था ;

(ख) दिसम्बर, 1967 और जनवरी, 1968 में जापान को कुल कितने मल्य का लौह अयस्क तथा लौहमय मैंगनीज अयस्क निर्यात किया गया ; और

(ग) यदि निर्यात में कोई कमी आई है तो उसका क्या कारण है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी) : (क) निर्यात मूल्य सम्बन्धी आंकड़े अन्तर्राष्ट्रीय संविदा प्रलेखों का एक भाग होते हैं, इसलिये उन्हें बताना खनिज तथा धातु व्यापार निगम/अन्य निर्यातकों के व्यापारिक हितों में नहीं होगा। पौण्ड स्टर्लिंग के अवमूल्यन के

प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिये, चालू संविदाओं में स्टर्लिंग में उल्लिखित मूल्यों को, क्रेताओं के साथ बातचीत करके बढ़ा दिया गया है ।

(ख) और (ग) दिसम्बर, 1967 तथा जनवरी, 1968 में जापान को खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा किये गये निर्यातों का मूल्य क्रमशः 396.25 लाख रु० तथा 356.95 लाख रु० है। गोआ से माल भेजने वालों द्वारा किये गये निर्यातों का मूल्य अभी ज्ञात नहीं है। जहाँ तक खनिज तथा धातु व्यापार निगम के निर्यातों का सम्बन्ध है, उनमें अधिक गिरावट नहीं आई है। संविदा दायित्वों के अनुसार माल भेजा गया है ।

सुराकाचार कोयला खान से रूसी तारों के गुम होने के बारे में जांच

3790. श्री उमानाथ :　　　　　　**श्री प० गोपालन :**
श्री सत्यनारायण सिंह :　　　　　　**श्री एस्थोस :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री 13 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 23 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश पुलिस ने रूसी तारों के गुम हो जाने के बारे में इस बीच जाँच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हाँ, तो जाँच निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो जाँच के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) नहीं महोदय।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जाँच पूरी करने के लिये कितना समय लगने की सम्भावना है,यह निर्धारित करना मध्य प्रदेश पुलिस अधिकारीवर्ग का काम है ।

बीकानेर में रेलवे फाटक

3791. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीकानेर शहर में कितने रेलवे फाटक हैं और वे यातायात के लिये कितनी बार बन्द किये जाते हैं ; और

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि इससे जनसाधारण को बड़ी परेशानी और असुविधा होती है, और यदि हाँ, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) बीकानेर शहर की सीमा में तीन समपारों में से प्रत्येक को, संरक्षा की दृष्टि से 24 घंटों में लगभग 40 बार बन्द करना पड़ता है ।

(ख) जी हाँ; 1961 में रेलवे स्टेशन के दोनों ओर एक-एक ऊपरी सड़क पुल बनाने की योजना बनायी गयी थी। लेकिन स्थानीय व्यक्तियों के विरोध के कारण यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी और राज्य सरकार के अनुरोध पर इन प्रस्तावों को अन्तिम रूप से त्याग देना पड़ा ।

यात्री सुविधायें

3792. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री नम्बियार :**
श्री नायनार : **श्री विश्वम्भरन् :**
श्री चक्रपाणि :

क्या **रेलवे** मंत्री 13 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 74 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्री सुविधाओं पर विचार करने के लिये बनायी गयी समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हाँ ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें समिति के निष्कर्षों और सिफारिशों का संक्षेप दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 436/68]**

(ग) और (घ) समिति की सिफारिशों की ध्यानपूर्वक जाँच की जा रही है और इन पर यथासम्भव शीघ्र निर्णय किया जायेगा ।

खेत्री और कोलीहन ताम्बा खानें

3793. **श्री सत्य नारायण सिंह :** **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री रमानी : **श्री भगवान दास :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खेत्री और कोलीहन ताम्बा खानों के पास औषधालय के लिये पर्याप्त स्थान नहीं है ;

(ख) यदि हाँ, तो वहाँ के कर्मचारियों के लिये चिकित्सा की पर्याप्त-सुविधाओं की व्यवस्था करने के हेतु अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि औषधालय में उपलब्ध डाक्टरी उपचार की सुविधाओं से वहाँ के कर्मचारी सन्तुष्ट नहीं हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है कि कर्मचारियों के लिये चिकित्सा की उचित व्यवस्था हो ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) नहीं, महोदय ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 31-1-1968 की हुई दुर्घटना के अनन्तर, जिसमें एक चालक मारा गया था, कुछ कार्यकर्ताओं ने मृत चालक की पर्याप्त चिकित्सा की ओर ध्यान न देने के आरोप लगाये थे । इस बात की जाँच की जा रही है ।

(घ) कार्यकर्ताओं के लिये पर्याप्त चिकित्सा की सुविधाएं पहले से ही प्राप्त हैं ।

भारतीय खान ब्यूरो

3794. श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० गोपालन :
श्री अब्राहम :
श्री अनिरुद्धन :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खान ब्यूरो ने 1966 में जिन लोगों का चयन किया था उन्हें अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) हाँ, महोदय । चार व्यक्ति भारतीय खान ब्यूरो ने 1966 में नियुक्तियों के लिये चुने थे ; परन्तु वर्तमान पदों में 3 प्रतिशत कटौती कर देने के कारण मितव्ययिता के फलस्वरूप नियुक्त नहीं किये जा सके ।

रेलवे गार्डों के लिए संगचल भत्ता

3795. श्री अ० क० गोपालन :
श्री अब्राहम :
श्री चक्रपाणि :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गार्डों के संगचल भत्ते में वृद्धि की जाँच करने के लिये नियुक्त की गई समिति के काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) प्रतिवेदन के कब तक प्राप्त होने की संभावना है ; और

(ग) विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) समिति अपना काम कर रही है और आशा है कि वह मई, 1968 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट दे देगी ।

खनन मशीनरी का आयात

3796. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र के लिये पृथक-पृथक पिछले दस वर्षों में देशवार कितने मूल्य की खनन मशीनों का आयात किया गया ; और

(ख) कितने मूल्य की मशीनों को (1) पूर्णतया (2) आँशिक रूप से प्रयोग किया गया है और (3) कितने मूल्य की मशीनों को बिल्कुल प्रयोग नहीं किया गया है ?

स्पात, खान तथा धातु मन्त्रोलय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायगी ।

रेलवे में अविलम्बनीयता प्रमाणपत्रों के दिये जाने पर किये गये काम

3797. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में रेलवे में विभिन्न कामों के लिये कितने 'अविलम्बनीयता प्रमाण-पत्र' दिये गये ;

(ख) उन पर कुल कितना व्यय हुआ ; और

(ग) ये प्रमाण-पत्र किन परिस्थितियों में दिये गये ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 262.

(ख) 9344.31 लाख रुपये ।

(ग) टूट-फूट, बाढ़, तूफान, भू-स्खलन, दुर्घटनाओं आदि के कारण रेलपथ को फिर से चालू करने, भाषा सम्बन्धी आन्दोलन में क्षतिग्रस्त रेल-पथ, पुलों, सिगनल व्यवस्था आदि की मरम्मत और परिचालन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, परिवहन की कठिनाइयों को दूर करने से सम्बन्धित निर्माण-कार्य आदि समय-समय पर बहुत उच्च अग्रता के आधार पर करने पड़े और ये काम इतने आवश्यक थे कि इनको सामान्य रीति से, खर्च करने से पहले व्यौरेवार अनुमानों की मंजूरी की प्रतीक्षा करके, नहीं किया जा सकता था ।

भूतपूर्व बीकानेर रियासत की रेलवे के कर्मचारियों से मकान-किराये की वसूली

3798. **श्री सूरज भान** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के उन कर्मचारियों से जो 1-4-1950 से पूर्व भूतपूर्व बीकानेर रियासत की रेलवे के कर्मचारी थे और जो बिना किराये के मकान या उसके स्थान पर मकान भत्ता पाने के अधिकारी थे क्या उनसे मकान किराया वसूल किया गया है ;

(ख) क्या इस वसूली में उन्हें वापस करने सम्बन्धी निर्णय को पूर्णतः क्रियान्वित नहीं किया गया है और अनेक कर्मचारियों को यह राशि वापस नहीं की गई है ; और

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो निर्णय को क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं और इसका पालन कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं :

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

"ब्लैक" चाय पर उत्पादन शुल्क

3799. **श्री हेमराज** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमृतसर की मंडी में कम उत्पादन वाले बागानों (वीक गार्डन) की "ब्लैक" चाय का कम मूल्य प्राप्त होने को देखते हुए इस पर लगाया गया उत्पादन शुल्क अधिक सिद्ध हो रहा है ;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग). चाय बोर्ड, कलकत्ता को सम्बोधित अभ्यावेदन की एक प्रति सरकार को कांगड़ा वैली टी प्लांटर्स एसोसिएशन, पालमपुर के मंत्री से प्राप्त हुई है जिसमें कांगड़ा घाटी में पैदा होने वाली काली चाय के उत्पादन शुल्क में कमी करने का आग्रह किया गया है। आग्रह का आधार यह है कि चाय की इन किस्मों का अमृतसर के बाजार में बहुत कम भाव मिलता है। कांगड़ा घाटी की काली चाय पर पहले ही बहुत कम उत्पादन शुल्क है। इस पर विचार किया जा रहा है कि क्या उनकी प्रार्थना के अनुसार, उसमें और भी कमी की जानी चाहिए ।

सहकारी औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण

3800. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **औद्योगिक-विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम सहकारी औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिये प्रतिवर्ष 50 लाख रुपय नियत करने के लिये सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उन बस्तियों तथा सहकारी समितियों का रूप क्या है ?

(ग) क्या राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार उनकी स्थापना के सम्बन्ध में पहल करेंगी; और

(घ) कौन-कौन सी राज्य सरकारें इस राशि का उपयोग करने की अधिकारी होंगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) और (ख). जी, हाँ। सहकारी समितियों तथा मिश्रित पूंजी कम्पनियों द्वारा स्थापित की जाने वाली औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिए सन्तोषजनक स्थापना स्थल ऋण व्यवस्था विपणन तथा अन्य सुविधाएं और उचित निरीक्षण तथा प्रशंसनीय व्यवस्था जैसी कुछ शर्तें पूरी कर लेने पर ही ऋण दिया जायगा ।

(ग) और (घ). स्थापना-स्थल का निर्णय केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, सहकारी समिति अथवा कम्पनी द्वारा किया जा सकता है बशर्ते कि वह सन्तोषजनक हो । देश में किसी भी स्थान पर स्थापित की गई बस्तियां यह सहायता पाने की हकदार बन सकती हैं। राज्य सरकारें इस राशि का प्रयोग नहीं कर सकेंगी। तथापि राज्य सरकारें उन को दिये जाने वाले ऋण की गारन्टी देंगी और ऋण दी जाने वाली बस्ती के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी करेंगी ?

Office Room for Station Master at Atarra Station

3801. **Shri Jageshwar Yadav:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government propose to provide a separate office room for the station Master of Atarra Station on the Jhansi-Manikapur section of the Central Railway in view of over-crowding at the station; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) No.

(b) The existing accommodation in Station Master's office is adequate for him and his staff.

कैमरून के साथ व्यापार-समझौता

3802. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार तथा कैमरून संघीय गणराज्य के बीच हाल ही में दिल्ली में एक व्यापार समझौता सम्पन्न हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके अन्तर्गत भारत को क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) जी, हां। भारत और कैमरून के संघीय गणराज्य से मध्य 22 फरवरी, 1968 को नई दिल्ली में एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर हुए।

(ख) करार स्वरूप में सामान्य है और उस में अन्य बातों के साथ साथ दोनों देशों द्वारा व्यापार के मामले में परस्पर परम मित्र राष्ट्र व्यवहार प्रदान करने की व्यवस्था है। उसमें दोनों देशों ने पारस्परिक लाभ के लिये आपसी सहयोग का वचन दिया है ताकि दोनों देशों के मध्य आर्थिक सम्बन्ध मजबूत हों और वाणिज्यिक क्षेत्र में, विशेषत: जहां भी संभव हो, तकनीकी प्रशिक्षण तथा सहायता द्वारा, वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान का आदान प्रदान तथा प्रयोग सुकर हो सके। यह कहरा अनुसमर्थन की लिखत के आदान प्रदान की तिथि से लागू होगा और आरम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिये वैध होगा। अत: इसे दोनों पक्षों की मौन स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है जब तक कि दोनों में से किसी एक पक्ष द्वारा तीन महीने की लिखित सूचना द्वारा उसे संशोधित अथवा रद्द न कर दिया जाए।

(ग) यद्यपि आयात के मामले में करार में दोनों देशों में से किसी भी देश की विशेष वचन बद्धता नहीं है तथापि आशा है कि इससे कैमरून के संघीय गणराज्य के साथ हमारे व्यापार सम्बन्ध सुदृढ़ होंगे और अफ्रीका में फ्रांसीसी-भाषा-भाषी देशों के साथ हमारे घनिष्ट सम्बन्ध आरम्भ होंगे।

ईराकी औद्योगिक प्रतिनिधि मण्डल

3803. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री दीवीकन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में एक ईराकी औद्योगिक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया था ;

(ख) यदि हाँ, तो उस के साथ क्या क्या बातचीत हुई ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) जी, हाँ।

(ख) प्रतिनिधि मंडल की यात्रा का मुख्य उद्देश्य हाल ही में के वर्षों में भारत में उद्योग के विकास की जानकारी प्राप्त करना था जिस से उन क्षेत्रों का पता लग सके जिन में भारत-ईराक में घनिष्ट सहयोग सम्भव हो सकते हैं। विचार-विमर्श के दौरान दोनों देशों में घनिष्ट आर्थिक सहयोग के विकास के स्वरूप का सर्वेक्षण किया गया। दोनों पक्षों ने अनुभव किया कि भारत और ईराक में सहयोग के लिये संयुक्त उद्यम विशेष रूप से लाभदायक हैं और वे इस बात पर सहमत हो गये कि दोनों देशों की उपयुक्त पार्टियों को ऐसे उद्यमों में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। दोनों देशों में व्यापार के विकास की संभाव्यताओं पर भी विचार किया गया और यह निश्चय हुआ कि दोनों पक्षों को व्यापार के विस्तार तथा विविधीकरण के लिए और भी प्रयत्न करने चाहियें।

(ग) चूंकि विचार-विमर्श सामान्य प्रकार का तथा गवेषणात्मक था अतः विचार-विमर्श के परिणामों को ठीक ठीक आँकना अभी सम्भव नहीं है।

वाणिज्य मन्त्री की विदेश यात्रायें

3805. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपना वर्तमान पद ग्रहण करने के बाद उन्होंने कितनी बार विदेश-यात्रा की है; और

(ख) उन्होंने नगरों की यात्रा की कितनी बैठकों में भाग लिया और कितने लोगों से मुलाकात की और प्रत्येक स्थान पर वह कितने दिन ठहरे ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) अपने वर्तमान पद-ग्रहण के उपरान्त वाणिज्य मंत्री चार बार विदेश गये।

(ख) एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखा जाता है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 437/68]

आन्ध्र प्रदेश में सीमेंट का कारखाना

3805. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य के कड़पा जिले में येरगुन्टला नामक स्थान पर एक सीमेंट का कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव दूसरी पंचवर्षीय योजना से सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या इस कारखाने की स्थापना के लिए एक-एक करके तीन गैर-सरकारी यन्त्रों को लाइसेंस दिये गये थे और उनमें से प्रत्येक इस परियोजना को स्थापित करने में असफल रही;

(ग) क्या भारत सरकार के सीमेंट निगम ने उक्त स्थान पर सरकारी कारखाने की सम्भावना का पता लगाने के उद्देश्य से उस स्थान की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) पहले से हुई देरी तथा कड़क जैसे दुर्भिक्ष ग्रस्त क्षेत्र में कम से कम एक उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार का विचार इस परियोजना को तत्काल सरकारी क्षेत्र में लेने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख): जी, हाँ। प्रारम्भ में एक प्राइवेट पार्टी को एक औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया था जिस ने उसे लौटा दिया और 1961 में जिसे रद्द कर दिया गया था। अन्य पार्टियों को 1962 और 1964 में आशय-पत्र जारी किए गये थे जिन्हें क्रमश: 1964 और 1965 में रद्द कर दिया गया था, क्योंकि पार्टियों ने इस परियोजना को लागू करने में कोई रुचि नहीं दिखाई ।

(ग) से (ङ) सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया ने इस स्थल पर सूराख और खुदाई का कार्य पूरा कर लिया है किन्तु उस ने सरकार को मंजूरी के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है । कारखाने की स्थापना पर कारपोरेशन से परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो जाने और उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जायगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय काफी करार

3806. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** **डा० सूर्य प्रकाश पुरी :**
श्री म० ला० सोंधी : **श्री रामजी राम :**
श्री क० प्र० सिंह देव : **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुए अंतर्राष्ट्रीय काफी सम्मेलन में एक पंचवर्षीय करार किया गया है ;

(ख) भारत ने काफी के निर्माण की कितनी मात्रा की मांग की थी और वह कहाँ तक स्वीकार की गई ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन देशों को, जिन पर अंतर्राष्ट्रीय काफी करार लागू नहीं होता, काफी का निर्यात बढ़ाने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) भारत द्वारा मांगे गये 27,600 मैट्रिक टन के मूल्य निर्यात कोटे की बजाय 25,380 मे. टन का मूल कोटा स्वीकार किया गया है ।

(ग) जी, हाँ ।

Manufacture of paper in Hastinapur

3807 **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to refer the reply given to Unstarred Question No. 7249 on the 28th July, 1967 and state :

(a) whether it is a fact that a special type of grass can be easily grown in Hastinapur District Meerut, U. P. for manufacturing paper;

(b) if so, whether Government propose to set up a paper factory in the said area; and

(c) if so, when ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) Activities pertaining to the Agriculture of the type referred to are the concern of State Govts. and in this case, the Central Govt. have not been informed of any such plans by U. P. Govt.

(b) and (c) There is no proposal to set up any paper factory in the area in question.

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा इस्पात के माल का निर्यात

3808. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के ईरान को भेजे जाने वाले माल में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने ईरान को इस्पात का निर्यात कब तथा किस एजेन्सी के माध्यम से आरम्भ किया था ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकारी स्तर पर द्विपक्षीय निर्यात प्रबन्ध को हाल में समाप्त कर दिया गया था ;

(घ) क्या ईरान में एक गैर-सरकारी फर्म को ऐजेन्सी दे दी गई थी ; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे और एजेन्सी की शर्तें क्या थीं ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) और (ख) हिदुस्तान स्टील लिमिटेड ने वित्त-वर्ष 1964–65 में ईरान को निर्यात करना आरम्भ किया था । निर्यात भारतीय निर्यात कर्ताओं द्वारा तथा ईरान में सीधा क्रेताओं को किया जा रहा है । हाल ही में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने नये प्रकार के ढांचे बनाने में सफलता प्राप्त की है जिनकी ईरान को आवश्यकता है और कुछ माल भी सप्लाई किया गया है । हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने ईरान की राजकीय रेलवे के लिए नई किस्म की रेल की पटरी भी तैयार की है और 5000 टन के लगभग रेल की पटरी जहाज़ द्वारा भेजी जा चुकी है ।

(ग) भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता है जिसकी अवधि 1970 तक है । इसके अनुसार ईरान भारत से लोहा और इस्पात खरीदने के लिए किसी प्रकार से पाबन्द नहीं है । यह करार खतम नहीं किया गया है ।

(घ) और (ङ) हाल ही में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने ईरान की मार्केट के लिए विशेष रूप से बनाये गये 11,000 टन जोइस्ट्स की सप्लाई के लिए मेसर्स ईरान कम्पनी, तेहरान, के साथ सीधा करार किया है । चूंकि इस सेक्शन का विकास करने के लिए बड़ी मात्रा में आर्डरों की आवश्यकता थी इसलिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को ईरान की एक ऐसी संस्था की आवश्यकता थी जो मूलभूत खरीददारों से जो थोड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं, से आर्डर ले सके। कोई भी पार्टी तीन महीने का नोटिस दे कर समझौते को खत्म कर सकती है । दूसरे माल के लिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का ईरान की किसी पार्टी के साथ एकमात्र समझौता नहीं है ।

Scheme for Shell Button Factories

3809. **Shri K. M. Madhukar**: Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the number of shell botton factories running in Mehsi in District Champaran of Bihar, the amount of capital invested in them and the total number of labourers working there;

(b) whether Government's attention has been drawn towards the problems being faced by those factories;

(c) whether any scheme for the modernization of the said industry is under consideration; and

(d) if so, the details thereof and when it is likely to be implemented ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

New Station between Kanti and Motipur Stations

3810. **Shri K. M. Madhukar**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Railway authorities conducted a survey towards the end of 1967 in regard to the proposal for providing a new station between Kanti and Motipur stations on Muzaffarpur-Narkatiaganj line on the N. E. Railway;

(b) whether it is a fact that after the said survey, the officers concerned had also given an assurance to provide a new station at Virpur (N. E. Railway); and

(c) if so, the reasons for delay in providing this station ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) A proposal for providing a train halt between Kanti and Motipur Stations was examined towards the end of 1967 and it was found that it would result in heavy recurring financial loss. The proposal was, there-fore, dropped.

There was a proposal to provide a crossing station on this section on operating considerations, during the Third Five Year Plan, but due to non-materialisation of the expected traffic, the proposal has not been pursued. If sufficient traffic develops in future, this proposal will be exanined.

(b) No.

(c) Does not arise .

Manufacture of Shell Buttons in Mehsi Bihar

3811. **Shri K. M. Madhukar**: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether Government have explored the possibilities of exporting shell buttons, produced at Mehsi, Bihar, to East European Countries in order to earn foreign exchange;

(b) if not, the reasons therefore; and

(c) whether Government have consulted or propose to consult the businessmen of these countries in this regard and if so, when ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) No, Sir.

(b) Shell buttons face difficult competition from nylon buttons which are cheaper and more attractive and are available in different sizes, designs and colours. Further, mussels shells which are obtained from river beds are not adequate to meet the requirements of all the units located in and around Mehsi.

(c) In view of (b) above, the question does not arise.

जापान से 'रोल्ड' इस्पात का आयात

3812. **श्री वामानी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री जापान को लौह् अयस्क के निर्यात के बारे में 13 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 198 के उत्तर के सम्बन्ध में यह् बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम जापान से 'रोल्ड' इस्पात आयात करने के लिये सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी) : (क) जी, हां ।

(ख) फरवरी, 1968 में लौह् अयस्क की बिक्री के सम्बन्ध में खनिज तथा धातु व्यापार निगम का एक प्रतिनिधि मंडल जापान गया था, तब यह् तय हुआ था कि वर्ष 1968 तथा 1969 में खनिज तथा धातु व्यापार निगम 40 लाख अमरीकी डालर के कुल मूल्य तक (जहाज तक निःशुल्क आधार पर) के इस्पात उत्पादों का जापान से आयात करेगा । परिमाण एवं श्रेणियों का निर्णय भारतीय उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं तथा जापानी इस्पात कारखानों के उत्पादन को ध्यान में रख कर किया जायेगा । इस्पात के आयात के लिये उपलब्ध सहायता व्यवस्था अथवा येन ऋण अथवा अन्य किसी ऋण के अंतर्गत की गई खरीदों को भी 40 लाख डालर की इसी राशि में गिना जायेगा ।

रेलवे में मिस्त्रियों के पदों की वर्गोन्नति

3813. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **रेलवे** मंत्री यह् बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह् सच है कि 26 नवम्बर, 1967 को रेलवे बोर्ड ने कुशल श्रमिकों के काम का पर्यवेक्षण करने वाले मिस्त्रियों के पदों को वर्गोन्नत करने के लिये आदेश संख्या ई(एस) 1-57टी॰ आर॰ बी॰/7 जारी किया था;

(ख) क्या विभिन्न रेलों द्वारा इस आदेश को क्रियान्वित किया गया था; और

(ग) 1 अप्रैल, 1957 से लेकर अब तक पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में कितने मिस्त्रियों की वर्गोन्नति की गई ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे॰ मु॰ पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सूचना मंगायी जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पैकेटों में चाय का निर्यात

3814. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पैकेटों में चाय का निर्यात बढ़ रहा है;

(ख) क्या खुली चाय की अपेक्षा इसका अधिक मूल्य प्राप्त होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो उसके निर्यात को और अधिक बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी) : (क) हाल ही के महीनों के पैकेट बन्द चाय के निर्यात के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) पैकेटों में चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार ने पहिले ही पैकेट बन्द चाय पर निर्यात शुल्क की रियायती दरें प्रदान की हैं। कुछ अन्य उपायों पर भी विचार हो रहा है।

रेलवे में लोगों को यात्रा सम्बन्धी रियायतें

3815. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों को दी गई यात्रा सम्बन्धी कुछ रियायतें हाल में वापिस ले ली गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). जी हां। पहले व्यावसायिक मनोरंजन कम्पनियों या पार्टियों (नाटक, संगीत और सर्कस पार्टियों तथा संगीत व नृत्य मंडलियों) को, कम से कम 5 व्यक्तियों की टोलियों में यात्रा करने पर और प्रशिक्षित नर्सों या दाइयों तथा छात्रा नर्सों व छात्रा दाइयों को जो रियायतें दी जाती थीं, वे 1-2-1968 से समाप्त कर दी गयी थीं।

लेकिन, पुनर्विचार के बाद, सर्कस कम्पनियों द्वारा, पूरे डिब्बों में बुक किये गये सामान और उपस्कर, जिनमें जानवर भी शामिल हैं, के लिए पुनः एक विशेष दर लागू करने का विनिश्चय किया गया है।

यह भी विनिश्चय किया गया है कि जो छात्रा नर्सें और छात्रा दाइयां अस्पतालों में या इण्डियन नर्सिंग कौंसिल या किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त किन्हीं अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण ले रही हों, उन्हें भी रियायत दी जाये।

इस मामले पर आगे और विचार किया जा रहा है।

Chain-Pulling Between Naini and Allahabad Stations

3816. **Shri Jageshwar Yadav** : W(ll the Minister of **Railway** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the 'Pandas' of Allahabad get the chains of trains pulled by goondas between Naini and Allahabad stations on the Central Railway:

(b) whether it is also a fact that as a result of this chain pulling the passengers miss their trains for onward journey from Allahabad junction and Naini station and they have to wait there for a full day; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government in the matter ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) Government are not aware of any such activity. As a matter of fact the incidence of alarm chain pulling between Naini and Allahabad is insignificant.

(b) No.

(c) Does not arise.

Manhandling of Railway employee at Sarai Rohilla Station

3817. **Shri Lakhan Lal Kapoor**: Will the Minister of **Railways** be pleased tp state:

(a) whether it is a fact that on the evening of the 24th February, 1968 a class IV Railway employee was manhandled and injured by some goondas at Sarai Rohilla Station ;

(b) whether it is also a fact that the said employee had also reported the matter to the Station Master, G. R. P. and Divisional Superintendent; and

(c) if so, the action taken by the Railway Police in the matter so far ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग के साथ व्यापार करार

3818. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जम्बर्ग और भारत के बीच एक द्विपक्षीय कपड़ा करार पर हाल ही में हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस करार को, जो 1 जनवरी, 1968 से तीन वर्षों की अवधि के लिये लागू रहेगा, शर्तों के अन्तर्गत भारत प्रति वर्ष बेनलक्स देशों को 1,300 मे० टन सूती वस्त्र तथा करार में उल्लिखित तैयार वस्तुएं निर्यात कर सकता है । इस कोटे में प्रत्येक किस्म की उच्चतम सीमाएं निर्धारित कर दी गई हैं । हथकरघा वस्त्र इस करार से मुक्त हैं अतः इस कोटे से अतिरिक्त मात्रा का निर्यात किया जा सकता है ।

अखबारी कागज निर्माण कारखाने

3819. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी, गैर-सरकारी तथा सहकारी क्षेत्र में एक एक अखबारी कागज निर्माण कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है;

(ग) ये कारखाने कहां स्थापित किये जायेंगे और उनमें से प्रत्येक कारखाने की उत्पादन क्षमता क्या होगी; और

(घ) इस योजना द्वारा अखबारी कागज़ उत्पादन क्षमता कहां तक बढ़ाने का विचार है और यह योजना कब तक कार्यान्वित की जायेगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). सरकारी, गैर-सरकारी अथवा सहकारी क्षेत्र में अखबारी कागज़ बनाने वाले संयंत्रों की स्थापना सम्बन्धी सभी प्रस्तावों की अभी जांच की जा रही है और उनके स्थान या आकार के बारे में अभी तक कोई भी निर्णय नहीं किया गया है।

कच्चे रेशम पर आयात शुल्क

3820. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कच्चे रेशम पर आयात शुल्क में कटौती करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी;

(ग) आयात शुल्क में इस कटौती के परिणामस्वरूप आयातित कच्चे रेशम का मूल्य कितना कम होगा; और

(घ) स्वदेशी कच्चे रेशम की उत्पादन लागत की तुलना में यह कितना कम अथवा अधिक होगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

अरंडी के तेल का निर्यात

3821. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्राजील द्वारा अरंडी के तेल का मूल्य 450 डालर से 435 डालर प्रति टन कर दिये जाने के कारण भारत से अरंडी के तेल के निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ख) भारतीय अरंडी के तेल की लागत को घटाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ताकि विदेशी मण्डियों में भारतीय तेल ब्राजील के तेल से प्रतिस्पर्धा कर सके ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) ब्राजील द्वारा मूल्यों में की गई ऐसी किसी कटौती की सरकार को जानकारी नहीं है। फिर भी भारतीय अरंडी के तेल के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता कर पा रहे हैं।

Change in the Name of Patna Junction and Patna station

3822. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the residents of Patna have been demanding [for some time that the names of Patna Junction and Patna City Stations on the Eastern Railway be changed to Patliputtra and Patna Saheb respectively;

(b) whether the Bihar Government have also supported the change in the names of aforesaid stations;

(c) if so, the reaction of Government thereto; and

(d) the time likely to be taken in implementing this change in the names ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) A representation was received from the Prabandhak Committee, Shri Takhat Harimandirji Patna City to change the name of 'Patna City' railway station to 'Patna Saheb'. Norepresentation from the residents of Patna for changing the name of 'Patna Jn' railway station to' Pataliputtra' has been received in this Ministry. A proposal to this effect made by the State Government of Bihar is however, under consideration.

(b) Yes.

(c) The proposals are under examination by the Ministry of Home Affairs in consultation with the Ministries concernned including the Ministry of Railways.

(d) This Ministry is not in a position to furnish this information at present.

कोयले की खनन लागत

3823. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1958 में कोयला मूल्य पुनरीक्षण समिति द्वारा लागत ढांचे पर प्रतिवेदन दिये जाने के पश्चात् प्रशुल्क आयोग द्वारा किये गये मूल्यांकन के अनुसार कोयले की खनन लागत में काफी वृद्धि हो गई है ;

(ख) कोयला खनन के लिये आर्थिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता के संबंध में प्रशुल्क आयोग की सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) हां, महोदय।

(ख) प्रशुल्क आयोग ने कोयला खनन के लिये अपनी सिफारिश की हुई मूल्य संरचना में दूसरी बातों के अतिरिक्त मशीनों को बदलने के लिये उदार छूटें कार्यवाहक पूंजी पर 3.75% प्रत्यावर्तन,

शुद्ध नियत परिसंपत् पर 15% प्रत्यावर्तन संभाव्यताओं पर एक $2\frac{1}{2}$% उपबन्ध और संग्रहों के मूल्यों को अद्यावधिक करने के लिये एक और अधिक उदार प्रबन्ध देकर प्रोत्साहन दिया है। इसके अतिरिक्त प्रति मनुष्यपारी का उत्पादन जो कि खनन मूल्यों की सभी गणनाओं का आधार है महासंचालक खान सुरक्षा द्वारा विभिन्न भागों जैसे बंगाल, बिहार और दूरस्थ क्षेत्रों इत्यादि पूरे क्षेत्रों के लिए, प्रकाशित आंकड़ों से कम लिया गया है। राजसहाय्य के संबंध में, यथार्थ और मितव्ययता से किये गये खर्चों को पूर्णरूप से निष्फल करने की सिफारिश की गई है।

(ग) राजसहाय्य का प्रश्न एक अध्ययन समूह को जांच करने के लिये सौंपा गया है। सब प्रकार के कोयले और साफ्ट कोक पर से मूल्य नियंत्रण हटा लिया गया है।

New Industries in Mysore

3824. **Shri Ramchandra Veerappa:** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether any new industries are proposed to be established in the public sector during the Fourth Five Year Plan in Mysore State;

(b) If so, tbe locations thereof; and

(c) the types of such industries ?

The Minister of Industrial Development and Comapany Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) to (c). The work on the Fourth Plan, which is to begin from April, 1969 has just been initiated. An idea of the programme of industries to be established in the public sector would be available when the detailed studies on the Fourth Plan are completed.

वैस्टीबुलर गाड़ियां

3825. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल गाड़ियों में हत्याओं और अन्य अपराधों की रोकथाम करने और बिना टिकट यात्रा को करने के लिये वेस्टीबुलर गाड़ियां चलाने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) और (ख). गलियारेदार गाड़ियां भारतीय रेलों में पहले से चल रही हैं। यह एक स्वीकृत नीति है कि जैसे जैसे कारखानों से गलियारे के लिए उपयुक्त डिब्बे तैयार हो कर निकलें, भारतीय रेलों में क्रमशः अधिक से अधिक गलियारेदार गाड़ियां चलायी जायें।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

3826. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में कुल कितनी पूंजी लगी हुई है तथा उसकी कुल औसत वार्षिक बिक्री क्या है ;

(ख) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की बिक्री इसी प्रकार के गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की बिक्री के मुकाबले में अच्छी है ;

(ग) यदि नहीं, तो अब तक कुल कितनी हानि उठाई गई है तथा उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) बिक्री की दरों में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) से (घ) . सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

3827. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहयोग के संबंध में दिनांक 13 फरवरी, 1968 के "इंजीनियरिंग टाइम्स" में हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा व्यक्त किये गये विचारों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उ ता ।

कोट्टयम में क्षेत्रीय चाय बोर्ड

3828. श्री नंजा गौडर : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल लघु चाय उत्पादक संस्था ने प्रार्थना की है कि कोट्टयम में क्षेत्रीय चाय बोर्ड कार्यालय खोला जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां,तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रार्थना को स्वीकार करना सरकार के लिए संभव नहीं है ।

रेलवे के कर्मचारी निरीक्षक और कल्याण निरीक्षक

3829. श्री य० आ० प्रसाद : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी निरीक्षक और कल्याण निरीक्षक दोनों का संबंध कर्मचारी शाखा से है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्तर रेलवे में 210—320 के ग्रेड में काम करने वाले सहायक कर्मचारी निरीक्षक और 250—380 के ग्रेड में काम करने वाले कर्मचारी निरीक्षक गत 8 से 12 वर्षों से उसी ग्रेड में काम कर रहे हैं क्योंकि उच्चतर ग्रेड बहुत कम हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उच्चतर ग्रेड के पदों में उनके लिये कोई प्रतिशतता निर्धारित नहीं की गई है जैसा कि अन्य श्रेणियों के मामले में किया गया है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि उत्तर रेलवे में सहायक कल्याण निरीक्षकों और कल्याण निरीक्षकों के लिये 250—380 और 335—425 के ग्रेड में पदोन्नति के ज्यादा अवसर हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो दोनों श्रेणियों में पदोन्नति के अवसरों में समानता लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ङ). सूचना मंगायी जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में कच्चे लोहे के कारखाने

3830. **श्री वामानी** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र में कच्चे लोहे के कारखाने स्थापित करने के कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई निर्णय किया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) आजकल निजी क्षेत्र में लौह अयस्क के कारखानों की स्थापना के लिए आशय-पत्र देने के बारे में किसी आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Railway Security Special Force

3832. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of persons recruited in Railway Security Special Force, category-wise, during the period from 1962 to January, 1968; and

(b) the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes among them ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the table of the House.

Hindi Work in Railway Ministry

3833. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3273 on the 30th June, 1967 and state :

(a) whether it is proposed to maintain all record relating to Class III and Class IV employees in Hindi;

(b) if not, the reasons therefor;

(c) whether the records at Railway stations are maintained in Hindi;

(d) if not, the reasons therefor; and

(e) whether it is proposed to display the tables regarding arrival and departure of trains in Hindi on the boards at Delhi and New Delhi Stations?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) and (c). No.

(b) and (d). No decision has so far been taken for maintaining such records in Hindi.

(c) Boards displaying times of arrival and departure of trains have already been provid ed in Hindi also at Delhi and New Delhi stations.

Classes of Railway Passengers

3834. **Shri Molaha Prasad**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to convert the existing four classes of Compartments on Railways into one or two classes in future ;

(b) if so, when; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No such proposal is at present under consideration.

(b) In view of the answer to part (a) the question does not arise.

(c) The present arrangement of different classes of travel on Indian Railways is tailored to the needs of the customers and necessity has not been felt for making any change.

Work in Hindi

3835. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Industrial and Development and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4271 on the 30th June, 1967 and state:

(a) the reasons for which work has not been started in Hinidi in any of the Sections under his Ministry; and

(b) the time by which it is proposed to be started in Hindi in the non-technical divisions ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) and (b) Notings on files in Hindi have since been started on cases, which are not of a complicated nature, in a few Sections in the Department of Industrial Development.

हैवी इलेक्ट्रिकल संयन्त्र

3836. **श्री रा० बरुआ** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हैवी इलैक्ट्रिकल संयंत्रों में असामान्य औद्योगिक अशान्ति के कारणों का पता लगाने के लिये कोई अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) इन कारणों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :(क) से (ग) हैवी इलेक्ट्रिकल्स संयंत्रों में असाधारण औद्योगिक अशांति जैसी कोई स्थिति नहीं है। श्रम समस्याओं को कारखाने विशेष में विद्यमान स्थितियों के अनुसार निबटाया जाता है, अत: कोई ऐसा सामान्य अध्ययन करना अभी तक आवश्यक नहीं समझा गया है जैसा कि सुझाव दिया गया है।

Allotment of quarters to Railway Employees in Delhi

3837. **Shri Chandra Shekhar Singh:** Will the Minster of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that allotment of quarters to railway employeees in Delhi is not made according to the date of their appointment;

(b) if so, the basis on which allotment of quarters is made; and

(c) the reasons for which allotment of quarters is not made according to the date of appointment?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) Priority of allotment of quarters to Railway employees is determined by the date of registration with the allotting authority according to the date of receipt of their applications.

(c) The existing procedure is being followed uniformly on all Railways for many years and has been working satisfactorily. A change in existing practice in Delhi area is not feasible as this will have repercussion on all Railways and is likely to create many new problems.

रासायनिक संयन्त्र तथा मशीनरी संस्था

3838. **श्री सुदर्शनम :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिजली संयंत्र तथा सम्बद्ध क्षेत्रों से संबंधित अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदने में गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों की क्रयनीति के बारे में भारतीय रासायनिक संयंत्र तथा मशीनरी संस्था ने सरकार से विरोध प्रकट किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है ।

खनन तथा सम्बद्ध मशीनरी निगम, दुर्गापुर

3839. **श्री च० चु० देसाई :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनन तथा सम्बद्ध मशीनरी निगम, दुर्गापुर ने अपना कार्य कब आरम्भ किया था;

(ख) क्या यह सच है कि निगम ने अपने आरम्भ से लेकर अब तक कोई मुनाफा नहीं कमाया है अपितु 1965–66 की 2 42 लाख रुपये की हानि की तुलना में 1966–67 में लगभग 4 72 लाख रुपये हानि है ;

(ग) क्या 1965–66 की तुलना में 1966–67 के वेतन में वृद्धि हुई है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) कौल माइनिंग मशीनरी प्रोजेक्ट, जो बाद में माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि० के नाम से अलग एक कम्पनी के रूप में बना दी गई थी, में 1963 में आंशिक रूप से उस समय काम शुरू किया गया था जब कि वह हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची का एक भाग था।

(ख) कारपोरेशन को उसके निर्माण से लेकर कोई भी लाभ नहीं हुआ है। उसे 1965–66 में 2,08,24,164 रु० और 1966–67 में 4,71,51, 560 रु० की हानि हुई थी।

(ग) जी हां, और

(घ) कुल वेतन बिलों में वृद्धि कर्मचारियों की वार्षिक वृद्धि और बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता देने के कारण हुई थी।

खनन तथा सम्बद्ध मशीनरी निगम

3840. श्री चं० चु० देसाई : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनन तथा सम्बद्ध मशीनरी निगम दुर्गापुर की अर्थव्यवस्था में काफी समय से चली आ रही मन्दी के कारण विगत एक वर्ष से भी पहले सरकार ने इस कारखाने के उत्पादन के तौर तरीके तथा प्रशासन में काफी परिवर्तन किये थे और इसमें उसे कोई खास सफलता नहीं मिली है ;

(ख) क्या रूसी सहयोग से लगभग 31 करोड़ रुपये की लागत पर इस कारखाने को लगाने का उद्देश्य आत्म निर्भर प्राप्त करना था और बाद के वर्षों में अपेक्षित मात्रा में कोयले न मिलने के कारण उत्पादन को विविध प्रकार का बना देने का कार्यक्रम बनाना पड़ा था ; और

(ग) क्या कोयला खनन उपकरणों की पर्याप्त मांग न होना, उत्पादन संबंधी कार्यक्रम में विविधता लाना, उपकरणों को प्राप्त करने तथा चालू करने में विलम्ब और श्रमिका कम उपयोग ही उत्पादन में कमी के कारण ठहराये जा सकते हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). कोयला खनन मशीनी परियोजना की स्थापना भारी इंजीनियरी निगम, राँची के अंग के रूप में रूसी सहायता से की गई थी और परियोजना की अनुमानित लागत 31 करोड़ रुपये थी। इस परियोजना की स्थापना के लिये अप्रैल, 1965 में माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर नामक एक अलग कम्पनी बनाई गई थी। परियोजना की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना में 760 लाख मी० टन कोयले की आवश्यकता पूरी करने के लिए की गई और जिसकी क्षमता चौथी पंचवर्षीय योजना में बढ़ कर 1360 लाख मी० टन हो जायगी। संयंत्र ने 1965–66 में 5000 मी० टन कोयला खनन मशीनों तथा उपकरणों के उत्पादन से प्रारम्भ करके 1971–72 में 45,000 मी० टन का उत्पादन करना था। फिर भी कोयले के उत्पादन लक्ष्य में कमी किए जाने तथा खानों के मशीनीकरण की गति मन्द होने के कारण उन उपकरणों के, जिनके निर्माण के लिए इस की स्थापना की गई थी, आर्डर कम मिलने के कारण इस संयंत्र को इकट्ठे आर्डर देने की दृष्टि से यह आवश्यक हो गया था कि इसके उत्पादन में विविधता लायी जाय। इस विविधता के लिए प्रशासकीय तथा संगठनात्मक परिवर्तन करना आवश्यक हो गया था जिनके परिणामों का पता कुछ समय बाद ही चलेगा। इस संयंत्र में वास्तविक उत्पादन मूल रूप में निर्धारित क्षमता से कम रहा है। इसका कारण आंशिक रूप से विविधता संबंधी कार्यक्रम अपनाने से संयंत्र की कुछ कर्मशालाओं में असंतुलन

उत्पन्न हो गया है और आंशिक रूप से श्रमिक वर्ग की अपेक्षाकृत उत्पादिता कम हो जाना है। इस संबंध में सुधार करने के लिये प्रोत्साहन योजनाएं लागू करना तथा तकनीकी विभागों का पुनर्गठन जैसे कुछ उपाय किए गए हैं।

'चामाग्राम' स्टेशन का रेलवे यार्ड

3841. **श्रीमती उमाराय :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में 'चामाग्राम' रेलवे स्टेशन के यार्ड से बहुत से अपराधियों द्वारा प्रतिदिन भारी मात्रा में लोहे और इस्पात का सामान, खाद्यान्न तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुयें ड्यूटीपर तैनात रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों और अधिकारियों की जानकारी से चुराई जा रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर रेलवे सुरक्षा दल के मुख्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा ऐसी चोरियां को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं। 1966 और 1967 में लोहे और इस्पात के सामान की चोरी की कोई घटना नहीं हुई। 1967 में यार्ड में चोरी की केवल 3 घटनाओं की रिपोर्ट की गयी थी जबकि 1966 में 2 घटनाओं की रिपोर्ट की गयी थी। जहाँ तक अनाज की चोरी का संबंध है, 1967 में 10 और 1966 में 5 मामलों की रिपोर्ट की गयी थी।

(ख) निम्नलिखित निवारक उपाय किये गये हैं :—

(i) प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल के कार्मिकों द्वारा सशस्त्र गश्त की व्यवस्था ;

(ii) अनाज और अन्य अनिवार्य माल ले जाने वाली गाड़ियों में अनुरक्षकों की नियुक्ति ; और

(iii) पश्चिमी बंगाल वाले हिस्से में जिन स्टेशनों पर चोरी की घटनाएं अधिक होती हैं, वहाँ राज्य प्राधिकारियों द्वारा पुलिस के कर्मचारी तैनात किये गये हैं ताकि चावल की तस्करी की रोक-थाम की जा सके और तस्करी के चावल और तस्करों को पकड़ा जा सके।

Flour and Maida Mills

3842. **Shri P. L. Barupal:** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of flour and maida mills owned by the Jaju firm in different States;

(b) when each Mill was established, the number of those which were established with prior permission of the Central Government and the number of those in respect of which permission was sought for after their establishment;

(c) whether it is a fact that the Assam Flour Mills which was allotted a wheat quota of 20 tons, got this quota subsequently raised to 70 tons and later 100 tons and if so, the reasons therefor; and

(d) whether any memorandum or complaint against this mill was submitted to the former Home Minister and if so, the action taken thereon ?

The Minister of Industrial development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) There are eight flour mills in different States in which some of the Jajus have interests.

(b) Three of these units were licenced during 1959, 1966 and 1967 respectively and one has been permitted to be set up by the Government. The remaining are not licensed under the Industries (Development & Regulation) Act.

(c) M/s. Assam Flour Mills, Gauhati has been licensed for a capacity of 60 tonnes per day on single shift.

(d) we have no such information.

Stopping of Trains with Automatic Devices

3843. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any proposal has been submitteed to the General Manager, North Eastern Railway from Mahendru (Patna) in connection with the stoppage of trains with automatic devices;

(b) whether he has claimed that he can stop two trains coming from two different directions on the same line with the help of his device and there would be no collision between the two trains; and

(c) if so, whether Government propose to test the efficacy of his device so that Railway accidents could be avoided ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

हरयाना में इस्पात कारखाना

3844. **श्री यशपाल सिंह** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरयाना राज्य में एक इस्पात कारखाना लगाने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके लिये कौन सा स्थान चुना गया हैं ; और

(ग) उसके लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Fifth Steel Plant

3845. **Shri Nathu Ram Ahirwar;** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether any agreement was concluded with the British American Steel Works for India Consortium regarding the establishment of the fifth Steel Plant in the Public Sector;

(b) the names of the places which were selected by BASIC for the proposed plant and the names of the States where they are situated;

(c) the place, among those selected where Government propose to set up the fifth Steel Plant;

(d) whether any of the States, in which places for setting up the Plant have been selected, have demanded that the plant should be established early and if so, the names of those states and the action taken by Government thereon ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy): (a) to (d). The Government of India entered into an agreement on January 27, 1965 with the British American Steelworks for India Consortium (BASIC) to investigate six different sites in three areas:—

(i) Bailadila-Visakhapatnam

(ii) Salem- Neyveli; and

(iii) Hospet-Goa

suitable for location of the Fifth Steel Plant in the Public Sector, and recommend two sites in order of preference to the Government for their final selection. the Consortium in their Site Location Report, which was submitted to the Government on June 25, 1965 recommended two sites—(i) Visakhapatnam in Andhra Pradesh; and (ii) Hospet in Mysore; and of these two they preferred Visakhapatnam. Claims were received from the State Governments including Andhra Pradesh and Mysore for establishment of Fifth Steel Plant within their respective areas.

The question of setting up the Fifth Steel Plant in the Fourth Year Plan is being reviewed in the context of the expected demand and the availability of resources, and no final decision has been taken in this regard so far.

भारतीय मानक संस्था के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

3846. श्री भगवान दास :
श्री एस्बोस :
श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय मानक संस्था दिल्ली के कर्मचारियों ने 6 फरवरी, 1968 को भारतीय मानक संस्था कार्यालय दिल्ली के सामने प्रदर्शन किया था ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) इस विवाद का निपटारा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग). इस प्रदर्शन में भारतीय मानक संस्था के कर्मचारी संघ की विशेष माँग यह थी कि उन मामलों में मकान के किराये की रसीद दिये जाने पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए जिनमें 20 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर पर मकान किराये भत्ते का दावा किया जाता है क्योंकि 15 प्रतिशत तक भत्ते के दावे पर इसकी आवश्यकता नहीं होती है। इस मामले को भारतीय मानक संस्था द्वारा निपटाया जा रहा है और इसके आपस में ही तय हो जाने की आशा है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

"एम० वी० विश्वशांति" जहाज का कांस्टेन्टजा के निकट धंस जाना

Shri Sita Ram Kesri (Katihar). Sir, I call the attention of the hon. Minister of **Transport and Shipping** to the following matter of urgent public importance and request him to make a statement thereon :—

"Reported grounding of M. V. "Vishva Shanti." near Conrstantza port in Rumania on 1st March, 1968."

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मुझे यह सूचित करते हुये दुःख है कि हमारा एक अच्छा वा० पौ० 'विश्व शाँति' जो सरकारी शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि० का था जब कि कांस्टेंटजा के रूमानियन बन्दरगाह के निकट पहुंच रहा था 1 मार्च, 1968 को 18.50 घंटे पर पत्तन सीमाओं के बाहर पनकट दीवार में धंस गया और अत्यधिक क्षतविक्षत हो गया। सरकार को यह जानकर बड़ा शोक है कि एक सामान्य कर्मचारी श्री ए० एम० डि सिल्वा की मृत्यु हो गई। उसके निकट संबंधियों को सूचित कर दिया गया है और क्षतिपूर्ति की अदायगी के लिये प्रबंध कर लिये गये हैं। मुझे विश्वास है कि सभा सन्तप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने में मेरा साथ देगी। जीवन की सुरक्षा निश्चयन करने के लिये 2 मार्च, 1968 को 03.00 बजे अधिकारियों और अन्य कर्मीदल जो संख्या में उनसठ थे पोत से हटा लिये गये। क्षति के समय ऋतु की दशा सामान्य से खराब की ओर थी। हल्की वर्षा हो रही थी और रोशनी बन्द हो रही थी।

2 मार्च, 1968 को पोत के मास्टर से पहली रिपोर्ट की प्राप्ति पर तुरन्त ही शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया ने बुखारेस्ट में भारतीय दूतावास को घटनास्थल पर जांच पड़ताल करने का और सब संभव सहायता करने का केबल दिया। समुद्री और युद्ध संकट के विपरीत पोत का बीमा भारत के जीवन बीमा निगम से किया हुआ है और वैयक्तिक अन्य बचाव और क्षतिपूर्ति संकटों के बारे में पोत की क्षतिपूर्ति प्रोटेक्शन एण्ड इंडेमनिटी क्लब, मेसर्स स्टीमशिप म्यूचुअल अंडरराइटिंग एसोसियेशन लि० लंदन द्वारा की जानी ह उन्हें भी तुरन्त सूचित कर दिया गया है और पोत तथा माल का उद्धार करने की कार्यवाही करने के लिये लन्दन के सालवेज एसोसिएशन से संपर्क स्थापित किया गया। सालवेज एसोसिएशन का इंस्पेक्टर पोत तथा माल की हानि का सर्वेक्षण करने तथा तकनीकी तौर से भग्न पोत, पोत के उपस्कर और जिस सीमा तक संभव हो वहाँ तक माल का अभिनिर्धारण करने के लिये घटनास्थल पर पहुंच गया है। इसके बाद पत्तन अधिकारियों की सलाह से निर्णय लिया जायेगा कि कौन से बचाव के उपाय किये जा सकते हैं। अभिनिर्धारण में कुछ दिन और लगेंगे। एक प्रवर तकनीकी अधिकारी और शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया के मास्टर मरीनर विमान द्वारा कांस्टेंटजा पहुंच गये हैं और घटनास्थल निरीक्षण करने तथा रिपोर्ट देने के लिये 4 मार्च, 1968 से दुर्घटना स्थल पर है।

जल परिवहन विभाग का एक समुद्री सर्वेक्षक भी व्यापारिक नौवहन अधिनियम 1958 के अधीन पोत के तल में बैठने के कारणों की प्रारंभिक जाँच करने के लिये 10 मार्च, 1968 को कांस्टेंटजा पहुंच गया है। कांस्टेंटजा का हारबर मास्टर भी तल

में बैठ जाने के कारणों की जाँच पड़ताल कर रहा है। वह अभी अपने परिणामों पर नहीं पहुंचा है ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० विशाखापत्तनम में इस्पात से बना 12407 डडवेट टनेज और 9191 कुल टनभार का पोत जो 7650 बी० एच० पी० के मान इंजन से फिट था 145.98 लाख रुपये की कुल लागत पर 1962 में शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा खरीदा गया था। विशाखापत्तनम पर इसके निर्माण की देखभाल पोत-निर्माताओं, भारत के नौवहन निगम, लिमिटेड, और श्रेणीकरण सोसाइटी अर्थात् लोइड्स रजिस्टर आफ शिपिंग के तकनीकी अधिकारियों द्वारा की गयी थी। जहाज, मशीनों और माल-संस्थापन लोइड्स रजिस्टर आफ शिपिंग के नियमों के अनुसार सर्वेक्षणों की देखरेख में बनाये गये थे । जल परिवहन विभाग के सर्वेक्षकों ने सुरक्षा उपस्कर और कर्मीदल के आवास का निर्माण के दौरान निरीक्षण किया (निर्माण के पूरा होने पर और सुपुर्दगी के समय जहाज का सर्वेक्षण और निरीक्षण इस बात के सुनिश्चित के लिए किया गया कि सांविधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाये और हमारे जल परिवहन विभाग द्वारा सांविधिक प्रमाण पत्र जारी किये गये । श्रेणीकरण सोसाइटी में इस जहाज का उच्चतम दर्जा था और इसमें नवीन मार्ग-निर्देशक उपस्कर थे ।

गत 6 वर्षों में इस जहाज ने संसार के विभिन्न भागों की 14 यात्राएं की जिनमें काला सागर के पत्तनों की यह यात्रा भी शामिल है । 1964 में इसका गारंटी ड्राई-डाकिंग किया गया और प्रथम विशिष्ट सर्वेक्षण 1967 में किया गया ।

भारतीय नौवहन का रिकार्ड प्रशंसनीय रहा है । लगभग गत दस वर्षों से हमारी नौवहन लाइनें रूमानियाँ तक नियमित सेवाएं चलाती आ रहीं हैं और काँस्टेंटजा जाने वाले जहाजों में भी वृद्धि हुई है । भारतीय जहाजों ने 1966 और 1967 में इस पत्तन की क्रमशः 19 और 22 यात्राएं की । यह पहला भारतीय जहाज है जो इस पत्तन पर दुर्घटना ग्रस्त हुआ ।

इस दुर्भाग्यपूर्ण यात्रा में इस जहाज में 9891 टन माल लदा हुआ था जिसमें शलाक, चाय, इस्पात, चेन्नल, तंबाकू, काली मिर्च, पामिरा फाइबर इत्यादि था जो कलकत्ता, मद्रास और कोचीन से जा रहा था । कोचीन में यह जहाज क्षमताशील और योग्य अधिकारियों और कर्मिक दल सहित और सब वैध सांविधिक कागजों के साथ 11 जनवरी, 1968 को चला । रिजेका (युगोस्लाविया), अलक्जेड्रिया (यू० ए० आर०) और वरना (बलगेरिया) पत्तनों से होते हुए चला और इन पत्तनों पर माल उतारने के बाद इसमें काँस्टेंटजा में भूमि में धंसने के समय 4137 टन माल था ।

ताजी रिपोर्टों के अनुसार जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और कई जगहों पर टूट गया है और संपूर्ण जहाज की हानि हो गयी है । माल को हुई हानि या क्षति अभी मालूम नहीं है । जहाज की कुल बीमा लागत 210 लाख रु० है। जीवन बीमा निगम और उसकी सहयोगी भारतीय बीमा कंपनियों ने 50 से 60 लाख रुपये तक का जोखिम अपने ऊपर ले लिया है और बीमा लागत की शेष राशि विदेशी बीमा कर्त्ताओं, जो मुख्यतः यू० के० में हैं, द्वारा पूरी की जाएगी ।

Shri Sita Ram Kesri. I want to know as to why the information of ship running around reached the hon. Minister so late ?

This ship had under taking round the world voyages fourteen or fifteen times. I want to know whether a signal regarding clear weather was given to this ship at the time of entry into Rumanian harbour.

डा० वी० के० आर० वी० राव : हमें इस दुर्घटना के समाचार के मिलने में विलम्ब नहीं हुआ है । हमें बहुत जल्दी सूचना मिल गई थी । इस सूचना को अविलम्ब सभी सम्बन्धित विभागों को भेज दिया गया । जहाज को निकालने वाले संगठन को तुरन्त सूचित किया गया था । रूमानिया स्थित हमारे दूतावास को सूचित किया गया और उसका एक अधिकारी दुर्घटनास्थल पर गया और अपेक्षित सहायता की व्यवस्था के लिये कार्यवाही की । मौसम के बारे में पूर्व सूचना के बारे में तो जाँच से पता चलेगा कि स्थिति कैसे थी ?

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मन्दसौर) : यह बड़ी चिन्ता का विषय है कि यह जहाज हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापटनम् में बना था । इस उपक्रम में हमारे देश का बहुत धन लगा हुआ था । अब इस जहाज के इस प्रकार ध्वंस जाने से पता चलता है कि इस जहाज बनाने के कारखाने में काम कैसा होता है । मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप कहाँ जा रहे हैं ? इनकी कार्यप्रणाली त्रुटिपूर्ण है । यह चिन्ता की बात है । क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड के काम में जाँच के लिये विशेषज्ञों की समिति नियुक्त की जायेगी ? दूसरे इस जहाज को समुद्र में यात्रा के योग्य किस प्राधिकारी ने घोषित किया था ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : इस जहाज को लायड्ज रजिस्टर आफ शिपस से प्रमाण-पत्र प्राप्त था । इसने 14 यात्राएं की हुई थीं । खेद की बात है कि दुर्घटनाएं हो जाती हैं । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की इस प्रकार निन्दा नहीं की जानी चाहिये । इस जहाज की यात्रा के लिये योग्यता की जाँच की गई थी और इसे बिल्कुल ठीक पाया गया था । और इस प्रकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर आरोप लगाना उचित नहीं है ।

श्री के० नारायण राव : वक्तव्य से पता चलता है कि इस जहाज को निकालने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है । क्या हमने इस बारे में रूमानिया सरकार के साथ कोई संधि नहीं की हुई है ताकि इस डूबे जहाज को तुरन्त निकाला जा सके ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मेरे पास इस समय इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है । वैसे जैसे मैंने पहले कहा है डूबे जहाजों के निकालने सम्बन्धी संगठन का एक अधिकारी वहां गया है ।

Shri Ravi Ray : I want to know if the family of the deceased officer would be paid any compensation ; if so, how much ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझे ठीक जानकारी नहीं परतु आश्रितों को काफी मुआवजा मिलता है । उस अधिकारी की मृत्यु पर हमें बहुत खेद है । उन्होंने अपना कार्य निभाते हुए मृत्यु का सामना किया और उनकी मृत्यु हो गई ।

श्री देवकी नन्दन पाटौदिया : मुझे मालूम है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड में बने दो जहाजों में निर्माण में त्रुटियाँ पायी गई थीं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके निर्माण में भी कोई त्रुटि पायी गई थी ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं हिन्दुस्तान शिपयार्ड के इतिहास में तो नहीं जाऊंगा परन्तु यह जहाज 1962 में बनाया गया था । इस में निर्माण सम्बन्धी कोई त्रुटि नहीं थी । अब भारत नौवहन निगम के तथा अन्य सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारी आरम्भिक जांच के लिये वहां पहुंच गये हैं और जांच की जायेगी ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

पश्चिमी बंगाल करारोपण विधियां (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : मैं पश्चिमी बंगाल राज्य के संबन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 20 फरवरी, 1968 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213(2) (क) के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल द्वारा 7 जनवरी, 1968 को प्रख्यापित पश्चिमी बंगाल करारोपण विधियां (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 1968 (1968 का पश्चिमी बंगाल अध्यादेश संख्या V) की एक प्रति । सभा पटल पर रखता हूं । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 408—68]

खनिज रियायतें (संशोधन) नियम, 1968

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति, जो दिनांक 2 मार्च, 1968 से भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 370 में प्रकाशित हुए थे । सभा पटल पर रखता हूं । [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी० 409—68]

काफी बोर्ड के प्रमाणित लेखे

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : मैं इन पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

वर्ष 1966–67 के लिए काफी बोर्ड के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षत प्रतिवेदन । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 410—68]

(2) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12-क के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 741 की एक प्रति जो दिनांक 23 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 411—68]

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERSTANDING

कार्यवाही-का सारांश

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj): मैं भारत के राज्य व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा गन्धक के आयात के लिये मैसर्स ओवल इण्डस्ट्रीज, न्यूयार्क, के साथ किये गये करार के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के पांचवें प्रतिवेदन से संबंधित बैठकों के कार्य-वाही-सारांश की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

तेइसवां प्रतिवेदन

श्री खाडिलकर : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तेइसवें प्रतिवेदन की एक एक प्रति सभा पटल पर उपस्थित करता हूं।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

सैंतिसवा तथा चवालीसवा प्रतिवेदन

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मैं निम्न की एक एक प्रति सभा पटल पर उपस्थित करता हूं :—

(1) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय (कृषि विभाग)—केन्द्रीय अन्तर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्था, बैरकपुर—के बारे में सैंतीसवां प्रतिवेदन।

(2) रेलवे मंत्रालय—दक्षिण पूर्व रेलवे —के बारे में प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) के इकानब्बे प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में चवालीसवां प्रतिवेदन।

मारीशस द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त किये जाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT Re: ATTAINMENT OF INDEPENDENCE BY MAURITICUS

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है कि सभा मारीशस को जिसे अब स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है, बधाई देने में मेरे साथ है। हमारे राज्य मंत्री श्री भगत इस समय वहां गये हुए हैं। उन्हें अब उपनिवेश-

वाद से मुक्ति प्राप्त हो गयी है। हम वहां के लोगों की खुशहाली और सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति की कामना करते हैं। और मुझे आशा है कि हमारे बीच पारस्परिक सद्भावना बढ़ेगी।

सदन की ओर से मेरा आप से अनुरोध है कि आप मारीशस के लोगों तथा सरकार को हमारी शुभकामनाएं प्रेषित कर ।

सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा—जारी

GENERAL BUDGET—GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : इस बजट से लोगों में आत्मविश्वास और आशा की भावना जागृत हो गई है। उन्होंने इस बजट के प्रस्तावों का स्वागत किया है। अगले वर्ष सरकार को जो राजस्व प्राप्त हो गया वह वर्ष 1947 में सरकार को प्राप्त हुए राजस्व की तुलना में 10 गुना है। इससे हमारे देश की पिछले 20 वर्षों की प्रगति की एक झलक मिलती है।

इस वर्ष के बजट में आंध्र प्रदेश के लिये बहुत कम व्यवस्था की गई है। इससे हमारे राज्य को बहुत हानि होगी। हमने इस बारे में एक ज्ञापन प्रधान मंत्री को दिया है। मुझे आशा है उप प्रधान मंत्री हमें अवश्य कुछ सहायता देंगे।

इस बजट में दो बात ऐसी हैं कि जिनके बारे में मुझे विशेष रूप से प्रसन्नता नहीं। एक तो पोस्ट कार्डों की दर बढ़ाना ठीक नहीं है। इस से देश के निम्न वर्ग के लोगों पर बोझ पड़ेगा। आपको वाणिज्य प्रयोजनों के लिये प्रयोग में लाया जाने वाला एक अलग कार्ड चालू करना चाहिये। उस कार्ड की दर आप सामान्य कार्ड से अधिक रख सकते हैं। इस प्रकार निर्धन जनता पर बोझ नहीं पड़ेगा। आप फोनोग्राम की दर बढ़ा सकते हैं। इससे भी निम्न वर्ग पर बोझ नहीं पड़ेगा। और सरकार की आय में भी पर्याप्त वृद्धि हो जायेगी। पोस्टकार्ड के कारण हो रही हानि पूरी हो जायेगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर हमारा लगभग 25,00 करोड़ रुपया लगा हुआ है। बहुत से उद्योगों को स्थापित हुए दस से बारह वर्ष तक हो चुके हैं। हमने विदेशों से बढ़िया मशीनरी भी मंगायी है। हमारे देश के कारीगर जब विदेशों में जाते हैं तो उन्हें वहां बहुत अच्छा वेतन मिलता है। हमें अपने देश में अच्छे वेतन देने की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि देश में औद्योगिक प्रगति हो सके।

मजदूरों को पर्याप्त मजदूरी दी जानी चाहिये ताकि वे अधिक उत्पादन कर सकें। इस समय मजदूरों को बहुत कम मजदूरी मिलती है। माननीय मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये। मुझे प्रसन्नता है कि कृषि को प्राथमिकता दी गई है। आंध्र प्रदेश में उद्योग बहुत कम और अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। मुझे खेद है कि इस राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बहुत कम धन की व्यवस्था की गई है। माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि एक संसदीय समिति का गठन करें जो कि राज्यों को दिये जाने वाले धन के व्यय किये जाने तथा प्रयोग में लाने के प्रश्न पर विचार करें। रेलवे के कार्य में भी अब पहले जैसी दक्षता नहीं रही है।

श्री हेम बरूआ (मंगलदाई) : हमारे देश की इस समय की अर्थ व्यवस्था की हालत शोचनीय है। उसी का प्रतिबिम्ब हमें इस बजट में मिलता है। देश में उत्पादन कम हुआ है और मूल्यों में वृद्धि हो गयी है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)
(Mr. Deputy Speaker in the Chair.)

अर्थव्यवस्था में सुधार के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया है। बजट में हमारी अवस्था का ठीक अनुमान नहीं लगाया गया है और भविष्य के लिये भी कोई विशेष उपाय नहीं सुझाये गये हैं। इस में मूल्यों को स्थिर करने के लिये कुछ नहीं किया गया है। इस में पूंजी बाजार को प्रोत्साहन देने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आज हमारे उत्पादन में कमी होती जा रही है परन्तु फिर भी घाटे की अर्थव्यवस्था की जा रही है।

वित्त मंत्री ने पहले कहा था कि घाटे का बजट नहीं बनाया जायेगा परन्तु वह वायदा पूरा नहीं किया गया है। इस बारे में प्रतिवर्ष घाटे की अर्थ व्यवस्था की राशि बढ़ती जा रही है।

वित्त मंत्री ने राज्यों को अपने बजट संतुलित रूप से बनाने को कहा है। उन्होंने स्वयं ऐसा नहीं किया है। घाटे के बजट से मुद्रा स्फीति में वृद्धि होगी और कीमतों में वृद्धि होगी। इस से देश के आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में संतुलन फैलेगा और कई विघटनकारी संगठनों को बढ़ावा मिलेगा।

देश में बढ़ती हुई कीमतों, बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था तथा मुद्रास्फीति के कारण देश के विभिन्न भागों में छुट-पुट क्रांतियाँ हो रही है, परन्तु ये बड़ी क्रांति का रूप भी धारण कर सकती है।

देश में बेरोजगारी प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। इसने अब गम्भीर रूप धारण कर लिया है। इसी कारण देश में विघटनकारी शक्तियाँ उभर रहीं हैं, इनको नारों से नहीं रोका जा सकता। मुझे खेद है कि वित्त मंत्री ने इस समस्या के हल के लिये कुछ नहीं किया है यद्यपि चुनाव में हार गये कांग्रेस सदस्यों को लाभ के पदों पर लगा दिया गया है

जहाँ तक कृषि का संबंध सरकार के विभिन्न विभागों ने अलग अलग प्राक्कलन प्रस्तुत किये हैं। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि इस वर्ष 950 लाख टन फसल के होने को सम्भावना है, शायद वित्त मंत्री का आशावादिता इस वर्ष की अच्छी फसल पर आधारित है और शायद वित्त मंत्री 290 करोड़ रुपये के घाटे को इस अच्छी फसल से समाप्त करने की आशा लगाये हैं, परन्तु देखने की बात तो यह है कि इस वर्ष की अच्छी फसल कितने प्रतिशत सरकार के प्रयासों तथा कितने प्रतिशत प्रकृति की सहायता के फलस्वरूप सम्भव हुई है। अभी भी हम कृषि के लिये वर्षा पर निर्भर हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण मध्यान्ह भोजन के पश्चात् जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the clock.

लोक सभा भोजन के मध्याह्न पश्चात् दो बज कर चार मिनट पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Four minutes past Fourteen of the clock.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(Mr Deputy Speaker in the Chair.)

श्री हेम बरूआ : गत बीस वर्षों से कृषि की उपेक्षा की जा रही है । यही कारण है कि कृषि के लिए हम आज भी वर्षा पर निर्भर करते हैं, सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ प्रयास करने चाहिये जिससे कि हम कृषि के लिए वर्षा पर निर्भर न रहें। इस समय हमारी विदेशी मुद्रा की आय का 70–75 प्रतिशत भाग कृषि का ही होता है । अतः अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए भी हमें कृषि में सुधार करना चाहिये ।

वित्त मंत्री ने निर्मित वस्तुओं पर कर लगाकर अच्छा कार्य नहीं किया है । पटसन से बनी वस्तुओं को पहले ही पड़ोसी देशों से प्रतियोगिता करनी पड़ रही है, कर लगाने से इन वस्तुओं के निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा । बजट प्रस्तावों में निर्यात व्यापार बढ़ाने का कोई संकेत नहीं मिलता है ।

खाद्यान्नों का फालतू भन्डार बनाने का निर्णय किया गया है विशेषकर पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आयात कर ऐसा करने का निर्णय किया है। वित्त मंत्री के बजट भाषण से खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के बारे में कोई संकेत नहीं मिलता है। मेरा निवेदन है कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों के आयात को जितनी जल्दी बन्द कर दिया जाये उतना ही देश के लिए अच्छा है ।

वित्त मंत्री ने कहा है कि प्रति रक्षा व्यय बढ़ गया है। मेरे विचार में यह ठीक ही हुआ है, परन्तु मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान प्रतिरक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की ओर दिलाना चाहता हूं । लोक लेखा समिति ने भ्रष्टाचार के कई मामलों का उल्लेख किया है । मोटर टायरों की खरीद में जो घोटाला हुआ था, उसको सभी जानते हैं । अतः भ्रष्टाचार को पूर्णतया समाप्त किया जाना चाहिये । जहाँ तक सीमावर्ती सड़कों के निर्माण का प्रश्न है इनको अवश्य बनाया जाना चाहिये । वित्त मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

कर लगाने की अपेक्षा सरकार को बकाया करों की राशि को वसूल करने पर अधिक ध्यान देना चहिये । अभी कल ही बताया गया है कि 541.70 करोड़ रुपये की राशि वसूल करनी शेष है, भारतीय व्यापार संस्थाओं के साथ-साथ अब विदेशी व्यापार फर्में भी कर अपवंचन करने लगी हैं। केवल बर्माशेल की ओर 285.40 लाख रुपये की आयकर राशि शेष है, प्रो० कालडोर के अनुमान के अनुसार भारत में 200 करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष करावंचन होता है, जहां तक कि राजकपूर जैसे चलचित्र कलाकार की ओर भी आयकर की राशि बकाया है । अतः मेरा निवेदन है कि कर वसूल करने की व्यवस्था को कठोर बनाया जाये ।

डाक दरों में विशेषकर पुस्तकों के पैकटों में, वृद्धि करने से पुस्तक व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । पुस्तकों की अपेक्षा अधिकांश दुकानें शहरी क्षेत्रों में हैं अतः देहाती लोगों को पुस्तकें मंगाने पर अधिक डाक दर देनी पड़ेगी ।

सरकारी व्यय में मितव्ययिता की जानी चाहिये परन्तु बजट भाषण में इस सम्बन्ध में कोई संकेत नहीं मिलता । प्रशासनिक व्यय प्रतिवर्ष बढ़ता ही जा रहा है। 1664–65 में सिविल प्रशासन पर 107 करोड़ रुपये व्यय किये जाते थे जबकि अब यह व्यय बढ़कर 186 करोड़ रुपये हो गया है । इससे भी मुद्रास्फीति होती है, मुद्रास्फीति से अनेक भयंकर परिणाम सामने आते हैं !

वित्त मंत्री ने विदेशी शराब पर कर लगाया है, इससे तस्करी बढ़ेगी। मद्य-निषेध से सरकार को प्रति वर्ष 300 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। अनेक राज्य सरकारें मद्य निषेध की नीति में ढील दे रही हैं, अतः वित्त मंत्री मद्य निषेध लागू करने के अपने उद्देश्य में असफल रहेंगे।

श्री को० सूर्यनारायण (एल्लूरू) : बजट की मांगों का समर्थन करते हुए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वे कृषि के विकास के लिए विशेष कर आंध्र प्रदेश में अधिक धन की व्यवस्था करे। आंध्र प्रदेश सरकार ने कृषि के विकास के लिए अनेक प्रस्ताव भेजे हैं। जब कभी मुख्य मंत्री इस बारे में केन्द्रीय सरकार से बातचीत करते हैं तो उनको कह दिया जाता है कि वह इन प्रस्तावों को अपनी योजनाओं के अन्तर्गत ही रखें। मेरा निवेदन है कि आंध्र प्रदेश के साधन बहुत सीमित हैं। आंध्र प्रदेश में अनाज पहले ही फालतू है परन्तु यदि वहां पर कृषि विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है तो यह फालतू अनाज समूचे देश विशेषकर दक्षिण भारत के काम आ सकेगा। अतः राज्य सरकार ने 12.50 करोड़ रुपये की लागत वाली छोटी सिंचाई कार्य की एक योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने हेतु भारत सरकार को भेजी थी। परन्तु यह योजना स्वीकार नहीं की गई है, राज्य सरकार नागार्जुन सागर परियोजना में पहले ही 130 लाख रुपये लगा चुकी है, परन्तु केन्द्रीय सरकार इस परियोजना की पूर्ति के लिए योजना अनुसार धन नहीं दे रही है।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि नदी जल के वितरण के बारे में अन्तर्राज्यीय विवाद चल रहा है। यह एक तकनीकी मामला है। कई प्लान दिये जा चुके हैं, परन्तु केन्द्रीय सरकार इस मामले में चुप है। इसके कारण आंध्र प्रदेश, मैसूर तथा महाराष्ट्र राज्य एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। ऐसे मामलों को गोलमेज सम्मेलन में सुलझाया जाना चाहिये। अतः इस मामले को सम्बन्धित राज्यों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिये विशेषकर ऐसे समय जबकि हम प्रतिवर्ष 1000 करोड़ की विदेशी मुद्रा खाद्यान्नों के आयात पर व्यय कर रहे हैं।

आंध्र प्रदेश की कई लाख टन अनाज अन्य राज्यों को प्रतिवर्ष देता है तथापि इसके कुछ क्षेत्रों में सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं है। जिन क्षेत्रों में नहर का पानी आता है वहां भूमि का मूल्य अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कई गुना है, राज्य सरकार ने इन स्थानों पर भी सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार की सहायता मांगी है। केन्द्रीय सहायता में वृद्धि की अपेक्षा प्रति वर्ष कमी होती जा रही है। चालू वर्ष में आंध्र प्रदेश को केवल 57.50 करोड़ की सहायता दी गई है जबकि 1965–66 में 65 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई थी।

बिहार सरकार के पास बिजली से चलने वाले अनेक मिल बेकार पड़े हैं। आंध्र प्रदेश सरकार इनको क्रय करने को भी तैयार है परन्तु इस मामले में अभी तक कुछ नहीं किया गया।

बाढ़ नियन्त्रण योजना के बारे में भारत सरकार के विशेषज्ञों ने अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, इसके लिए लगभग 10.65 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। परन्तु केन्द्रीय

(श्री कों० सूर्यनारायण)

सरकार इसके लिए भी धन नहीं दे रही है, यदि केन्द्रीय सरकार इन सभी परियोजनाओं को पूरा करने में वित्तीय सहायता दे तो आंध्र प्रदेश समूचे देश को भारी मात्रा में अनाज सप्लाई कर सकता है।

Shri Rabi Ray (Puri): It was expected that the hopes and aspirations of the crores of people of India will be reflected in the budget. But looking at the proposals made in the budget it appears that it will enhance the hardships of the people. It is not a budget of the common men. I would say that it is a budget of the vested interests. It becomes clear from the welcome accorded to it in the business circles. Big business men have been given some relief and concessions whereas poor people have been further taxed. Budget does not provide any solution to the various maladies afflicting our country. This budget is also without any direction and principle till the previous ones.

The Government has not taken note of the problems of the poorman because it is being run by the bureaucrats. Only few have been benefited in the last twenty years planning. Now there is a plan-holiday. During all these years we have ignored our basic industry that is agriculture. That neglection has made us dependent on the other countries for import of foodgrains. It also results in drainage of valuable foreign exchange.

The mostimportant question facing the country is how to become self-sufficient in foodgrains. For achieving this objective we have to give adequate facilities of irrigation to the farmers. In this connection I would also say that even after twenty years of independence we are still dependent on moonsoons. Nothing has been done to give incentive to the farmers. Most of the cultivated area lacks irrigation facilities. I would suggest that we should have 7 year irrigation plan which may cover the entire country. In this connection I would also like to mention that Israeli expert gave their expert advice to Late Pt. Nehru in regard to the later development of owr agriculture. The recommendations of those experts have not seen the light of the day. It is believed that they suggested minor irrigation schemes instead of big projects.

So far as the question of implementing the wide irrigation programme is concerned, it will not be difficult for the Government to raise the necessary resources. There is no dearth of resources but Government will have to take determined and radical steps in that direction. No family, whosoever it may be, allowed to spend more than 1500 rupees per month. It will result in the saving of 1000 crores. This money can be ulilized for the development of agriculture and industry.

An eminent swedish economist has stated in his book published recently that economic and social revolution in India has been averted. He has further stated that even the political revolution has became less of reality. The importance of eliminating corruption from public life has been emphasized. He has further emphasized the need of taking radical steps to rehabilitate the economy of the country.

It is clear from the reports of Mahalanobies Committee, Monopolies Inquiry Commission and Hazari Committee that entire wealth of the country has accumulated in the hands of few. Even after the receipt of the Hazari report Government is issuing licences to the Birlas. There seems to be conspiracy between the big business men, bureaucrats and ministers. The hon. Finance Minister has not given any indication in the Budget to break this unholy alliance.

So far as Socialism is concerned, it is a mere slogan with the Congress Government. The Government has failed to take any decision in regard to the abolition of Privy purses of

the ex-princes who have lot of wealth and property. These privy purses Cost Rs. 5 crores to the National exchequer. These purses must be abolished.

The gap between the poor and the rich is widening day by day. Nothing has been done to bridge this gap. Equality does not prevail between one citizen and the other. The public Schools should be abolished as they create class distinction. There should be only one class in the railway. Air-condition and first class should be abolished.

I conclude with the words that solution of the various ills of the country lies in removing the Congress from power.

श्री पी० राम मूर्ति (मदुरै) : देश के बड़े व्यापार-गृहों में बजट का स्वागत किया गया है। परन्तु मैं कुछ तथ्यों का उल्लेख करना चाहता हूं। वर्तमान बजट से बेरोजगारी बढ़ेगी और लोगों की स्थिति और खराब होगी। सरकारी क्षेत्र में कोई नया उद्योग लगाने की व्यवस्था नहीं है। इस वचन के बावजूद कि चौथी पंच वर्षीय योजना 1969 में आरम्भ की जायेगी कोई नहीं जानता कि वास्तव में यह कब शुरू होगी।

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में सभी वर्गों से आत्म-त्याग, सहयोग तथा अनुशासन की अपील की है। प्रश्न यह उत्पन्न होते हैं कि देश के बड़े बड़े व्यापारी लोग क्या आत्म-त्याग करते हैं। जहां तक जनसाधारण का सम्बन्ध है आत्म-त्याग का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। वित्त मंत्री ने जनसाधारण को रोजगार के अवसरों से भी वंचित रखा है। रेलवे से हजारों व्यक्तियों को नौकरी से निकाल दिया गया है।

वर्तमान बजट से स्वतंत्र दल और कांग्रेस दल को विभाजित करने वाली रेखा समाप्त हो गई है। स्वतंत्र दल का विश्वास है कि जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है देश भक्ति की भावना लम्बी अवधि तक अपना काम नहीं कर सकती। अतः वह व्यक्तिगत लाभ के पक्ष में है। उनका यह भी विचार है कि देशभक्ति की भावना को कुछ अवसरों पर ही प्रयोग किया जा सकता है। इस बजट के इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया है। बड़े-बड़े व्यापारियों को अनेक रियायतें दी गई हैं। लाभांश-कर समाप्त कर दिया गया है। उद्योगपतियों पर लगाये गये अधिकर को 35 से 25 प्रतिशत कर दिया गया है, यह सब कुछ उत्पादन बढ़ाने के नाम पर किया जा रहा है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन 20 वर्षों के दौरान हमारी सरकार बड़े-बड़े उद्योग-पतियों को सब प्रकार के प्रोत्साहन देती रही है। इसका परिणाम यह निकला है कि आज देश की अर्थव्यवस्था पर उनका पूरा नियंत्रण हो गया है। श्री देसाई ने यह स्वीकार किया था कि पिछले कुछ वर्षों में घाटे की अर्थव्यवस्था ही मुद्रास्फीति के लिये उत्तरदायी है। उन्होंने यह वचन दिया था कि भविष्य में घाटे का बजट नहीं बनाया जायेगा। फिर भी वित्त मंत्री ने अपना वचन पूरा न करके 300 करोड़ रुपये का घाटे का बजट प्रस्तुत किया है। विदेशी सहायता का उपयोग न कर सकने के कारण 109 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। इससे यह पता चलता है कि बजट बनाने में भी हमारी सरकार दूसरे देशों पर निर्भर करती है। सम्पूर्ण योजना के लिये विदेशों से धन जुटाया जाता है। परन्तु यदि विदेश सहायता बन्द हो जाये तो क्या स्थिति होगी ? विदेश सहायता का उपयोग औद्योगिक विकास के लिये ही नहीं अपितु बजट बनाने के लिये भी

[श्री पी० राम मूर्ति]

किया गया है। हम यह कहते हैं कि निर्यात बढ़ाने के लिये हमें विदेश सहायता की आवश्यकता है। सरकार ने इन 20 वर्षों के अनुभव से कुछ नहीं सीखा है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार सम्मेलन पिछले डेढ़ महीने से चल रहा है। इस सम्मेलन के कागजात से पता चला है कि इन 20 वर्षों में कम विकसित देशों को जितनी सहायता दी गयी है वह उस धन-राशि से बहुत कम है जो साम्राज्यवादी देशों ने उनसे प्राप्त की है। आंकड़ों से स्पष्ट पता चलता है कि कम विकसित देशों को दी जाने वाली सहायता की शर्तें उनके हितों के विरुद्ध जाती हैं। यह देखा गया है कि पिछले 15 वर्षों में इन साम्राज्यवादी देशों ने कम विकसित देशों से काफी धन प्राप्त किया है।

अवमूल्यन के बाद भी हमारी सरकार ने कुछ नहीं सीखा। हमारे देश तथा ब्रिटेन और अमरीका के बीच सम्बन्ध वैसा ही है जैसे गांव के एक गरीब व्यक्ति और महाजन के बीच होता है। यह एक नवीन प्रकार का उपनिवेशवाद है। बड़े-बड़े उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देना और विदेशी हितों को संतुष्ट करना ही हमारी सरकार का उद्देश्य है। यही उनकी मूल नीति है।

निर्यात को बढ़ाने के प्रयोजन से लगभग 100 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन दिये गये हैं। परन्तु इसके बावजूद निर्यात में कोई वृद्धि नहीं हुई। जिसका परिणाम यह है कि जनता की मेहनत की कमाई का दुरुपयोग किया जा रहा है। व्यक्तिगत लाभ की कोई सीमा तो निर्धारित की जानी चाहिये। श्री मोरारजी ने अपने बजट सम्बन्धी भाषण में कहा था कि वह कठोर कार्यवाही कर रहे हैं ताकि छिपाया हुआ धन जमा न हो सके। उन्होंने आगे कहा था कि उन लोगों को कड़ी सज़ा दी जायेगी जो अपनी आय या अपने धन को छिपा कर करों से बचना चाहते हैं। परन्तु यदि ऐसे लोग पकड़े जायेंगे तो उन्हें 100 रुपया जुर्माना हो जायेगा। हमारे विचार में जुर्माने के स्थान पर ऐसे व्यक्तियों को एक या दो वर्ष के लिये जेल में बन्द करना चाहिये। परन्तु ऐसे कई उदाहरण दिये जा सकते हैं कि जब जनसाधारण को बलिदान करने लिये कहा जाता है।

यदि मूल्यों में वृद्धि होती है और कर्मचारियों को अधिक महंगाई भत्ता देना पड़ता है तो उससे राज्यों पर बोझ पड़ेगा। क्योंकि वित्त मंत्री कहते हैं कि यह राज्य सरकार का कार्य है और राज्य सरकार को किसी भी कीमत पर कानून और व्यवस्था बनाये रखनी चाहिये। श्री देसाई ने समय से पहले ही वित्त आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। जब तक देश की अर्थव्यवस्था की बागडोर केन्द्रीय सरकार के हाथों में रहेगी तब तक देश की समस्याएं बनी रहेंगी चाहे किसी भी आयोग को स्थापित क्यों न किया जाये। यदि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के साथ अच्छे सम्बन्ध चाहती है तो राज्यों की शक्तियों की ठीक ढंग से परिभाषा की जानी चाहिये। राज्यों में कानून और व्यवस्था कायम करने का सम्बन्ध जनता के आर्थिक जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। यदि राज्य सरकारों को कानून और व्यवस्था की समस्या के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से निपटना है तो देश की अर्थव्यवस्था की दिशा निर्धारित करने के कार्य में राज्यों का अधिक हिस्सा होना चाहिये।

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : देश का बजट सभी वर्षों के लिये एक जैसा नहीं हो सकता यह देश की आर्थिक नीति का एक अत्यन्त लचीला उपकरण है। बजट का संतुलित या घाटे का होना देश की आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। पिछले तीन वर्षों में हमारे देश को बहुत गम्भीर आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ा है। इस अवधि में आर्थिक मंदी, बेरोजगारी में वृद्धि तथा मूल्यों में भी वृद्धि हुई है। हमारे निर्यातों में भी अन्तर बढ़ गया है। इसलिये हमारी अर्थ-व्यवस्था की स्थिति ऐसी बन गयी है कि अपनी सीमाओं के अन्दर रह कर अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिये कोई ठोस कार्यवाही करना बहुत आवश्यक हो गया है।

मेरे विचार में इस बजट को व्यावहारिक दृष्टि से देखना चाहिये। हमारे देश की आर्थिक स्थिति उस अवस्था में पहुंच गई है कि उस से निकलना परमावश्यक है। यदि हम चालू वर्ष में भी आगे नहीं बढ़े और इस मंदी पर काबू नहीं पा सके तो देश की आर्थिक अवस्था इतनी अधिक गम्भीर हो जायेगी कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।

हमें बजट पर इस दृष्टि से विचार करना चाहिये कि क्या इससे हमारी आर्थिक अवस्था में कुछ सुधार होता है या नहीं। इसी बात को ध्यान में रख कर वित्त मंत्री ने अपनी इच्छा के विरुद्ध घाटे का बजट प्रस्तुत किया है। वर्ष 1968-69 में किसी प्रकार से खर्च में वृद्धि करने के विचार से घाटे की अर्थव्यवस्था नहीं की गई है। वर्ष 1967-68 और 1968–69 का खर्च लगभग समान है। यदि घाटे की अर्थव्यवस्था न की जाती तो एक-दो सप्ताह में वित्त मंत्री 290 करोड़ रुपये की कटौती करते जिसके परिणाम कल्पनातीत होते। एक ओर हम कहते हैं कि घाटे की अर्थव्यवस्था नहीं की जानी चाहिये परन्तु दूसरी ओर हम चाहते हैं कि खेतिहरों पर कोई कर न लगाया जाये, बल्कि उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। हम भी यह चाहते हैं कि खेतिहरों को हर प्रकार की सुविधाएं दी जायें। हम चाहते हैं कि हम अनाज के सम्बन्ध में केवल आत्मनिर्भर ही न हों बल्कि हम अनाज का निर्यात भी कर सकें। इस समय यदि घाटे की अर्थव्यवस्था नहीं की जाती तो कृषि मूल्यों में भारी कमी हो जाती।

[श्री गु० सिं० ढिल्लों पीठासीन हुए
Shri G. S. Dhillon *in the Chair*]

इसलिये कृषि मूल्यों को गिरने से बचाने के लिये और बेरोज़गारी को बढ़ाने से रोकने के लिये घाटे की अर्थव्यवस्था करना अनिवार्य था। यदि घाटे की अर्थव्यवस्था नहीं की जाती तो निश्चय ही बेरोज़गारी बढ़ती जो वर्ष 1965-66 में लगभग स्थिर रही है। फिर पिछले दो वर्षों में जो भी अच्छे कार्य हुए हैं वह भी निरर्थक हो जाते।

हम घाटे की अर्थव्यवस्था के पक्ष में नहीं हैं परन्तु कुछ आर्थिक परिस्थितियों में संतुलित बजट की अपेक्षा घाटे की अर्थव्यवस्था अच्छी रहती है। हम यह जानते हैं कि मूल्यों की वृद्धि के कारण जनता बहुत दुखी है, परन्तु बहुत अच्छी फसल होने के कारण मूल्यों में वृद्धि का ख़तरा कुछ कम है। यदि हम पिछले तीन वर्षों में हुई मूल्य वृद्धि का विश्लेषण करें तो हमें पता चलेगा कि अनाज के मूल्यों में अधिक वृद्धि हुई है। परन्तु

[डा० वी० के० आर० वी० राव]

अच्छी फ़सल होने के कारण घाटे की अर्थव्यवस्था के फलस्वरूप मूल्यों में वृद्धि होने की कम सम्भावना है। आज से दो तीन वर्ष पहले जो वस्तुओं के मूल्य थे हम वहां तक नहीं पहुंच सकते परन्तु अब तो हमें यह सोचना है कि मूल्य की आगे वृद्धि न हो।

मुझे यह कहने में कोई हिचकचाहट नहीं कि हम इस देश में ग़ैर-सरकारी उद्यमों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं क्योंकि हम यह चाहते हैं कि नियोजन बढ़ता रहना चाहिये जिससे उत्पादन भी बढ़े। हमें आर्थिक गतिविधि और उत्पादन को बढ़ाना है, अन्यथा यह आर्थिक मंदी दूर नहीं हो सकती। ऐसा तभी हो सकता है यदि सरकारी क्षेत्र में परिव्यय बढ़ाया जाए, उत्पादन में वृद्धि की जाये और ग़ैर-सरकारी उद्यमों को प्रोत्सहन दिया जाये। जैसा कि मैं ने पहले बताया है, हम चाहते हैं कि आर्थिक गतिविधियों में संबन्धित रचनात्मक और विकास कार्यों में ग़ैर-सरकारी क्षेत्र को उपयुक्त अवसर मिले। इस प्रयोजन से वित्त मंत्री ने कई कदम उठाये हैं जैसे वार्षिकी जमा योजना को समाप्त करना, निगमित लाभ पर अतिकर में कमी, अधिक लाभांश कर को समाप्त करना आदि। अब हमारे पास आयतित फ़ालतू पुर्जे काफी मात्रा में उपलब्ध हैं और फिर अच्छी फसल होने के कारण कृषि सम्बन्धी कच्चा माल भी काफी उपलव्ध हो गया। इस से हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी और हमें आशा है कि अब ग़ैर-सरकारी क्षेत्र देहाती क्षेत्रों में अधिक वस्तुएं बेच सकेगा और उसमें जो बचत होगी वह उसे उद्योगों में लगा सकेगा। मेरे विचार में यह बजट ग़ैर-सरकारी उद्यमों के पक्षपातियों के लिये चुनौती है। मुझे आशा है कि वे इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और उससे हमारा उद्देश्य पूरा हो जायेगा। यदि ग़ैर-सरकारी क्षेत्र आलोचना करने के स्थान पर वित्त मंत्री द्वारा दी गयी रियायतों का लाभ उठायें, तो मुझे प्रसन्नता होगी। उन्हें नियोजन में वृद्धि करके उत्पादन बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करना चाहिये।

निर्यात को बढ़ाने के विचार से निर्यात शुल्कों में कमी कर दी गयी है और इस सम्बन्ध में कई प्रकार के प्रोत्साहन, सुविधाएं और कर सम्बन्धी रियायतें दी गयी हैं। ग़ैर-सरकारी उद्यमों के समर्थकों को इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिये और उपरोक्त हिदायतों से लाभ उठाना चाहिये। वित्त मंत्री ने सामान्य भविष्य निधि का प्रस्ताव प्रस्तुत कर के बड़ा साहसी कार्य किया है। सीमित आय वाले लोग इस योजना का लाभ उठा कर अपने लिये बचत कर सकेंगे। वित्त मंत्री ने ब्याज दरों में वृद्धि की है और हमें आशा है कि निजी बचतों से सरकारी साधनों में वृद्धि होगी। परन्तु यह सच है कि विकास सम्बन्धी व्यय के लिये संसाधन जुटाने के विचार से इस बार भारी कर लगाने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। सरकारी संसाधन जुटाने के लिये कराधान का महत्व बहुत अधिक है। आज कोई भी राजनीतिक दल कराधान का समर्थन करने के लिये तैयार नहीं है। आजकल कर धान के विरोध करने को देशभक्ति माना जाता है। यदि यही वातावरण बना रहा तो सरकारी संसाधन जुटाना कठिन हो जायेगा। हमें यह महसूस करना चाहिये कि विकास कार्यों के लिये सरकारी संसाधन जुटाना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिये हमें इस अस्वस्थ वातावरण को बदलना चाहिये।

हमें अधिक कर देने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसका उचित व्यय भी किया जाना चाहिये। खर्च में कमी कर्मचारियों की छंटनी करके पूरी नहीं की जानी चाहिये। (अन्तर्बाधाएं) हमें फिजूल खर्ची को रोकना चाहिये।

कर जांच आयोग ने व्यय आयोग स्थापित करने का सुझाव दिया था। उसका अभिप्रास कर्मचारियों की छंटनी करना न था परन्तु उसका अभिप्राय यह देखना था कि व्यय का किस प्रकार कम किया जाये (अन्तर्बाधाएं)

सरकारी क्षेत्र की कार्यकुशलता में वृद्धि बहुत आवश्यक है। जब तक सरकारी क्षेत्र देश के विकास में पूरा अंशदान प्रदान नहीं करेंगे तब तक देश में समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती।

सरकार प्रशासनिक आयोग द्वारा सरकारी क्षेत्रों के सम्बन्ध में दी गई सिफारिशों के सम्बन्ध में विचार कर रही है। इस सत्र के समाप्त होने से पूर्व सरकार का विचार सभा को सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सुधार के लिये किये जाने वाले उपायों से सूचित करने का है।

सरकारी क्षेत्र उद्यम केवल उचित संगठन से ही उन्नति नहीं कर सकते। उनमें उचित वातावरण की भी आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र उद्यमों को उचित रूप से कार्य करने के लिये समाजवाद मनोविज्ञान की आवश्यकता है।

यदि हम आर्थिक आयोजन की समस्या हल करना चाहते हैं तो अधिक निजी बचत जुटानी होगी। गैर-सरकारी और सरकारी वेतनों को विनियमित करना होगा। निर्धारित अवधि के लिये आय पर ऐच्छिक और अस्थायी सीमा भी लगानी पड़े। इस बीच हमें निजी बचत जुटाने के लिये भरसक प्रयास करना होगा। इसके लिये यह आवश्यक है कि हम देश में ऐसा आवश्यक वातावरण पैदा करें।

आज हमारे देश में बचत की दर 8 या 10 प्रतिशत है जब कि किसी विकासशील देश में यह दर 19 से 20 प्रतिशत होनी चाहिये।

सरकारी क्षेत्र की कार्यकुशलता बढ़ाना आवश्यक है। देश के विकास संसाधनों में सरकारी उद्यमों ने भारी योग दान न दिया तो देश में समाजवादी अर्थ-व्यवस्था नहीं लाई जा सकेगी।

यदि देश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार करना और उत्पादन में वृद्धि करनी है तो यह आवश्यक है कि देश में कानून और व्यवस्था बनी रहे। देश में होने वाले दंगे तथा हड़तालें, चाहे उनमें उचित मांग की गई हो अथवा नहीं, देश के लिये घातक हैं।

देश की आर्थिक व्यवस्था के लिये शान्ति का वातावरण आवश्यक है। हमें यह महसूस करना चाहिये कि देश की अर्थव्यवस्था हम सब से ऊपर है। देश का हित सब दलों से ऊपर है। अतः मैं सबसे अपील करूंगा कि आगामी वर्षों में हम देश में ऐसा वातावरण उत्पन्न करें कि देश में उत्पादन में बाधा न पड़े।

यह बजट गैर-सरकारी क्षेत्र और उन सभी के लिये चुनौती है जो सरकारी क्षेत्र में विश्वास रखते हैं। हमें बजट के उन अन्तिम परिणामों पर निर्भर रहना चाहिये जिनके आधार पर देश को वर्तमान कठिन स्थिति से निकालकर उन्नति और समाजवाद की ओर ले जाया जा सकता है।

श्री प्र० के० देव: वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में व्यक्त की गई आशा के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में निराशा व्याप्त है। इसका मुख्य कारण सरकार द्वारा अपने दल की सलाह न मानना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता ने सरकार की आंखें खोल दी हैं। चौथी योजन को स्थगित करना इस बात को महसूस करना है।

[श्री प्र० के० देव]

भारतीय अर्थ व्यवस्था की सबसे बड़े त्रुटि यह है कि 1955-56 से उत्पादन में 4 प्रतिशत वृद्धि हुई है जब कि मांग में 8 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यह अन्तर इतना अधिक है कि इस वर्ष इतनी अधिक अच्छी फसल होने के बावजूद भी मुझे याद है कि इसमें वृद्धि होने की सम्भावना नहीं है।

गत दो वर्षों में देश के विभिन्न भागों में सूखा और अकाल पड़े हैं। यद्यपि इस वर्ष फसल अच्छी होने की सम्भावना है तथापि हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि 1964-65 और 1967-68 में खाद्यान्नों के उत्पादन में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि जनसंख्या में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वस्तुओं के मूल्य बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 14 अक्तूबर, 1967 तक मूल्यांक 224 तक पहुंच गया था।

बजट में 290 करोड़ रुपया का घाटा दिखाया गया है जो वित्त मंत्री की इस नीति के विरुद्ध है जो उन्होंने गत वर्ष बजट प्रस्तुत करते समय निर्धारित की थी जिसके अनुसार घाटे की अर्थव्यवस्था नहीं होनी चहिये। इस घाटे के बजट का हमारी अर्थव्यवस्था पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा और कीमतें अवश्य बढ़ेगी।

हमारी अर्थव्यवस्था कृषि से सम्बन्धित है। हमारे देश में कृषि मुख्यतया वर्षा पर आधारित है। सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय की मांगों को देख कर काफी निराशा हुई है। इस मंत्रालय के लिये अधिक धन राशि निर्धारित की जानी चाहिये थी।

सिंचाई तथा विद्युत् की मांगों में काफी कमी हुई है। यदि किसानों को जल सम्भरण और सस्ती बिजली का आश्वासन दे दिया जाये तो वे अपने तकनीकी तरीके, अच्छे उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं, अधिक उपज देने वाले बीजों को अपनाने के इच्छुक हैं और वे कृषि में काफी धन लगाने के लिये तैयार हैं। उन्हें उनकी उपज का अधिक धन मिलना चाहिये और किन्हीं मामलों में सरकार से भी सहायता मिलनी चाहिये। उन्हें उर्वरक और कीटनाशक दवाएं उन दरों पर दी जानी चाहियें जिनमें सरकारी सहायता भी हो। भूमि लगान की पुरानी पद्धति को समाप्त किया जाना चाहिये।

बजट प्रस्तावों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि कुछ उपायों से हमारी अर्थ-व्यवस्था में किसी सीमा तक सुधार होता है और बाकी उपायों का हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। 500 रुपये तक के लाभांश-कर को समाप्त करने, कम्पनी के लाभों पर अतिभार की दर को कम करने, विकास की छूट में रियायत, वार्षिक जमा आदि समाप्त किये जाने आदि से मामूली मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा जब कि आयकर और सम्पत्ति कर की ऊंची दरों के कारण हमारी बचत और भी घट जायेगी और पूंजी निर्माण कम हो जायेगा। आयकर से छूट की सीमा को बढ़ाकर 7,500 रुपये कर देना चाहिये। इससे बहुत से लोगों को राहत मिलेगी।

वित्त मंत्री ने बहुत सी अत्यावश्यक वस्तुओं पर प्रत्यक्ष कर लगाया है। इनमें बल्ब, ट्रान्सिजटर आदि शामिल हैं। ये आवश्यक वस्तुएं हैं विलासिता की नहीं। इन पर कर नहीं लगाना चाहिये।

अनिर्मित तम्बाकू मजदूरों और निम्न श्रेणी के लोगों की प्रिय वस्तु है अतः इसके उत्पादन शुल्क में वृद्धि करना उचित नहीं ।

डाक तथा तार की दरों में वृद्धि करने के परिणामस्वरूप गरीब लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा । इसमें वृद्धि करने के लिये यह दलील दी जाती है कि डाक और तार विभाग की आमदनी में कमी हो गई है । परन्तु आश्चर्य की बात है कि यह कमी हर वर्ष दिखाई जाती है । डाक और तार की दरों में वृद्धि करने से पूर्व इस विभाग के खर्चे में कमी की जानी चाहिये ।

इन्जीनियरिंग उद्योग जो मंदी से पहले ही बहुत अधिक प्रभावी है उन पर उत्पादन शुल्क लगाना उचित नहीं है । यदि प्रशासनिक व्यय में कमी की जाये तो इस घाटे को कम किया जा सकता है ।

प्रतिरक्षा व्यय में 45 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है । यदि यह 45 करोड़ रुपये आधुनिक सैनिक सामान मंगाने पर खर्च किये गये होते जिससे हमारे सैन्य उपकरणों में वृद्धि होती तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं होती । सैनिक अधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई है जब कि हमारे 7,000 इंजीनियर बेरोजगार हैं ।

कोरापुट में एक इंजीनियरिंग कारखाने की स्थापना की गई है । उड़ीसा सरकार ने इसके लिये 3500 एकड़ भूमि कारखाने को दी है । उड़ीसा सरकार ने सिविल बिजली और सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरी का एक संगठन बना दिया जिसकी जिम्मेदारी एक चीफ इंजीनियर पर डाल दी गई है और वहां पर 300 इंजीनियरों को काम मिल गया है । इस संगठन ने बहुत बढ़िया काम किया है ।

सरकारी क्षेत्र का कार्य सन्तोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है । 1965-66 में सरकारी क्षेत्र के चालू संगठनों में पिछले वर्ष के 2.9 प्रतिशत लाभ की तुलना में 1.1 प्रतिशत का लाभ दिखाया गया है । राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की इस ह्रासोन्मख प्रवृत्ति के लिये सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का असफल संचालन भी दोषी है ।

बोकारो बहुत खर्चीली योजना है । उसके लिये की गई 110 करोड़ रुपये की व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिये ।

राज्यों को बैंकों से धन निकालते समय अच्छे वित्तीय अनुशासन का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये और जमा की गई राशि से अधिक धन नहीं निकालना चाहिये । मैं यह जोर देकर कह सकता हूं कि वर्तमान स्थिति के लिये केन्द्रीय सरकार की मुद्रा-स्फीति नीति उत्तरदायी है । केन्द्रीय सरकार की नीति के कारण ही मूल्य भी बढ़े हैं और आर्थिक मन्दी में भी वृद्धि हुई है । बहुत सी राज्य सरकारों ने बढ़े हुए मंहगाई भत्ते और ऊंची कीमतों को देखते हुए केन्द्र से अतिरिक्त बोझ उठाने का अनुरोध किया है ।

केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय तथा प्रशासनिक मामलों के सम्बन्ध में विचार किया जाना चाहिये । 1967 के आम चुनावों के बाद की बदलती हुई स्थिति को देखते

[श्री प्र० के० देव]

हुए संविधान में आवश्यक उपबन्ध करके संसाधनों के विभाजन सम्बन्धी प्रक्रिया में सुधार किया जाना चाहिये ।

योजना आयोग में तानाशाही का जोर है । परादीप परियोजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार को खर्च के लिये 16 करोड़ रुपये न दिये जाने में कोई औचित्य नहीं है । परियोजना को लाभ की स्थिति में पहुंचने से पूर्व ही सरकार ने इसका कार्य अपने हाथ में ले लिया है । भूतपूर्व सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से इसके लिये लिये गये 15.9 करोड़ रुपये के ऋण का भुगतान करने के लिये यह धन दिया जाना बहुत आवश्यक है । उड़ीसा से इस ऋण की ब्याज सहित अदायगी की मांग करना उचित नहीं । यदि ऐसा हुआ तो राज्य की सभी विकास योजनाएं स्थगित करनी होंगी ।

बजट द्वारा हमारी वर्तमान समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है और न ही इससे सामान्य जनता की स्थिति में सुधार ही हुआ है । वित्त मंत्री ने बजट द्वारा राष्ट्र को एक बहुत कड़वी गोली दी है ।

Shri Mudrika Singh (Aurangabad) : Agriculture is the true measure of Indian economy. This year we are expecting good crops. As a result of good crops this year, there is likely to be improvement in recession and the purchasing power of the peasants will improve. The Government has not paid the necessary attention towards agriculture.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(**Mr. Speaker** *in the Chair*)

Improvement in agriculture is necessary for the development of the country. Without improvement in agriculture, there can be no improvement in the commercial and industrial sphere. Although the position of food has improved a lot this year, still the agriculturists are in debt.

In order to improve the agricultural production in the country we will have to give some incentive to the agriculturists. We should also provide some facilities to them.

We should make necessary improvement in irrigation, seeds etc. for increasing agriculture output. Government should provide them as much assistance as possible. We cannot depend upon P.L. 480 for ever.

Deficit financing in a developing country is not a strange thing. If it is done for the development of the country, we have no objection. We should invest the money for increasing production. While going to deficit finance we should also try to take all steps to improve recession and to recover the tax arrears. Efforts have not been made for increasing income.

If we really want to increase income, banks should be nationalized. In that case our national income will increase and the question of licence will also be solved.

Public Sector undertakings should also run in profit.

श्री मनोहरन (मद्रास : उत्तर) : यह कहना गलत नहीं है कि भारत सरकार द्वारा रुपये का अवमूल्यन किये जाने के परिणामस्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ गई है । खरीफ की फसल अच्छी हो जाने पर भी दो वर्षों की सूखे की स्थिति और औद्योगिक मंदी की स्थिति के दुष्प्रभाव को दूर करना सम्भव नहीं है ।

1966–67 के कृषि उत्पादन में पहले वर्ष की तुलना में बहुत कम वृद्धि हुई है और उत्पादन के मामले में 1964–65 के स्तर तक नहीं पहुंच सके हैं । 1967–68 के 9 करोड़ 30 लाख टन के अनुमानित उत्पादन से न तो कोई बड़ी राहत ही मिलेगी और न ही अनाज का आयात कम होगा । इस बीच बढ़ती हुई जनसंख्या नगरीकरण और आय बढ़ने के परिणामस्वरूप अनाज की मांग बढ़ती जा रही है ।

वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये आर्थिक सर्वेक्षण में यह बात मानी गई है कि खाद्यान्न की मांग आगे के वर्षों में बढ़ती ही जायेगी । यदि यह स्वीकार कर लिया जाय कि खाद्यान्न का उत्पादन इस वर्ष 930 लाख टन होगा तो इसका श्रेय उद्योगों तथा राज्य सरकारों को ह जाता है । आज आवश्यकता इस बात की है कि केंद्र राज्य सरकारों को अधिक वित्तीय अधिकार दे । मद्रास के राज्यपाल ने अपने इस वर्ष के अभिभाषण में इस सम्बन्ध में जोर डाला है । उन्होंने कहा है कि राज्य सरकारों के पास पर्याप्त साधन नहीं हैं । मद्रास के राज्यपाल ने कहा की जनता के विचारों को ठीक रूप में रखा है ।

गत वर्ष जो औद्योगिक मंदी आई उसका कारण भी कृषि में कमी होना था । इस समय जो मंदी है उसने दो मुख्य बिन्दु कपड़ा उद्योग तथा इंजिनियरिंग और पूंजीगत सामान है । हम ने यह भी देखा है कि आयात के लायसेंसों का पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया ।

इस मंदी का एक और कारण मुद्रास्फीति है । सरकार ने 3000 करोड़ रू० के नोट छाप दिये हैं और 1967–68 में 300 करोड़ रु० के और नोट छापे हैं । वित्त मंत्री ने इस सदन में कई बार आश्वासन दिया था कि घाटे का बजट तैयार नहीं करेंगे परन्तु अब फिर कहते हैं कि इसके बिना गुजारा नहीं है ।

हमारी ऋण देने की तीन संस्थायें अर्थात् रिज़र्व बैंक, स्टेट बैंक तथा अन्य संस्थायें अपने कार्य में असफल रही हैं और तकनीकी परामर्श नहीं दे सकीं । हमारे ऊपर विदेशी ऋण बढ़ता ही जा रहा है ।

निर्यात के क्षेत्र में हम प्रतियोगिता करने में असमर्थ होते जा रहे हैं । इस कारण मैं सरकार से इस देश की गरीब जनता की ओर से कहूंगा कि वह गलत नीतियों को लागू कर के जनता की कमर न तोड़े ।

प्रतिरक्षा का व्यय 1000 करोड़ रुपया से अधिक हो गया है । केन्द्रीय सरकार का विकासेत्तर व्यय कम होना चाहिये । एक सचिवों की समिति इस संदर्भ में स्थापित की जाये जो व्यय को कम करे ।

मिठाइयों पर तथा डाक के करों को आधा किया जाये । चीनी पर पहले ही उत्पादन शुल्क बहुत है और उसका प्रभाव पहले ही मिठाईयों पर पड़ रहा ।

सरकार से बहुत सी संस्थायें अनुदान प्राप्त कर रही हैं । उन में बम्बई की फिल्म सोसायटी तथा भारत सेवक समाज जैसी बदनाम संस्थायें भी हैं । इस सूची में कमी की जानी चाहिये ।

[श्री मनोहरन]

मंत्रिमंडलों में मंत्रियों की संख्या में कमी की जानी चाहिये। आज कांग्रेस के 280 सदस्य यहां हैं उनमें से लगभग 60 मंत्री हैं। प्रतिरक्षा मंत्री के आदेशानुसार मद्रास से फिज़ियोलोजी की संस्था को स्थानांतरित किया जा रहा है। ऐसा करना ठीक नहीं है।

भाषा के बारे में सरकार का रवैया ठीक नहीं है। सरकार ने गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के साथ जो वचन किये थे उनका पालन नहीं किया जा रहा है। इस बात की पुष्टि अब केरल के मुख्य मंत्री ने भी कर दी है जो कि पहले हिन्दी के बहुत विरोधी नहीं।

मुझे दुःख से कहना पड़ता है कि डा० सेठ गोविन्द दास ने यह कहा है कि मद्रास में सेना को भेजना चाहिये जब यह भाषा पर झगड़ा करें। अब वह कह रहे हैं कि हिन्दी भाषी राज्यों में उपकुलपतियों का घेराव किया जाये यदि वह अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देना बन्द नहीं करते हैं।

हमारे द्र० मु० क० दल ने अलगाव की नीति को छोड़ दिया है। परन्तु आप अलगाव के बीज मत बोइये। इसलिये सेठ गोविन्द दास की सेना से प्रयोग करने की बात ठीक नहीं हैं

आज बम्बई में मद्रास में निर्मित फिल्मों का बहिष्कार किया जा रहा है। यह ठीक नहीं है।

मैं सारे दक्षिण की ओर से कहना चाहता हूं कि हमारा विश्वास देश की एकता में है।

श्री रा० कु० सिंह (फैज़ाबाद) : मुझसे पहले के सदस्य ने कहा है कि वह सारे दक्षिण की ओर से बोल रहे हैं।

मद्रास के लोग उस समय चिल्लाते हैं जब उन के आर्थिक मामलों पर आघात होता है जैसा कि बम्बई में हुए उन फिल्मों के विरुद्ध आन्दोलन से ज़ाहिर है जो मद्रास में निर्मित की गई हैं।

अभी तो यह भी पता नहीं कि द्र० मु० क० दल की नीति क्या है। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को जलाया है तथा रेलवे की सम्पत्ति को आग लगाई है। क्या वह राष्ट्रीय सम्पत्ति नहीं है ?

भारतीय जनसंघ का ही कार्य था कि साम्प्रदायिक दंगे कराये। साम्यवादी नेता प्रो० ही० ना० मुकर्जी ने कहा कि नया फाशिज़म फैल रहा है परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि उसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

स्वतंत्र दल वाले जब साधारण जनता की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि पूंजीपतियों के हितों का ध्यान रखें।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा तैयार किये गये दस सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाना चाहिये। हमें अपने साधनों का पूरा उपयोग करना चाहिये जिससे हमें अमरीका और रूस पर निर्भर न रहना पड़े।

देश में युवकों में बेरोजगारी के फलस्वरूप जो निराशा फैल रही है उसका कारण यह है कि हम अपने युवकों को उपयुक्त शिक्षा नहीं दे रहे हैं। विद्यार्थियों द्वारा किये जा रहे आन्दोलनों का गैर-जिम्मेवार राजनीतिज्ञ अनुचित लाभ उठा रहे हैं। उनको साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों से बचाया जाना चाहिये जिससे वे अपने देश की सम्पत्ति को नष्ट न करें और अपने देश के भविष्य को अंधकारमय न बनायें। देश के प्रति उनकी क्या जिम्मेवारियां हैं उनका उन्हें अहसास कराया जाना चाहिये जिससे वे अपने देश की सुरक्षा और इसके भविष्य की रक्षा कर सकें। देश में युवकों का मार्गदर्शन करने तथा उन्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए योजनायें बनाई जानी चाहियें और इसके लिए आयव्ययक में अधिक व्यवस्था की जानी चाहिये।

डाक तथा तार विभाग और रेलवे विभाग में कार्य और अधिक अच्छी तरह हो, इसके लिए कोई व्यवस्था की जानी चाहिये। कभी-कभी हमें एक टेलीफोन करने के लिए घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसी प्रकार लोगों को रेलवे माल विभाग की बजाये गैर-सरकारी माल-वाहकों का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि रेलवे की सेवा अच्छी नहीं है। इन दो विभागों के खर्च को कम करने के लिए जांच-पड़ताल की जानी चाहिये। हमें सभी साधनों का उपयोग करना चाहिये। पोस्ट-कार्डों तथा लिफाफों की कीमतों को काफी नीचे लाया जाना चाहिये। बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण से सफलता न मिलने की सूरत में इनका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। निजी थैलियों को भी यथासम्भव शीघ्र समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

श्री सेक्वीरा (गोआ, दमन तथा दीव): आयव्ययक में कृषि, सिंचाई और ग्रामीण कार्यक्रमों की उपेक्षा करके ऐसी परियोजनाओं पर ज़ोर दिया गया है जिनमें उत्पादन आरम्भ होने में अधिक समय लगेगा। उदाहरणार्थ पिछले वर्ष की तुलना में कृषि के लिए राज्य सरकारों को दिये जाने वाले ऋणों की राशि में एक करोड़ रुपये की, छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए निधि में 3 करोड़ रुपये की मिट्टी संरक्षण के लिए निधि में $1\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की, वन योजनाओं के लिए निधि में लगभग $\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की, मछली-पालन योजनाओं के लिए निधि में एक करोड़ रुपये की, ग्रामीण जनशक्ति का उपयोग करने सम्बन्धी योजनाओं के लिए निधि में लगभग एक करोड़ रुपये की और सिंचाई तथा विद्युत् परियोजनाओं के लिए निधि में 4 करोड़ रुपये की कमी की गई है जबकि लोक-निर्माण-कार्य विभाग के भवनों के लिए निधि में और सरकारी कम्पनियों और कारपोरेशनों में लगाने के लिए निधि में क्रमशः 64 लाख रुपये और 32 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। कृषि में सुधार और अनुसन्धान करने पर चालू वर्ष में नियत की गई धनराशि की वास्तव में केवल 20 प्रतिशत धनराशि ही खर्च की जायेगी। जबकि दिल्ली की पूंजीगत योजनाओं में इस वर्ष $2\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये अधिक लगाये जायेंगे। इन परिस्थितियों में यदि प्रकृति ने हमारा साथ न दिया और वर्षा अच्छी न हुई तो हमारी खाद्य समस्या और जटिल हो जायेगी। अतः हमें दीर्घ काल में पूरी होने वाली परियोजनाओं पर उतना ही खर्च करना चाहिये जितना कि हमने 1967 में किया था और सिंचाई और ग्रामीण योजनाओं पर

[श्री मेकर्जीरा]

अधिक बल दिया जाना चाहिये । यदि अगली बार अच्छी वर्षा हो जाती है जैसी कि हमें आशा है और इसके फलस्वरूप कीमतें गिरती चली जाती हैं तो कृषि-पुनर्वित्त के लिए कुछ अधिक और औद्योगिक ऋण संस्थाओं के लिए कुछ कम धनराशि नियत करना अच्छा रहेगा ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

समद्र द्वारा कलकत्ता से मद्रास को कोयले के परिवहन के लिए राजकीय सहायता की व्यवस्था की गई है। यदि रेलवे के पास अतिरिक्त क्षमता है तो यह कार्य रेलवे को ही सौंप दिया जाना चाहिये

नागालैंड विकास योजनाओं तथा सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास करने की योजनाओं के लिए निधि में क्रमशः 95 लाख रुपये तथा 41 लाख रुपये की कमी कर दी गई है। इस के विपरीत नक्सलबाड़ी तथा आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों पर और अधिक खर्च किया जाना चाहिये ।

आम लोगों के उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर उत्पादन-शुल्क को कम कर दिया जाना चाहिये । विलासिता की वस्तुओं पर अधिक कर लगाये जाने चाहिये । उपभोग की वस्तुओं पर करों से और बड़े-बड़े उपक्रमों को सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा अधिक धन उपलब्ध किये जाने से उद्यमियों को बड़े-बड़े उपक्रमों में थोड़ा सा धन लगा कर उन पर नियन्त्रण करने के लिये प्रोत्साहन मिला है । अतः इस नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिये ।

जहां तक निगमित करारोपण का सम्बन्ध है, इसकी सभी कम्पनियों के लिए समान दर होनी चाहिये । यह देशी कम्पनियों के लिये 50 प्रतिशत और विदेशी कम्पनियों के लिये 65 प्रतिशत होना चाहिये । निर्माण करने वाली कम्पनियों को होने वाले लाभ में से जितने धन का वितरण कर दिया जाता है उस पर 10 प्रतिशत अधिक कर लगाया जाना चाहिये और उसमें जितना धन पुनः लगा दिया जाता है उस पर 10 प्रतिशत कम कर लगाया जाना चाहिये । 50,000 रुपये की वार्षिक आय वाले छोटे अंशधारियों की क्षतिपूर्ति तथा छोटे अंशधारियों को प्रोत्साहन देने के लिये मेरा सुझाव यह है कि व्यक्तिगत कर में, जो वितरित आय पर 60 प्रतिशत कर पर आधारित है, लाभांश से प्राप्त होने वाली आय पर दिये गये निगम कर पर 40 प्रतिशत कमी की जानी चाहिये। मेरे विचार में इससे निगमित क्षेत्र की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती चली जायेगी और छोटे अंशधारियों के पास विनियोजन के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध होती रहेगी ।

यह धन पुनः निगमित क्षेत्र में लगे और इस क्षेत्र के स्वामित्व के रूप में परिवर्तन हो इसके लिए ये तीन कदम उठाना आवश्यक होगा : (एक) सरकारी वित्तीय संस्थाओं से उपलब्ध निधियों में कमी की जाये; (दो) रिजर्व बैंक द्वारा यह हिदायत दी जानी चाहिये जिस के अन्तर्गत अस्थियों को प्रतिशतता के रूप में ऋण के वर्तमान अनुपात को कम किया जाना चाहिये और थोड़े ऋण की तुलना में अधिक ऋण पर अधिक कर लगाया जाना

चाहिये, और (तीन) 50,000 रुपये अथवा 75,000 रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों द्वारा देय व्यक्तिगत कर में, पिछले वर्ष पब्लिक लिमिटेड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी में इन व्यक्तियों द्वारा साम्य अंशों में लगाई गई धनराशि के 20 अथवा 30 प्रतिशत के बराबर कटौती की जानी चाहिये परन्तु यह कटौती करारोपण योग्य आय के 10 प्रतिशत अथवा 3,000 रुपये, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होनी चाहिये।

सरकारी क्षेत्र का प्रबन्ध जिस सुचारु और व्यवस्थित ढंग से किया जाना चाहिये। उस तरह से नहीं हो रहा है। यह एक ऐसी बात है जिस पर सभी सहमत हैं। इन बड़े-बड़े उपक्रमों में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने की बजाय इनके लिए अलग-अलग पदाली बनाई जानी चाहिये। इस प्रकार बनाई गई पदालियों के अधिकारियों को उतना वेतन मिलना चाहिये जितना उन्हें गैर-सरकारी क्षेत्र में मिल सकता है। सरकार को सेवा से निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को ऐसे पदों पर नियुक्त करने के प्रश्न पर भी विचार करना चाहिये।

कुछ सरकारी उपक्रमों में जो लेखा निदेशक नियुक्त किये जाते हैं उन्हें लेखा-परीक्षा और लेखा सेवा में से लिया जाता है। होता यह है कि जो व्यक्ति लेखा-परीक्षा करने के लिए भेजा जाता है उसका सम्बन्ध भी उक्त सेवा से होता है और ऐसा होता है कि उक्त निदेशक का तबादला हो जाने पर उस लेखा-परीक्षक को उसके अधीन काम करना होता है। इसलिए लेखा-परीक्षा ठीक तरह से नहीं हो पाती है। इस समस्या को हल करने का एक तरीका यह है कि इनकी अलग-अलग पदाली होनी चाहिये। इसके अलावा लेखा-परीक्षक के के साथ एक तकनीकी सदस्य भी होना चाहिये।

Shri Tulsidas Jadhav (Baramati) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the budget is very good in the present circumstances. It is gratifying that it does not impose much burden on the common man.

It is the duty of each nation in the world to ensure that basic necessities of life *i.e.* food, clothing, housing, education and medical aid are provided to all its people. To achieve this end, Western countries like Britain, America, France, Italy have a capitalist economy whereas the communist countries like Russia, China, Hungary etc. have a socialist economy. We in India have adopted socialistic pattern of society and it is of fundamental importance that the abovementioned necessities of life are provided to all the people. The economy which assure these necessities is really a good one. We have a mixed economy and such a system is best suited to a democratic country like ours.

[श्री गु० सिं० ढिल्लों पीठासीन हुए]
[**Shri G. S. Dhillon** *in the Chair*]

Whereas a large sum of money has been invested in the basic industries, due attention has not been paid to agriculture. Our conflicts with China and Pakistan have adversely affected our economy. If proper attention had been paid to agriculture, we would have been in a better position to face these situations.

Administrative expenditure should be cut down in all the Ministries as has been done in the Ministry of Finance by abolishing certain posts.

In order to augment production and to attain self-sufficiency, it is necessary that more and more money should be invested in productive activities. While doing so, those

[Shri Tulsidas Jadhav]

projects of which might yield results within a period of two years, should be given preference over the projects of long gestation. Otherwise our poor people will have to suffer much more difficulties.

The Finance Minister has given tax relief in certain items with the aim that the money thus saved should be invested in the productive activities. In order to achieve this aim, it is necessary that all should co-operate with the Government in this matter.

There has been some decline in our traditional exports as more and more competitors have come up. But our trade with certain countries like U.S.S.R. and U. A. R. is developing. We should pay particular attention to these countries. At the same time the quality of commodities which are exported, should be maintained as there is general complaint that Indians are not trust-worthy in this respect. In order to build up a reputation in this sphere, it is of paramount importance that there should be strict enforcement of quality control.

Instead of going in for new industries, we must first use the idle capacity of the existing ones. A number of textile mills are closed. Sholapur spinning and Weaving Mill has been closed for the last four years. The Government should see that it is started again.

It is good that due attention has been paid to the agriculture. The concessions which have been given in respect of fertilizers and in other matters are welcome. The Government should see that there is no clash in the interests of agriculturists and consumers. While remunerative prices should be paid to agriculturists taking into account the cost of cultivation, the interests of the consumers should also be protected. The latter should get foodstuffs at reasonable prices even though the Government might have to provide them at subsidized rates.

It is true that the price of a postcard in India is the lowest in the world, but since it is used by common man, its price should not be increased too much.

To-day we find that the communalism has again raised its ugly head. There were language and communal riots at a number of places such as Bilaspur, Karimganj, Meerut etc. The Government should go to the root of the matter and remove the basic causes which led to these riots. All political parties should give serious thought to this problem. The elements responsible for them should be dealt with strictly.

The rate of our economic growth is slow and it should be accelerated.

श्री ग्ररुमुगरम (टेंकासी) : मैं सामान्य रूप से भ्रायव्ययक का स्वागत करता हूं। घाटे को पूरा करने के लिये डाक की वस्तुश्रों की दरों को बढ़ाने के प्रस्ताव किये गये हैं। पोस्टकार्डों के मूल्य में वृद्धि करने से ग्राम लोगों पर बोझ पड़ेगा। ग्रतः माननीय मंत्री को इस प्रश्न पर पुनः विचार करना चाहिये। इसके साथ-साथ चाकलेटों ग्रौर तम्बाकू पर उत्पादन-शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिये।

यह एक ग्रच्छी बात है कि त्रूतीकोरिन पत्तन परियोजना के लिये ग्रधिक धन की व्यवस्था की गई है। चौथी योजना ग्रवधि में तमिलनाड के लोगों की इस मांग पर भी विचार किया जाना चाहिये कि सलेम में एक इस्पात कारखाना स्थापित किया जाये।

भाषा नीति के सम्बन्ध में स्वर्गीय प्रधान मंत्री के आश्वासनों को पूरा करने के लिये संसद् के पिछले सत्र में एक संकल्प और राजकीय भाषा (संशोधन) विधेयक लाया गया था। यह हिन्दी भाषा-भाषी तथा गैर-हिन्दी भाषा-भाषी लोगों के बीच एक समझौता था। परन्तु उसमें जो बाद में संशोधन किये गये उनसे दक्षिण भारत के लोगों में भ्रम उत्पन्न हो गया है। कुछ नेताओं का जिनमें माननीय गृह-मंत्री भी शामिल हैं विचार है कि इससे गैर-हिन्दी भाषा-भाषी लोगों पर अधिक बोझ पड़ेगा जो कि उचित नहीं है। अतः जब तक इस असमानता को दूर नहीं किया जाता तब तक इस संकल्प की क्रियान्विति को रोक दिया जाना चाहिये।

कृषि क्षेत्र के लिये और अधिक धनराशि नियत की जानी चाहिये। मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई है कि हमारे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। यद्यपि हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आधारित है तथापि हमें खाद्यान्नों का आयात करना पड़ता है। यदि हम कृषकों को अधिक प्रोत्साहन देंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।

यद्यपि माननीय मंत्री इस बात पर भी सहमत हो गये हैं कि किसानों को अपने उत्पादों का अधिक लाभप्रद मूल्य मिलना चाहिये तथापि बाजार भाव और वसूली मूल्य में बहुत बड़ा अन्तर है और विशेषतया मद्रास राज्य में उसके पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा वसूली भाव कम निर्धारित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त अधिकारी गल्ला वसूली करते समय बल प्रयोग करते हैं और चाहे किसान का उत्पादन कितना ही कम हो उससे जबरन वसूली की जाती है। वसूली अधिकारी किसानों को सता रहे हैं। कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनमें वसूली की मात्रा किसान के वास्तविक उत्पादन से भी अधिक नियत की गई है।

वितरण के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि मद्रास की भूतपूर्व सरकार द्वारा सब ग्रामों में परिवार राशन कार्ड के माध्यम से चावल दिया जाता था, परन्तु अब वह प्रणाली खत्म कर दी गई है। इसलिये जो लोग ग्रामों में रहते हैं उन्हें मंहगे भाव पर चावल खरीदना पड़ता है। मद्रास की वर्तमान सरकार ने वचन दिया था कि एक रुपये का तीन सेर (मद्रास में प्रचलित बाट के अनुसार) चावल दिया जायेगा, परन्तु वह इसे पूरा करने में असफल रही है। उन्होंने एक रुपये का एक मद्रास के सेर के हिसाब से चावल देने की जो योजना आरम्भ की है वह भी मद्रास और कोयम्बटूर तक ही सीमित है तथा यह बड़े दुःख की बात है कि इसे राज्य के अन्य क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया है, हालांकि यह आश्वासन दिलाया गया था कि इस योजना को 15 जनवरी, 1968 से समस्त राज्य में लागू कर दिया जायेगा।

जहां तक रोजगार का प्रश्न है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। शिक्षित व्यक्तियों में भी बेरोजगारी बढ़ रही है। कुछ राज्यों में औद्योगिक विकास रुक गया है। मद्रास राज्य में भूतपूर्व सरकार के समय कुछ औद्योगिक विकास हुआ था जिससे अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए थे, परन्तु अब वर्तमान सरकार के अधीन औद्योगिक विकास बिल्कुल बन्द हो गया है। यदि यही स्थिति रही तो देश में अराजकता फैल जायेगी। मेरे जिले तिनुवेली में 8 उप-कलैक्टरों की पदावनति करके उन्हें तहसीलदार बना

[श्री अरुमुगम]

दिया गया है तथा तहसीलदारों की पदावनति करके उन्हें उप-तहसीलदार बना दिया गया है। राज्य भर में हजारों लिपिकों की छटनी की गई है। इसी प्रकार सैंकड़ों कनिष्ठ इंजीनियरों को भी नौकरी से निकाल दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मद्रास सरकार इस प्रकार बेरोजगारी की समस्या को हल कर सकेगी।

मद्रास राज्य सरकार ने प्रधान मंत्री तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रियों से अनुरोध किया है कि वे उस राज्य का दौरा न करें। इससे यह सिद्ध होता है कि वहां विधि तथा व्यवस्था की स्थिति दिन-प्रति-दिन खराब होती जा रही है। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख होता है कि राज्य की विधि-व्यवस्था बिगड़ रही है।

संसार के सब देशों में यह एक बहुत स्वस्थ परम्परा है कि जब कोई व्यक्ति अध्यक्ष चुना जाता है तो वह दलगत राजनीति में भाग लेना बन्द कर देता है तथा दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर निष्पक्ष रूप से काम करता है। परन्तु यह बड़े खेद की बात है कि मद्रास विधान सभा का वर्तमान अध्यक्ष खुले रूप से दलगत राजनीति में भाग ले रहा है। मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह अध्यक्षों का एक सम्मेलन बुलायें तथा इस परम्परा को स्वस्थ रूप से लागू करने के लिये उचित कार्यवाही करें।

मैं हाल में बम्बई गया था। वहां सैंकड़ों तामिल वासियों ने मुझ से भेंट की। वे लोग शिव सेना की गतिविधियों से आतंकित हैं। मैं सरकार से अनरोध करता हूं कि उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाये। शिव सेना जैसे संगठनों की गतिविधियों से देश को कोई लाभ नहीं होगा। एकता के बिना हम प्रगति नहीं कर सकते।

कल रैलवे बजट पर बोलते हुए द्रविड़ मुनेत्र कषगम के एक माननीय सदस्य ने डालमियापुरम् रेलवे स्टेशन के नाम को बदलने की मांग की थी। मैं कहना चाहता हूं कि यह अधिक अच्छा होता कि वह यह मांग करने से पूर्व इस प्रश्न पर कुछ विचार कर लेते। यह एक सुविदित तथ्य है कि श्री डालमिया एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं। उन्होंने तिरुचिरापल्ली में 17 कारखाने स्थापित किये हैं तथा उन कारखानों में 4,000 से अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं। श्री डालमिया ने अपने कारखानों के श्रमिकों के लिये एक बस्ती बनवाई है जिसका नाम डालमियानगर है। डालमियापुरम् रेलवे स्टेशन इस बस्ती के निकट स्थित है तथा इस स्टेशन का प्रयोग अधिकांशतः डालमियानगर निवासियों द्वारा किया जाता है। अतः यह सुझाव देना कि क्योंकि श्री डालमिया उत्तर भारत निवासी हैं, इसलिये इस स्टेशन का नाम बदल दिया जाये, ठीक नहीं है। द्राविड़ मुनेत्र कषगम पार्टी के कार्यकर्ता यह दावा करते हैं कि उन्होंने उत्तर दक्षिण का भेदभाव तथा पृथकतावादी नीति को छोड़ दिया है। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या द्राविड़ मुनेत्र कषगम के सदस्य का उपरोक्त सुझाव उनके इस दावे के विरुद्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहता हूं कि कोयम्बटूर नगर में 5 पर्यटक बसें आई थीं जिनके नाम भारतीय नदियों के नाम पर गंगा, यमुना, सरस्वती, नरबदा तथा कावेरी रखे गये थे। हुआ क्या कि कावेरी के नाम को छोड़ कर अन्य सब बसों पर से नामों को मिटा दिया गया और यह काम द्राविड़ मुनेत्र कषगम दल के सचिव द्वारा करवाया गया। क्या इस घटना से यह सिद्ध होता है कि उन्होंने पृथकतावादी नीति को छोड़ दिया है।

मद्रास के मुख्य मंत्री श्री अन्नादुरै ने कल घोषणा की थी कि राष्ट्रीय झंडों तथा संविधान की प्रतियों को जलाने की जो घटनायें हुई हैं उनमें द्राविड़ मुनेत्र कषगम दल का कोई हाथ नहीं था और उनके दल ने इस बारे में लोगों को न तो उकसाया ही है और न ही वे उनका समर्थन करते हैं। मैं द्राविड़ मुनेत्र कषगम के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि वे इस बात का निष्ठा से पालन करें।

श्री तेन्नटि विश्वानाथम (विशाखापतनम्) : मैं भाषा विवाद का विस्तारपूर्वक उल्लेख नहीं करना चाहता तथापि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाषा विवाद के कारण इतनी कठिन स्थिति उत्पन्न हो गई है यदि समय रहते इस स्थिति को न सुधारा गया तो वह और भी गंभीर एवं भयंकर रूप धारण कर लेगी। भाषा विवाद के सम्बन्ध में द्राविड़ मुनेत्र कषगम की नीति सबसे उग्रवादी है परन्तु यदि स्थिति को न सुधारा गया तो अन्य राज्यों की नीति भी इतनी ही उग्र हो जायेगी जितनी द्राविड़ मुनेत्र कषगम की है। उदाहरण के तौर पर आन्ध्र प्रदेश विधान सभा द्वारा भाषा के सम्बन्ध में एक संकल्प पारित किया गया है जिसमें संसद् द्वारा पारित किये गये संकल्प में कुछ फेर बदल करने की मांग की गई है। उस संकल्प के अन्त में एक पैरा है कि यदि केन्द्रीय सरकार हमारे सुझावों को नहीं मानती है तो हमें बाध्य हो कर दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि आन्ध्रवासियों की विचारधारा भी द्राविड़ मुनेत्र कषगम जैसी होती जा रही है। यह एक बहुत गम्भीर मामला है। इस समय मैं भाषा के मामले पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहता क्योंकि प्रधान मंत्री ने कुछ समय पूर्व कहा था कि वह भाषा के सम्बन्ध में सब सम्बन्धित व्यक्तियों का एक सम्मेलन बुलायेंगी तथा हिन्दी भाषी व्यक्तियों पर भाषा का अधिक प्रभाव न पड़े इसका यथासंभव प्रयत्न करेंगी।

आयव्ययक के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि जहां कहीं भी हम जाते हैं, लोग आयव्ययक के अतिरिक्त हमसे पूछते हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं देश का भविष्य क्या है? वे संसद् अथवा नई दिल्ली अथवा बंगाल अथवा पंजाब अथवा हरियाणा अथवा किसी अन्य स्थान की किसी घटना का उल्लेख करते हुए हम से प्रश्न करते हैं कि इस देश में क्या हो रहा है? अतः इस समय यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है—आयव्ययक से कहीं अधिक महत्वपूर्ण। मैं उप-प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करें। सरकार का यह कर्तव्य है कि अपने कार्य से वह देशवासियों के मन में यह भावना पैदा करें कि देश का भविष्य अंधकारमय नहीं है, देश में कोई गड़बड़ी नहीं है तथा अपने भविष्य के बारे में हम पूर्णतया आशावादी हैं। पुरानी पीढ़ी का होने के नाते मैं यह कह सकता हूं कि नई पीढ़ी हमारे साथ प्रतियोगिता कर रही है। परन्तु हमें अपनी नई पीढ़ी पर पूरा भरोसा है। हमारे नवयुवक प्रतिभाशाली हैं और उनमें देश को समृद्ध बनाने की क्षमता है। हमें देश की एकता और अखंडता के लिये कार्य करना चाहिये, क्योंकि यह परमावश्यक है। देश की एकत हर कीमत पर कायम रखी जानी चाहिये और हमें इस दशा में काम करना चाहिये।

इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है कि उप-प्रधान मंत्री ने यह वचन दे कर भी कि वह घाटे के बजट के विरुद्ध हैं तथा घाटे का बजट नहीं बनायेंगे उन्होंने घाटे का बजट पेश किया है। परन्तु मैं अनुभव करता हूं कि घाटे का बजट पेश करने के लिये उप-प्रधान मंत्री को दोषी ठहराना

[श्री ते नटि विश्वनाथन]

ठीक नहीं है। वर्तमान स्थिति में और किया भी क्या जा सकता था। वित्त मंत्री खर्च में कमी करने में असमर्थ रहे हैं। विभागों द्वारा धन खर्च करके धन की मांग की जाती है और वित्त मंत्री को उसकी व्यवस्था करनी होती है। अतः वित्त मंत्री इस स्थिति में न होते हुए कि वह विभागों से पूछे कि इतना धन क्यों खर्च किया गया तथा जो धन मांगा जा रहा हो उसे कैसे और क्यों खर्च किया जायेगा, उन्हें वित्त की व्यवस्था करनी होती है। इसलिये वित्त मंत्री के पास घाटे का बजट पेश करने के अतिरिक्त कोई विकल्प न था।

सरकारी ठेकों तथा निर्माण, सिंचाई एवं बिजली जैसे सार्वजनिक कार्यों से सम्बन्धित व्यक्तियों ने मुझे बताया है कि सरकार जितना खर्च करती है उस के 60 प्रतिशत खर्च से भी काम चलाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। परन्तु इस समय मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं जिस से यह स्पष्ट हो जाये कि सरकारी काम किस प्रकार किया जाता है। मुझे एक बार अनन्तपुर के इंजीनियरी कालेज में जाने का अवसर मिला। इस कालेज को विस्तार तथा मरम्मत के लिये कुछ धन की आवश्यकता थी। अतः उस कालेज के प्रिंसिपिल ने जो स्वयं एक इंजीनियर हैं कहा कि योजना तो बहुत बड़ी है जिस पर 20 लाख रुपये खर्च होंगे परन्तु 3 लाख रुपये तो अवश्य मंजूर किये जायें। मैं ने पूछा कि आप तीन लाख रुपया क्यों मांग रहे हैं तब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि अविलम्ब मरम्मत तुरन्त की जायें। इसके पश्चात् तीन लाख रुपये की धनराशि मंजूर की गई। फिर उन्होंने कहा कि तीन लाख रुपये की यह धनराशि लोक निर्माण विभाग को न दे कर उन्हें दी जाये क्योंकि इस तीन लाख रुपये से वह इतना काम करवा सकेंगे जिस के लिये लोकनिर्माण विभाग छः लाख रुपये की राशि की मांग करेगा। इस से स्पष्ट है कि एक इंजीनियर की सार्वजनिक लोक निर्माण विभागों के इंजीनियरों के बारे में क्या राय है। साधायणतया सरकारी परियोजनाओं के कार्यभारक बहुत बड़े अधिकारी होते हैं। अतः अन्त में वह बड़ी नम्र भाषा में और शिष्ट तरीके से प्रधान मंत्री अथवा उप प्रधान मंत्री से प्रार्थना करते हैं कि इस योजना के लिये इतनी धन राशि और मंजूर की जाये अन्यथा 7 करोड़ रुपये की यह योजना बेकार हो जायेगी। इस पर उप प्रधान मंत्री को वह राशि मंजूर करनी पड़ती है और सरकारी खर्च इस प्रकार बढ़ता रहता है। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि सार्वजनिक कार्यों के लागत ढांचे पर विचार करने और यह मालूम करने के लिये कि जितना धन सरकार द्वारा नियत किया जाता है वह सब उन ही कार्यों पर खर्च किया जाता है जिन के लिये नियत किया गया है अथवा नहीं और यदि नहीं तो उस में से कितना धन उन कार्यों पर खर्च किया गया है एक विशेष समिति नियुक्त की जाये। मैं मंत्री महोदय को विश्वास दिलाता हूं कि यदि वह मेरे सूझाव के अनुसार एक समिति का गठन करते हैं को उन्हें इस सत्य का पता चल जायेगा कि सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। साधारणतया लोगों की यह भावना हो गई है कि लोक निर्माण विभाग का अर्थ लोक धन बरबादी विभाग। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों तथा अधिकारियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाये बिना मैं यह कहना चाहता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था के हित में यह आवश्यक है कि ऐसी व्यवस्था की जाये जिस से लोगों को यह विश्वास हो कि सरकारी धन को बर्बाद नहीं किया जा रहा है।

बजट में केवल कुछ ही व्यक्तियों का ध्यान रखा गया है तथा अधिकांश जनता की उपेक्षा की गई है। गांव में जनसाधारण की स्थिति बहुत दयनीय है। यदि आप देहात में जायें तो आप देखेंगे कि वहां लोगों के गाल पिचके हुए हैं और आखें अन्दर को धंसी हुई हैं। यदि आप उन के पोषाहार इत्यादि

की जांच करने के लिये किसी डाक्टर को भेजें तो आप को ज्ञात होगा कि प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले 70 प्रतिशत बच्चों तथा माध्यमिक स्कूलों के 60 प्रतिशत विद्यार्थियों और विश्वविद्यालयों के 40 से 50 प्रतिशत छात्रों को पौष्टिक भोजन नसीब नहीं होता है। वे सब अल्पपोषित हैं। वास्तव में पिछला विश्व युद्ध आरम्भ होने के समय से अब तक हमारे देश के लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल सका है। पिछले 20 वर्षों से हमारे युवकों को भरपेट खाना नहीं मिल पाया है, इसलिये देश में अशांति फैली हुई है। भूखा आदमी हमेशा क्रोधी होता है और यही स्थिति हमारे देश की है। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि वेशभूषा से जो सरकारी कर्मचारी काफी समृद्ध तथा धनी प्रतीत होते हैं वास्तव में कोट-पैन्ट पहनने वाले इन सरकारी कर्मचारियों में से भी अधिकांश की हालत यह है कि उन्हें भर पेट भोजन नहीं मिल पाता है। हम अर्थव्यवस्था की तथा विदेशी सहायता की बात करते हैं परन्तु हमारे निर्धन ग्रामीणों की अभी वही स्थिति है जो पहले थी।

इस बजट का हमारे देश की 80 प्रतिशत जनता के लिये कोई महत्व नहीं है। यह सारा बजट केवल 20 प्रतिशत लोगों के लाभ के लिये पेश किया गया है। मैं वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे निर्धन ग्रामीणों की स्थिति पर विचार करें। अधिकारियों का ध्यान उद्योगपतियों की ओर ही जाता है। उत्पादन शुल्क गरीब आदमी से लिया जाता है। उसे कोई राहत नहीं दी गई है। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस बात की जांच करें कि उत्पादन शुल्क किस नीति के अनुसरण में लगाया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि जिन वस्तुओं का उत्पादन सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है तथा जिन का उपयोग भी सरकार द्वारा किया जाता है उन पर उत्पादन शुल्क क्यों लगाया जाता है? मेरी समझ में यह नहीं आता कि सरकार द्वारा सिक्योरिटी प्रैस में तैयार किये जा रहे कागज पर उत्पादन शुल्क क्यों लगाया जा रहा है? यह सब पुरानी पूंजीपती परम्परा है। सरकार को अपनी सम्पत्ति का लाभ उठाना चाहिये। उसे इस ढंग से लगातार कर नहीं लगाने चाहियें जिन से बाद में उत्पादन लागत में वृद्धि हो। भारतीय खाद्य निगम की भी यही स्थिति है। यदि सरकार असैनिक सप्लाई विभाग के लिये 20 करोड़ रुपया नियत करती है तो उस पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाता परन्तु यदि यही धन राशि खाद्य निगम को जो पूर्णतया एक सरकारी संगठन है दी जाती तो निगम से 7 $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। इस से उपभोक्ता मूल्य बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं होने दिया जाना चाहिये तथा उपभोक्ता मूल्यों को घटाया जाना चाहिये।

देश की सब समस्याओं का समाधान ईमानदारी में है। यदि मुझे 20 ईमानदार मंत्रियों का नेतृत्व करने का अवसर दिया जाये तो मैं समझता हूं कि छः महीने की अवधि में सब समस्यायें हल हो सकती हैं। ऊंचे-ऊंचे पदों पर ईमानदार व्यक्ति होने चाहियें जिससे उनकी ईमानदारी का असर उन के महातहत कर्मचारियों पर भी पड़े। वर्तमान कठिन स्थिति में ईमानदार सरकार का होना बहुत जरूरी है।

श्री राणा (भड़ौंच) : संसार के कुछ देशों में कर दो प्रकार से लगाये जाते हैं। एक तो सर्वसाधारण के उपभोग में आने वाले सामान पर कर लगाया जाता है तथा दूसरे विलासता की वस्तुओं पर कर लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पर इंगलैंड में विलासिता की वस्तुओं पर कर लगाया जाता है और साधारण उपभोग में आने वाली वस्तुओं को उचित राजसहायता दी जाती है। लंदन में यदि आप एक साधारण सूट अथवा जूता खरीदें तो वह बहुत सस्ता मिलेगा क्योंकि उस पर कर नहीं लगाया गया है परन्तु यदि आप कोई कीमती सूट खरीदते हैं तो वह बहुत महंगा मिलेगा क्योंकि

[श्री राणा]

उस पर बहुत अधिक कर लगाया गया है । इसी तरह यदि हम भी विलासिता की वस्तुओं पर कर लगा कर और सर्वसाधारण के काम में आने वाले सामान के लिये राजसहायता दे कर अपने बजट को संतुलित कर सकें तो मुझे पूर्ण विश्वास है हमारी स्थिति सुधर जायेगी । सर्वसाधारण के काम में आने वाले सामान से मेरा अभिप्राय उस सामान से है जो हमारे दैनिक जीवन के लिये आवश्यक है । भोजन, कपड़ा तथा मकान मुहिया करना सरकार का कर्तव्य है अथवा इसके लिये कम से कम राजसहायता तो अवश्य दी जानी चाहिये । यदि हम ऐसा करने में सफल होते हैं तो हम विलासता की वस्तुओं पर बड़ी सफलता से कर लगा सकते हैं ।

दूसरा तरीका यह है कि प्रशासनिक खर्च को कम किया जाये । मैं हमेशा यह कहता रहा हूं कि हमारा प्रशासनिक खर्च बहुत बढ़ गया है । इस खर्च को कम करके और इस प्रकार बची हुई राशि को कृषि तथा सिंचाई जैसे कार्यों में लगाया जाना चाहिये । मैं समझता हूं कि हम इमारतों पर बहुत ज्यादा खर्च करते हैं । उदाहरण के तौर पर एक छोटे से बीज फार्म के लिये जिस का काम एक कच्चे मकान में चलाया जाता है तीस तीस हजार की छः इमारतें बनाई जाती हैं । हमें बड़ी बड़ी इमारतों पर अधिक धन खर्च नहीं करना चाहिये ।

मध्य प्रदेश के एक माननीय सदस्य ने कहा है कि वह नर्मदा का पानी गुजरात में नहीं जाने देंगे । यह एक बहुत गलत दृष्टिकोण है । अन्ततः भारत की सब नदियां सब भारतवासियों की हैं और इन से सब को लाभ होना चाहिये । नर्मदा नदी से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तथा संभवतया कच्छ और राजस्थान में सिंचाई की जा सकती है। नर्मदा परियोजना एक अखिल भारतीय परियोजना है और भारत सरकार को उसे अपने हाथ में लेना चाहिये ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 13 मार्च, 1968/23 फाल्गुन, 1889 (शक) के 11 बजे मध्याह्न पूर्व तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday the 13th March, 1968/23 Phalguna 1889 (Saka).